सशक्त पंचायत सतत् विकास

150 Years of Vande Mataram

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

पुरस्कृत पंचायतों एवं संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ

2025

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

सशक्त पंचायत सतत् विकास

150 Years of Vande Mataram

सत्यमेव जयते

Panchayati Raj

NATIONAL PANCHAYAT AWARDS

BEST PRACTICES OF

AWARDEE PANCHAYATS AND INSTITUTIONS

2025

Ministry of Panchayati Raj
Government of India

परिचय

सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति आज विश्व के सबसे बड़े जनभागीदारी आधारित विकास मॉडलों में से एक के रूप में उभरकर सामने आई है। इस परिवर्तन के केंद्र में पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें तथा 32 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि देशभर में समावेशी शासन, सामुदायिक सहभागिता और सतत् ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। विविधताओं से परिपूर्ण भारत जैसे विशाल देश में पंचायतों के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनकेंद्रित शासन का वैश्विक स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।

इन प्रयासों को मान्यता और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पंचायती राज मंत्रालय प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है। यह दिवस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस ऐतिहासिक संशोधन ने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा प्रदान किया।

सशक्त पंचायत सतत् विकास

विकसित भारत की परिकल्पना तथा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 एजेंडा के अनुरूप, ये पुरस्कार सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (स्थैळे) के नौ विषयों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। इनमें आजीविका संवर्धन, स्वास्थ्य, जल पर्याप्तता, सुशासन, आधारभूत संरचना, पर्यावरणीय सतत्ता तथा महिला नेतृत्व आधारित विकास जैसे विषय शामिल हैं। वर्ष 2025 में पुरस्कार व्यवस्था को पंचायत विकास सूचकांक (पं.वि.सू.) 2.0 से जोड़ा गया, जो सतत् विकास लक्ष्यों से संबद्ध लगभग 150 सूचकांकों पर पंचायतों के प्रदर्शन का साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन ढांचा है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश की उत्कृष्ट पंचायतों और संस्थानों, विशेषकर जिला पंचायत संसाधन केंद्रों, का चयन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 14 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से की गई कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डी.डी.यू.पी.एस.वी.पी.) के अंतर्गत, जो प्रत्येक स्थानीय सतत् विकास लक्ष्य विषय पर उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को सम्मानित करता है, 27 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से 199 विशिष्ट ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हुए 201 नामांकन प्राप्त हुए।

नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एन.डी.एस.पी.एस.वी.पी.) के अंतर्गत पंचायतों को सभी नौ विषयों में समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु मान्यता प्रदान की गई। विस्तृत मूल्यांकन प्रक्रिया के उपरांत, 17 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की 42 पंचायतों को इन श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

वर्ष 2025 में 'आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार' (ए.एन.पी.एस.ए.) की शुरुआत भी की गई, जिसका उद्देश्य पंचायतों में वित्तीय आत्मनिर्भरता, स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ता तथा स्व-स्रोत राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन न्यूट्रैलिटी से संबंधित पूर्ववर्ती पुरस्कारों को समेकित कर 'क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड' (सी.ए.एस.पी.ए.) के अंतर्गत शामिल किया गया। वहीं, 'पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार' (पी.के.एन.एस.एस.पी.) के माध्यम से क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, नवाचार और संस्थागत सहयोग के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने वाले संस्थानों को निरंतर सम्मानित किया गया।

विशेष श्रेणी पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 8 राज्यों की 6 ग्राम पंचायतों और 3 संस्थानों को जलवायु कार्रवाई, स्थानीय आत्मनिर्भरता, जमीनी स्तर के सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए।

यह ई-पुस्तक पुरस्कार विजेता पंचायतों और संस्थानों की प्रेरणादायी यात्राओं तथा परिवर्तनकारी पहलों को प्रस्तुत करती है। यह दर्शाती है कि सशक्त स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ किस प्रकार सतत, समावेशी और आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास को गति प्रदान करते हुए भारत की सतत् विकास लक्ष्यों की यात्रा में सार्थक योगदान दे रही हैं। सफलता के इन अनुकरणीय मॉडलों को प्रस्तुत करते हुए यह प्रकाशन देशभर की पंचायतों एवं हितधारकों को नवाचार, जनभागीदारी और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण हेतु प्रेरित करने का प्रयास करता है।

महिला नेतृत्व की बढ़ती भूमिका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। डी.डी.यू.पी.एस.वी.पी. तथा एन.डी.एस.पी.एस.वी.पी. श्रेणियों के अंतर्गत सम्मानित 22 पंचायतों का नेतृत्व महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। विशेष श्रेणी पुरस्कारों में भी 6 में से 3 पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों का नेतृत्व महिला सरपंचों ने किया। इस प्रकार, कुल 48 पुरस्कार विजेता पंचायतों में से 25 पंचायतों का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में रहा, जो कुल पुरस्कार विजेताओं का 52 प्रतिशत से अधिक है। यह उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व ग्रामीण भारत में समावेशी विकास, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जलवायु अनुकूलता तथा सामुदायिक नेतृत्व आधारित सतत् परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महिला नेतृत्व की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त भूमिका को पुनः स्थापित करता है।

INTRODUCTION

India's progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs) stands among the world's largest examples of grassroots-led development. At the centre of this transformation is the Panchayati Raj system with over 2.5 lakh Gram Panchayats and more than 32 lakh elected representatives driving inclusive governance, community participation, and sustainable rural development across the country. In a vast country of ours with diversity of many factors, the localisation of SDGs through Panchayats represents a globally significant model of democratic decentralisation and people-centric governance.

To recognise and encourage these efforts, the Ministry of Panchayati Raj annually confers the National Panchayat Awards (NPA) on 24th April, celebrated as National Panchayati Raj Day, commemorating the enactment 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, which granted constitutional status to Panchayats as institutions of local self-governance.

Aligned with the vision of Viksit Bharat and the United Nations 2030 Agenda, the awards promote excellence across the nine themes of Localization of SDGs (LSDGs), ranging from livelihoods support, health, and water sufficiency to governance, infrastructure, environmental sustainability, and women-led development. For the year 2025, the awards framework was linked to Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0, an evidence-based framework assessing Panchayat performance across around 150 indicators aligned with SDGs.

National Panchayat Awards 2025 brought together some of India's best-performing Panchayats and Institutions (District Panchayat Resource Centres) through a rigorous evaluation process undertaken by the Ministry in collaboration with 14 Central Ministries and Departments. Under the Deen Dayal Upadhyay Panchayat Satat Vikas Puraskar (DDUPSVP), which recognises outstanding Gram Panchayats across each Localized Sustainable Development Goal (LSDG) theme, 201 nominations representing 199 unique Gram Panchayats were received from 27 States and Union Territories. The Nanaji Deshmukh Sarvottam Panchayat Satat Vikas Puraskar (NDSPSVP) recognised Panchayats for exemplary overall performance across all nine themes. Following a rigorous assessment process, 42 Panchayats across 17 States and Union Territories were conferred awards under these categories.

The year 2025 also marked the introduction of the Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA) to promote fiscal self-reliance, local economic resilience, and enhanced Own Source Revenue mobilisation by Panchayats. In addition, the earlier awards on renewable energy and carbon neutrality were consolidated under the Climate Action Special Panchayat Award (CASPA), while the Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP) continued to recognise institutions making significant contributions towards strengthening Panchayati Raj Institutions through capacity building, training, innovation, and institutional support systems.

Under the Special Category Awards 2025, 6 Gram Panchayats and 3 Institutions across 8 States have been honoured for their exemplary work in climate action, local self-reliance, grassroots governance, and institutional capacity development. The Special Category Awards were conferred by the Hon'ble Prime Minister of India during the National Panchayati Raj Day celebration held on 24th April 2025 at Madhubani, Bihar.

This eBook presents the inspiring journeys and transformative initiatives of these award-winning Panchayats and institutions, showcasing how empowered local governments are advancing sustainable, inclusive, and self-reliant rural development while contributing meaningfully to India's SDGs journey. By showcasing replicable models of success, this publication aspires to inspire, and catalyse further innovation among Panchayats and stakeholders committed to building a sustainable and self-reliant rural India.

Women elected representatives led 22 award-winning Panchayats under the DDUPSVP and NDSPSVP categories. In the Special Category Awards, 3 out of the 6 award-winning Gram Panchayats were headed by women Sarpanches. Overall, women led 25 out of the 48 award-winning Panchayats under the National Panchayat Awards 2025, accounting for over 52 percent of the awardees. This remarkable representation reaffirms the nationally and globally recognised role of women's leadership in advancing inclusive development, democratic decentralisation, climate resilience, and sustainable community-led transformation across rural India.

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्री
और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री
भारत सरकार
Minister of Panchayati Raj and
Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

DO. No.....MIN PR&FAHD/20.....

संदेश

सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में भारत की प्रगति, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जमीनी स्तर पर हुए परिवर्तन की शक्ति को प्रतिबिंबित करती है। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समावेशी एवं सतत् विकास में रूपांतरित किया है।

विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना तथा संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के अनुरूप, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करते हैं तथा पंचायतों को नवाचार, सतत् विकास, सामाजिक न्याय और सहभागी शासन के केंद्र के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये पुरस्कार ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्यों को बढ़ावा देते हैं। मुझे हर्ष है कि स्थानीय शासन में महिलाओं का नेतृत्व निरंतर बढ़ रहा है, जहाँ वर्ष 2025 में 48 पुरस्कार विजेता पंचायतों में से 25 पंचायतों का नेतृत्व महिला प्रतिनिधियों ने किया है। उनकी उपलब्धियाँ सतत् विकास को आगे बढ़ाने तथा स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने में महिलाओं की परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाती है।

मैं 'पुरस्कृत पंचायतों एवं संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ' विषय पर यह ई-पुस्तक प्रकाशित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की सराहना करता हूँ तथा सभी पुरस्कृत पंचायतों एवं संस्थानों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन देशभर की पंचायतों को समावेशी विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करेगा तथा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की भावना को वास्तविक रूप में प्रतिबिंबित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत में योगदान देगा।

(राजीव रंजन सिंह)

Room No. 234, B- Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001 (India)
Ph. +91 11-23380780/81/82 Fax: +91 11- 23380783 Resi. 011-23782781/82

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्री
और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री
भारत सरकार
Minister of Panchayati Raj and
Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

DO. No.....MIN PR&FAHD/20.....

MESSAGE

India's progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs) reflects the strength of grassroots-led transformation through the Panchayati Raj system. More than 2.5 lakh Gram Panchayats have translated national priorities into inclusive and sustainable development.

Aligned with the vision of Viksit Bharat @ 2047 and the United Nations 2030 Agenda, the National Panchayat Awards recognise excellence in the Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs) and encourage Panchayats to emerge as centres of innovation, sustainability, social justice, and participatory governance. The awards promote impactful work across various sectors of rural development. I am heartened by the growing leadership of women in local governance, with women representatives leading 25 of the 48 award-winning Panchayats in 2025. Their achievements reflect the transformative role of women in advancing sustainable development and strengthening local self-governance.

I commend the Ministry of Panchayati Raj for bringing out this e-Book on 'Best Practices of Awardee Panchayats and Institutions' and extend my heartfelt congratulations to all award-winning Panchayats and Institutions. I am confident that this publication will inspire Panchayats across the country towards inclusive development, good governance, and self-reliance, truly reflecting the spirit of "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas" and contribute to the vision of Viksit Bharat envisioned by Hon'ble Prime Minister.

(Rajiv Ranjan Singh)

Room No. 234, B- Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001 (India)
Ph. +91 11-23380780/81/82 Fax: +91 11- 23380783 Resi. 011-23782781/82

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
राज्य मंत्री
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी
एवं
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

Prof. S.P. SINGH BAGHEL
Minister of State for
Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
and
Panchayati Raj
Government of India

संदेश

पंचायतों के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की अवधारणा भारत के उस विशिष्ट विकास मॉडल को प्रतिबिंबित करती है जिसमें ग्रामीण स्थानीय शासन, जनभागीदारी, समावेशन और सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर विकास को गति प्रदान करता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में पंचायतों की उपलब्धियाँ यह सिद्ध करती हैं कि स्थानीय स्वशा. सन संस्थाएँ ग्रामीण नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए वैश्विक विकास प्राथमिकताओं में प्रभावी योगदान दे सकती हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार इन उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हैं तथा पंचायतों को आजीविका, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आधारभूत संरचना, पर्यावरणीय सतत्ता, महिला सशक्तिकरण और सुशासन जैसे प्रमुख विषयों पर निरंतर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्ष 2025 में प्रारंभ एवं सुदृढ़ किए गए विशेष श्रेणी पुरस्कार जलवायु अनुकूलता, वित्तीय आत्मनिर्भरता तथा संस्थागत क्षमता निर्माण के महत्व को भी रेखांकित करते हैं, जो सतत् ग्रामीण परिवर्तन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि पंचायती राज मंत्रालय ने 'पुरस्कृत पंचायतों एवं संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ' विषयक इस ई-पुस्तक के माध्यम से पुरस्कार विजेता पंचायतों की उपलब्धियों का संकलन किया है। मैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के अंतर्गत सम्मानित सभी पंचायतों एवं संस्थानों को सेवा प्रदायगी, नवाचार और जनभागीदारी के प्रेरणादायी मानक स्थापित करने हेतु हार्दिक बधाई देता हूँ।

मुझे विश्वास है कि इस ई-पुस्तक में संकलित अनुभव और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ देशभर की पंचायतों एवं संस्थानों को माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने तथा सशक्त स्थानीय शासन के माध्यम से भारत की सतत् विकास लक्ष्यों की यात्रा को गति प्रदान करने के लिए प्रेरित करेंगी।

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

Office: Room No. 392, 'E' Wing, 3rd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Residence: 7, K. Kamraj Lane, New Delhi
Phone: 011-23782143, 23782548, 23782518, E-mail Id: mos-mopr@gov.in

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
राज्य मंत्री
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी
एवं
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

Prof. S.P. SINGH BAGHEL
Minister of State for
Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
and
Panchayati Raj
Government of India

MESSAGE

The Localisation of Sustainable Development Goals (LSDGs) through Panchayats reflects India's unique approach of rural local government-led developmental model where progress is driven through participation, inclusion, and community ownership. In a country of India's scale and diversity, the achievements of Panchayats demonstrate how local governance institutions can effectively contribute towards global development priorities while addressing the aspirations of rural citizens.

The National Panchayat Awards recognise these outstanding efforts and encourage Panchayats to continuously strive for excellence across key themes such as livelihoods, health, sanitation, infrastructure, environmental sustainability, women empowerment and good governance. The Special Category Awards introduced and strengthened in 2025 further highlight the importance of climate resilience, fiscal self-reliance, and institutional capacity building in achieving sustainable rural transformation.

It is heartening to see that the Ministry of Panchayati Raj has collated the achievements of awardee Panchayats through e-Book on 'Best Practices of awardee Panchayats and Institutions'. I take this opportunity to congratulate all Panchayats and Institutions recognised under National Panchayat Awards 2025 for setting inspiring benchmarks on service delivery, innovation, and public participation.

I hope the experiences and best practices documented in this eBook will motivate Panchayats and Institutions across the country to contribute actively towards the vision of Viksit Bharat of our Hon'ble Prime Minister and accelerate India's progress towards the SDGs through empowered local governance.

(Prof. S.P. Singh Baghel)

Office: Room No. 392, 'E' Wing, 3rd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Residence: 7, K. Kamraj Lane, New Delhi
Phone: 011-23782143, 23782548, 23782518, E-mail Id: mos-mopr@gov.in

विवेक भारद्वाज, भा. प्र. से.
सचिव
Vivek Bharadwaj, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
कृषि भवन, नई दिल्ली -110001
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Dr. Rajendra Prasad Road,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, पंचायती राज मंत्रालय की उस सतत् प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब हैं, जिसके माध्यम से पंचायतों को उत्तरदायी, जवाबदेह और सतत् स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाया जा रहा है। सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की रूपरेखा के अनुरूप ये पुरस्कार ग्रामीण विकास के विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा प्राप्त प्रगति को मान्यता प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को पंचायत विकास सूचकांक 2.0 से जोड़ना जमीनी स्तर पर डेटा-आधारित मूल्यांकन और परिणामोन्मुखी शासन को संस्थागत स्वरूप देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। सतत् विकास लक्ष्यों से संबंधित लगभग 150 संकेतकों पर आधारित यह रूपरेखा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सतत्ता, आधारभूत संरचना, सुशासन, महिला सशक्तिकरण तथा स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन जैसे विविध आयामों का व्यापक मूल्यांकन करती है।

14 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से संपन्न पुरस्कार चयन प्रक्रिया स्थानीय शासन में उत्कृष्टता को मान्यता देने की समग्र एवं एकीकृत कार्यप्रणाली को दर्शाती है। 'आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार' की शुरुआत तथा जलवायु केंद्रित दो पुरस्कारों को समेकित कर 'क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड' के रूप में स्थापित करना, मंत्रालय की सतत्ता और आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है। यह प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के आह्वान के अनुरूप है।

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मंत्रालय ने 'पुरस्कृत पंचायतों एवं संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियाँ' विषयक इस ई-पुस्तक में पुरस्कार विजेता पंचायतों की उपलब्धियों एवं नवाचारपूर्ण पहलों का संकलन किया है। मैं इस ई-पुस्तक में सम्मिलित सभी सम्मानित पंचायतों एवं संस्थानों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि उनकी उपलब्धियाँ अन्य पंचायतों को भी सशक्त स्थानीय स्वशासन, समावेशी एवं सहभागितापूर्ण विकास तथा भारत की सतत् विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धताओं की दिशा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगी।

विवेक भारद्वाज

(विवेक भारद्वाज)

Tel.: 011-23389008, 23074309 Fax : 011-23389028 E-mail : secy-mopr@nic.in

विवेक भारद्वाज, भा. प्र. से.
सचिव
Vivek Bharadwaj, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
कृषि भवन, नई दिल्ली -110001
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Dr. Rajendra Prasad Road,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Message

The National Panchayat Awards reflect the Ministry's continued commitment towards strengthening Panchayats as institutions of responsive, accountable, and sustainable local governance. Aligned with the framework of Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs), the awards recognise measurable progress achieved by Panchayats across critical sectors of rural development.

The linkage of National Panchayat Awards with Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0 marks a major step towards institutionalising data-driven assessment and outcome-based governance at the grassroots level. Covering around 150 indicators aligned with SDGs, the framework captures diverse dimensions including social protection, health, water security, environmental sustainability, infrastructure, governance, women empowerment, and Own Source Revenue mobilisation.

The process of selection of awardees undertaken in collaboration with 14 Central Ministries and Departments reflects a comprehensive and integrated approach towards recognising excellence in local governance. The introduction of 'Atma Nirbhar Panchayat Special Award' and consolidation of two climate-focused awards into the 'Climate Action Special Panchayat Award' further underline the Ministry's focus on sustainability, resilience, and self-reliant rural development in line with the vision of Viksit Bharat, a clarion call given by our Hon'ble Prime Minister.

I am extremely happy to note that the Ministry has compiled the best practices and achievements of the Award-winning Panchayats in this e-Book on 'Best Practices of awardee Panchayats and Institutions'. I take this opportunity to congratulate all award-winning Panchayats and Institutions featured in this e-Book. I hope their achievements will inspire many others towards building empowered Panchayats and contributing meaningfully towards India's SDGs commitments while creating replicable models of inclusive and participatory development.

Vivek Bharadwaj

(Vivek Bharadwaj)

Tel.: 011-23389008, 23074309 Fax : 011-23389028 E-mail : secy-mopr@nic.in

गरीबी मुक्त

एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत

गरीबी मुक्त पंचायत वह है जो सुनिश्चित करे:

- सामाजिक सुरक्षा ताकि कोई भी पुन: गरीबी में न जाए।
- सभी के लिए बेहतर आजीविका के साथ विकास एवं समृद्धि।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- व्यक्तिगत/सामूहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन।
- स्वयं सहायता समूहों एवं किसान समूहों के सदस्यों का 100% बैंक लिंकेज।
- किसानों का केंद्रीय एवं राज्य पोर्टलों पर 100% पंजीकरण।
- आवास, पेयजल एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का 100% पंजीकरण।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को 100% जॉब कार्ड तथा सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों का 100% नामांकन एवं पात्रता आधारित राशन कार्ड सुनिश्चित करना।
- आयुष्मान भारत कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों का 100% कवरेज।
- नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार सेवाओं की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना / मिशन अंत्योदय डेटा के अनुसार वंचित लाभार्थियों की पहचान।
- जॉब कार्ड का प्रभावी वितरण।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना।
- कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास एवं रोजगार के माध्यम से आय सृजन।
- सिंचाई, बेहतर बीज, जैव उर्वरक, नई तकनीकों की पहचान तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के उपयोग से भूमि उत्पादकता में सुधार।
- प्रशिक्षण एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना।
- ग्राम पंचायत विकास योजना निधियों एवं कार्यक्रमों का अभिसरण।

POVERTY FREE AND ENHANCED LIVELIHOODS PANCHAYAT

A POVERTY FREE PANCHAYAT IS ONE WHICH ENSURES:

- Social protection so that none slip back to poverty
- Growth and prosperity with enhanced livelihoods for all

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Economic development & employment generation through individual/collective enterprises
- 100% bank linkages of Self Help Groups (SHGs) and Farmers Group Members associated with Group
- 100% registration of farmers on central and state based portals
- Providing access to basic services such as Housing, Water and Sanitation etc.
- 100% registration of eligible beneficiaries under social security schemes.
- MGNREGS Job cards to 100% eligible applicants and continuous employment to active job card holders under Employment Guarantee Scheme.
- 100% enrolment eligible families under PDS and ensuring entitlement based ration cards.
- 100% coverage of eligible citizens under Ayushman Bharat Card Scheme
- 100% access to services in accordance with the Citizen Charter.

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Beneficiary identification (deprived) as per SECC/MA data
- Effective distribution of job cards
- Facilitating registration in PDS
- Income generation through skill training, entrepreneurship development and employment
- Improvement in land productivity through irrigation, better seeds, bio-fertilizers, identification of appropriate new technologies, use of KVKs
- Strengthening SHGs by handholding training and accessing bank linkages
- Convergence of GPDP funds and programs

गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत

मुद्रादी

ब्लॉक पंचायत: हेबरी
जिला पंचायत: उडुपी
राज्य: कर्नाटक

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 220434
- कुल जनसंख्या: 6,102
- कुल परिवार: 1,671

1st PRIZE

मुख्य उपलब्धियाँ

- 650 महिलाओं को 65 स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर 100% बैंक लिंकेज एवं 100 लाख रुपये के ऋण उपयोग को सुनिश्चित किया।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 28,500 मानव-दिवस सृजित किए तथा 128 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया।
- पात्र लाभार्थियों के लिए पेंशन योजनाओं में 100% संतृप्ति प्राप्त की।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं बसवा वसति योजना के माध्यम से सभी के लिए आवास सुनिश्चित किया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 100% कवरेज प्राप्त किया।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन सुनिश्चित किए।
- किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभ हस्तांतरण प्रणाली पोर्टल पर 100% किसानों का पंजीकरण किया।
- उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे पशु शेड एवं वृक्षारोपण का निर्माण किया।
- वित्तीय समावेशन एवं महिला उद्यमिता को सशक्त बनाया।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ

चुनौतियाँ

- पश्चिमी घाट का दुर्गम भू-भाग, जिससे आधारभूत संरचना एवं सेवा वितरण प्रभावित हुआ।
- युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, जिससे कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी।
- डिजिटल विभाजन के कारण योजनाओं तक पहुंच में कठिनाई।
- रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामग्री भुगतान में देरी।
- ग्रामीण युवाओं में स्वरोजगार योजनाओं के प्रति सीमित जागरूकता।

दृष्टिकोण

- रोजगार गारंटी योजना को आवास एवं आजीविका योजनाओं से जोड़ते हुए अभिसरण मॉडल अपनाया।
- रोजगार दिवस एवं महिला सभाओं के माध्यम से सहभागी योजना निर्माण।
- आधुनिक एवं यंत्रीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा।
- सामाजिक अंकेक्षण एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की।
- स्वयं सहायता समूहों, आशा कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई।
- डिजिटल प्रशासन एवं वित्तीय समावेशन को मजबूत किया।

प्राप्त समर्थन

- केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से वित्तीय सहायता।
- कृषि, पशुपालन एवं बागवानी विभागों से तकनीकी सहयोग।
- बैंकों एवं स्वयं सहायता समूह महासंघों से ऋण सुविधा।
- कृषि सखी, पशु सखी एवं बैंक सखी के माध्यम से क्षमता निर्माण।
- ग्राम सभाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता।

नवाचार

- महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों में अचार, पापड़, नाश्ते एवं जैविक फिनाइल का उत्पादन।
- "हेबरी हनी" मधुमक्खी पालन पहल।
- स्वयं सहायता समूह संचालित कैफे।
- स्वयं सहायता समूह सदस्यों हेतु व्यावसायिक परिसर।
- महिलाओं को "नल जल मित्र" के रूप में जोड़ना।
- सिलाई, सौंदर्य सेवाएं, डेयरी एवं पुष्पकृषि में कौशल विकास।

सतत्ता के लिए रोडमैप

- डिजिटल निगरानी प्रणाली एवं ग्राम सभा समीक्षा को संस्थागत रूप देना।
- स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यमों का विस्तार।
- जलवायु अनुकूल कृषि एवं कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा।
- वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता को मजबूत करना।

Poverty Free and Enhanced Livelihoods Panchayat

MUDRADI

BLOCK PANCHAYAT : HEBRI
DISTRICT PANCHAYAT : UDUPI
STATE: KARNATAKA

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 220434
- Total Population: 6,102
- Total Households: 1,671

1st PRIZE

KEY ACHIEVEMENTS

- Mobilized 650 women into 65 SHGs with 100% bank linkage and credit utilization of 100 lakhs.
- Generated 28,500 person-days under MGNREGS, with 128 households completing 100 days of employment.
- Achieved 100% saturation in pension schemes for eligible beneficiaries.
- Ensured housing for all through PMAY-G and Basava Vasati Yojana.
- Achieved 100% coverage under the Public Distribution System (PDS).
- Ensured 100% Functional Household Tap Connections under Jal Jeevan Mission.
- Registered 100% farmers on the FRUITS portal for Direct Benefit Transfer.
- Created productive assets such as cattle sheds and plantations under MGNREGS.
- Strengthened financial inclusion and women-led entrepreneurship.

Women engaged in SHGs

CHALLENGES FACED

- Rugged terrain of the Western Ghats affecting infrastructure and service delivery.
- Migration of youth to urban areas leading to labour shortages in agriculture.
- Digital divide affecting access to welfare schemes.
- Delays in MGNREGS material payments.
- Limited awareness regarding self-employment schemes among rural youth.

APPROACH TAKEN

- Adopted a Convergence Model integrating MGNREGS with housing and livelihood schemes.
- Conducted Rozgar Diwas and Mahila Sabhas for participatory planning.
- Promoted modern and mechanized agricultural practices.
- Ensured transparency through social audits and public disclosure of beneficiary lists.
- Leveraged SHGs, ASHA workers, and Anganwadi centres for awareness and outreach.
- Strengthened digital governance and financial inclusion initiatives.

SUPPORT RECEIVED

- Financial support from Central and State Government schemes.
- Technical assistance from Agriculture, Veterinary, and Horticulture Departments.
- Credit linkages facilitated by banks and SHG federations.
- Capacity-building support from Krishi Sakhis, Pashu Sakhis, and Bank Sakhis.
- Active community participation through Gram Sabhas and awareness programmes.

INNOVATIONS

- Women-led micro-enterprises producing pickles, papads, snacks, and organic phenol.
- "Hebri Honey" apiculture initiative empowering rural women.
- SHG-run café promoting women entrepreneurship.
- Commercial complex providing shops to SHG members at nominal rent.
- Engagement of women as Nal Jal Mitras for water management.
- Skill development initiatives in tailoring, beauty services, dairy farming, and floriculture.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Institutionalization of digital monitoring systems and Gram Sabha reviews.
- Expansion of SHG-based enterprises through skill enhancement.
- Promotion of climate-resilient agriculture and efficient water management.
- Strengthening financial and digital literacy.
- Innovations
- Women-led micro-enterprises producing pickles, papads, snacks, and organic phenol.
- "Hebri Honey" apiculture initiative empowering rural women.
- SHG-run café promoting women entrepreneurship.
- Commercial complex providing shops to SHG members at nominal rent.
- Engagement of women as Nal Jal Mitras for water management.
- Skill development initiatives in tailoring, beauty services, dairy farming, and floriculture.

गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत

चेम्मुल्लापल्ली

ब्लॉक पंचायत: खाजीपेट मंडल
जिला पंचायत: वाईएसआर कडप्पा
राज्य: आंध्र प्रदेश

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 198377
- कुल जनसंख्या: 2,419
- कुल परिवार: 692

मुख्य उपलब्धियाँ

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 100% खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की।
- पात्र लाभार्थियों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित किया।
- सभी कच्चे मकानों को समाप्त कर 100% पक्का आवास सुनिश्चित किया।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100% रोजगार उपलब्ध कराया।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित किया।
- सभी घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए।
- 244 हेक्टेयर कृषि भूमि में 100% सिंचाई सुनिश्चित की।
- सभी 54 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई।
- बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत किया।

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयाँ एवं हरित दूत

चुनौतियाँ

- छह बिखरी हुई बस्तियों तक योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कृषि पर निर्भरता।
- स्वयं सहायता समूह सदस्यों में उद्यमिता कौशल एवं बाजार अनुभव की कमी।
- आय के स्रोतों में विविधता की आवश्यकता।

दृष्टिकोण

- ग्राम सभा सत्यापन के माध्यम से पारदर्शी लाभार्थी चयन।
- सिंचाई एवं रोजगार गारंटी परिसंपत्तियों के माध्यम से कृषि को सुदृढ़ किया।
- कौशल विकास एवं बाजार संपर्क के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया।
- राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का अभिसरण।
- बैंकों एवं कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।
- पारदर्शिता एवं दक्षता हेतु डिजिटल प्रशासन को अपनाया।

प्राप्त समर्थन

- केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से वित्तीय सहायता।
- विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग।
- बैंकों एवं स्वयं सहायता समूह महासंघों से ऋण सुविधा।
- कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं।
- ग्राम सभाओं के माध्यम से सक्रिय सामुदायिक सहभागिता।

नवाचार

- प्रभावी सेवा वितरण हेतु एकीकृत ग्राम सचिवालय।
- टेलीमेडिसिन सुविधा युक्त ग्राम स्वास्थ्य क्लिनिक।
- कृषि सहायता हेतु किसान सेवा केंद्र।
- जैविक खाद उत्पादन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र।
- अंत:क्रियात्मक वॉयस रिस्पॉन्स प्रणाली आधारित स्वच्छता निगरानी।
- व्हाट्सएप आधारित प्रशासन एवं नागरिक सहभागिता।
- सुलभ बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन।

सतत्ता के लिए रोडमैप

- डिजिटल निगरानी प्रणाली एवं ग्राम सभा समीक्षा को संस्थागत बनाना।
- कौशल उन्नयन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यमों का विस्तार।
- जलवायु अनुकूल कृषि एवं कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा।
- वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता को मजबूत करना।
- समावेशी विकास हेतु सामुदायिक निगरानी को बढ़ावा।

Poverty Free and Enhanced Livelihoods Panchayat

CHEMMULLAPALLI

BLOCK PANCHAYAT : KHAJIPET MANDAL
DISTRICT PANCHAYAT :YSR KADAPA
STATE: ANDHRA PRADESH

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 198377
- Total Population: 2,419
- Total Households: 692

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% food security under the Public Distribution System.
- Ensured universal social security coverage for eligible beneficiaries.
- Attained 100% pucca housing, eliminating all kutcha houses.
- Provided 100% employment under MGNREGS.
- Achieved universal health insurance coverage.
- Ensured universal tap water connections.
- Enabled 100% irrigation across 244 hectares of cultivable land.
- Facilitated bank credit access for all 54 Self-Help Groups.
- Strengthened financial inclusion through banking and digital services.

Solid Wealth Processing Units and Green Ambassador

CHALLENGES FACED

- Ensuring last-mile delivery of welfare schemes across six dispersed habitations.
- Dependence on agriculture vulnerable to climate variability.
- Limited entrepreneurial skills and market exposure for SHG members.
- Need for diversification of income sources for sustainability.

APPROACH TAKEN

- Transparent beneficiary identification through Gram Sabha validation.
- Strengthened agriculture through irrigation and MGNREGS assets.
- Empowered SHGs through skill development and market linkages.
- Convergence of State and Central Government schemes.
- Promotion of financial inclusion via banks and Common Service Centres.
- Adoption of digital governance for transparency and efficiency.

SUPPORT RECEIVED

- Financial assistance from State and Central Government schemes.
- Technical and administrative support from line departments.
- Credit facilitation from banks and SHG federations.
- Digital services through Common Service Centres.
- Active community participation through Gram Sabhas.

INNOVATIONS

- Integrated Village Secretariat for efficient service delivery.
- Telemedicine-enabled Village Health Clinic.
- Rythu Seva Kendralu for agricultural support.
- Solid Waste Processing Centre producing organic compost.
- IVRS-based sanitation monitoring system.
- WhatsApp-based governance for citizen engagement and transparency.
- Strengthened financial inclusion through accessible banking services.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Institutionalization of digital monitoring systems and Gram Sabha reviews.
- Expansion of SHG-based enterprises through skill enhancement.
- Promotion of climate-resilient agriculture and efficient water management.
- Strengthening financial and digital literacy.
- Community-led monitoring for inclusive growth.

गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत

ग्यालशिंग ओमचुंग

जिला: ग्यालशिंग
राज्य: सिक्किम

3rd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 254739
- कुल जनसंख्या: 3,050
- कुल परिवार: 623

मुख्य उपलब्धियाँ

- आय सृजन हेतु मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण एवं मधुमक्खी बक्सों का वितरण।
- 120 से अधिक युवाओं एवं महिलाओं को बांस शिल्प एवं हथकरघा प्रशिक्षण।
- अंत्योदय अन्न योजना, प्राथमिक परिवार श्रेणी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से 95% गरीब परिवारों की पहचान एवं सहायता।
- किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण एवं सूक्ष्म उद्यम सहायता।
- 338 परिवारों को रोजगार गारंटी एवं अन्य आजीविका कार्यक्रमों से जोड़ा।
- बोर्ड परीक्षा छात्रों हेतु नि:शुल्क कोचिंग एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

मनरेगा के अंतर्गत नागरिकों का पंजीकरण

चुनौतियाँ

- भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सीमित रोजगार अवसर।
- अनिश्चित मौसम एवं छोटी जोतों के कारण कृषि उत्पादकता में कमी।
- अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं एवं कमजोर डिजिटल कनेक्टिविटी।
- ऋण एवं वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच।
- दूरस्थ क्षेत्रों में खराब सड़क एवं आधारभूत संरचना।
- पारंपरिक सोच एवं जागरूकता की कमी।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पात्र लाभार्थियों के नामांकन में कठिनाई।

दृष्टिकोण

- रोजगार एवं उद्यमिता हेतु कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए।
- आधुनिक कृषि उपकरण वितरित कर कृषि को बढ़ावा दिया।
- स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए तथा आशा कार्यकर्ताओं को मेडिकल किट उपलब्ध कराई।
- बैंकों के सहयोग से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए।
- इंटरनेट एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों सहित आधारभूत संरचना को मजबूत किया।
- जागरूकता अभियान एवं ग्राम सभा सहभागिता के माध्यम से आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दिया।
- केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित किया।

प्राप्त समर्थन

- केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग।
- बैंकों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन टीमों एवं विभागों का सहयोग।
- महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी।
- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जागरूकता एवं सामुदायिक सहयोग।
- पंद्रहवें वित्त आयोग एवं पाँचवें राज्य वित्त आयोग से वित्तीय सहायता।

नवाचार

- मधुमक्खी पालन एवं बांस आधारित आजीविका को बढ़ावा।
- बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से अभिसरण आधारित गरीबी उन्मूलन।
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं वित्तीय समावेशन पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं एवं महिलाओं का क्षमता निर्माण।
- सहभागी योजना एवं समावेशी निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन को सुदृढ़ करना।

सततता के लिए रोडमैप

- शिक्षा एवं क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना।
- डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल वित्त में उन्नत कौशल प्रशिक्षण।
- विपणन सहायता एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यमों को बढ़ावा।
- मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा।
- नशा एवं शराब दुरुपयोग रोकथाम अभियान।
- सतत आजीविका एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन।
- सहभागी शासन एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से निरंतर निगरानी।

Poverty Free and Enhanced Livelihoods Panchayat

GYALSHING OMCHUNG

DISTRICT: GYALSHING
STATE: SIKKIM

3rd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 254739
- Total Population: 3,050
- Total Households: 623

KEY ACHIEVEMENTS

- Provided apiculture training and distributed beehives to promote income generation.
- Organized bamboo craftsmanship and handloom training for over 120 youth and women.
- Ensured identification and support to 95% of poor households through schemes such as AAY, PHH, PM-JAY, Old Age Pension, SGAY, and GCI Sheets.
- Facilitated access to subsidized loans and micro-enterprises under schemes like KCC, PMEGP, and MUDRA.
- Linked 338 households with MGNREGA and other livelihood programmes.
- Promoted education by providing free coaching for board examination students and organizing inter-school quiz competitions.

Enrollment of citizen under MGNREGS

CHALLENGES FACED

- Limited employment opportunities due to geographical constraints.
- Low agricultural productivity caused by unpredictable weather, small landholdings, and human-wildlife conflict.
- Inadequate healthcare facilities and weak digital connectivity.
- Limited access to credit and financial services.
- Poor road connectivity and infrastructure in remote areas.
- Difficulty in motivating villagers due to traditional mindsets and lack of awareness.
- Challenges in enrolling eligible beneficiaries under social security schemes.

APPROACH TAKEN

- Organized skill development programmes to generate employment and entrepreneurship.
- Promoted modern agricultural practices by distributing tools such as tillers and grass cutters.
- Conducted health camps and provided medical kits to ASHA workers, with special attention to children and senior citizens.
- Facilitated financial literacy camps in collaboration with banks to improve access to credit.
- Strengthened infrastructure, including internet connectivity and community assets.
- Encouraged participation in income-generating activities through awareness drives and Gram Sabha engagement.
- Ensured convergence of Central and State Government schemes for holistic development.

SUPPORT RECEIVED

- Financial and technical support from Central and State Government Departments.
- Assistance from banks, SRLM teams, and line departments for livelihood promotion and financial inclusion.
- Active participation of Self-Help Groups (SHGs) in women's empowerment and economic development.
- Support from Non-Governmental Organizations (NGOs) in awareness generation and community mobilization.
- Funding through the 15th Finance Commission (Central) and the 5th State Finance Commission.

INNOVATIONS

- Promotion of apiculture and bamboo-based livelihoods for sustainable income generation.
- Convergence-driven poverty alleviation through multi-sectoral interventions.
- Community-led awareness programmes on education, health, and financial inclusion.
- Capacity-building of youth and women through vocational training.
- Strengthening grassroots governance through participatory planning and inclusive decision-making.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthening education and capacity-building initiatives for long-term development.
- Providing advanced skill training in emerging sectors such as data analysis, artificial intelligence, and digital finance.
- Enhancing SHG-based enterprises through marketing support and value addition.
- Promoting mental health awareness and social well-being.
- Organizing campaigns to prevent alcohol and drug abuse.
- Encouraging sustainable livelihood opportunities and entrepreneurship.
- Ensuring continuous monitoring through participatory governance and Gram Sabhas.

स्वस्थ पंचायत

स्वस्थ पंचायत वह है जो सुनिश्चित करे:

- सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण।
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं।
- सभी का टीकाकरण।
- उचित एवं सुलभ दरों पर दवाओं की उपलब्धता।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- अवरुद्ध वृद्धि एवं कुपोषण का उन्मूलन।
- किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया का उन्मूलन।
- कम लागत वाले, अत्यधिक पौष्टिक एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, सब्जियां, फल, अंडे आदि की उपलब्धता।
- संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं उपचारात्मक उपाय।
- मातृ मृत्यु एवं पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को शून्य करना।
- सभी के लिए चिकित्सा देखभाल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता।
- खुले में शौच मुक्त प्लस स्थिति प्राप्त करना।

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना (पोषण, परामर्श, सेनेटरी नैपकिन का उपयोग एवं सुरक्षित निपटान आदि)।
- माताओं एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करना।
- संक्रामक रोगों (एनीमिया, तपेदिक, एचआईवी आदि) तथा असंक्रामक/जीवनशैली संबंधी रोगों (मधुमेह, कैंसर आदि) की रोकथाम एवं उपचार को बढ़ावा देना।
- विवाह एवं गर्भधारण की उचित आयु, मानसिक स्वास्थ्य एवं दिव्यांगता के प्रति जागरूकता।
- वृद्धजन देखभाल सहायता।
- आयुष पद्धतियों को बढ़ावा एवं उनका उपयोग।

HEALTHY PANCHAYAT

A POVERTY FREE PANCHAYAT IS ONE WHICH ENSURES:

- Good health and well-being for all at all ages
- Quality health services
- Vaccination of all
- Availability of medicines at reasonable and affordable prices

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Eliminate stunting and wasting
- Eliminate anaemia amongst adolescent girls and women
- Low cost, highly nutritious and locally procured cereals, vegetables, fruits, eggs etc.
- Preventive and curative measures for communicable diseases
- Zero maternal deaths, child deaths under 5 years
- Provision for medical care and health facilities for all
- Achieving Open Defecation Free+ stat
- us

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Ensuring children and mothers health (Nutrition, counselling, use & safe disposal of sanitary napkins etc.)
- Facilitating full immunization of mothers and children
- Prevention and facilitating treatment of communicable diseases (Anaemia, TB, HIV etc.) and non-communicable diseases/ life style diseases (diabetes, cancer etc.)
- Awareness on marriage and pregnancy age, mental health and disabilities
- Old-age care support
- Promotion and use of AYUSH

स्वस्थ
पंचायत

कंचनबाड़ी

ब्लॉक पंचायत: कुमारघाट ग्रामीण विकास ब्लॉक
जिला पंचायत: उनाकोटी
राज्य: त्रिपुरा

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 104033
- कुल जनसंख्या: 2,581
- कुल परिवार: 717

मुख्य उपलब्धियाँ

- 24×7 एम्बुलेंस सुविधा सहित पूर्णत: कार्यरत 20-बेड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।
- नियमित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस का आयोजन।
- 100% संस्थागत प्रसव तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर शून्य।
- तपेदिक मुक्त पंचायत का दर्जा प्राप्त तथा उच्च टीकाकरण कवरेज बनाए रखा।
- सामाजिक पेंशन योजनाओं के माध्यम से 137 व्यक्तियों को लाभ।
- 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में एनीमिया एवं अवरुद्ध वृद्धि के कोई मामले नहीं।
- आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत 100% कवरेज।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- सभी परिवारों को बिजली, एलपीजी एवं नल जल कनेक्शन उपलब्ध।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थापना।
- असंक्रामक रोग एवं मोतियाबिंद शिविर सहित नियमित स्वास्थ्य जांच।

स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता अभियान एवं टीबी मुक्त पंचायत पुरस्कार

चुनौतियाँ

- अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में कठिनाई।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की अनियमित बैठकें।
- ग्रामीणों में असंक्रामक रोगों एवं तपेदिक के प्रति कम जागरूकता।
- स्वास्थ्य योजनाओं के अपूर्ण कवरेज की समस्या।
- अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामुदायिक भागीदारी की सततता सुनिश्चित करना।

दृष्टिकोण

- स्वास्थ्य, एकीकृत बाल विकास सेवा, स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य योजनाओं का अभिसरण आधारित दृष्टिकोण अपनाया।
- आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य सखियों द्वारा घर-घर संपर्क अभियान।
- तपेदिक उन्मूलन, असंक्रामक रोग जांच एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान।
- स्वच्छता, अपशिष्ट पृथक्करण एवं स्वस्थ जीवनशैली पर व्यवहार परिवर्तन अभियान।
- सरकारी स्वास्थ्य एवं बीमा योजनाओं के अंतर्गत 100% परिवार कवरेज।
- स्वास्थ्य सखियों एवं स्वास्थ्य क्लबों के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया।
- ओपन जिम, सुरक्षित पेयजल एटीएम एवं जैविक खेती जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास।
- अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खेती एवं वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा।

प्राप्त समर्थन

- जल जीवन मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वास्थ्य योजनाओं से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।
- आधारभूत संरचना एवं स्वास्थ्य गतिविधियों हेतु विभागीय सहयोग।
- डिजिटल स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- स्वयं सहायता समूहों एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता।

नवाचार

- अपशिष्ट पृथक्करण एवं वर्मी कम्पोस्टिंग सहित पूर्ण स्वच्छता कवरेज।
- सभी सार्वजनिक एवं घरेलू भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं।
- स्वच्छ ईंधन हेतु एलपीजी एवं जैविक खेती को बढ़ावा।
- स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य क्लब एवं मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों सहित डिजिटल स्वास्थ्य पहल।
- जागरूकता अभियान एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता।

सतत्ता के लिए रोडमैप

- नियमित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, असंक्रामक रोग जांच एवं टीकाकरण अभियान जारी रखना।
- जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का रखरखाव एवं उन्नयन।
- आपदा न्यूनीकरण हेतु जैविक सुरक्षा पट्टी एवं वृक्षारोपण का विस्तार।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता परिसंपत्तियों में सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करना।
- डिजिटल निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र को संस्थागत रूप देना।
- नवीकरणीय ऊर्जा, वर्षा जल संचयन एवं सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

Healthy Panchayat

KANCHANBARI

BLOCK PANCHAYAT KUMARGHAT RD BLOCK
DISTRICT PANCHAYAT UNAKOTI
TRIPURA

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 104033
- Total Population: 2,581
- Total Households: 717

KEY ACHIEVEMENTS

- Fully functional 20-bed Primary Health Centre (PHC) with 24×7 ambulance support.
- Conducts regular Village Health and Sanitation Days (VHSD).
- Achieved 100% institutional deliveries, with zero maternal and child mortality.
- Achieved TB-Mukt Panchayat status and maintained high immunization coverage.
- Benefited 137 individuals through social pension schemes.
- No reported cases of anemia or stunted growth among children aged 0-5 years.
- Ensured 100% coverage of health insurance schemes (e.g., Ayushman Bharat).
- Implemented solid and liquid waste management programs, including composting and waste segregation.
- Provided reliable electric, LPG, and tap water connections to all households.
- Established PDS (Public Distribution System) and water supply projects.
- Conducted regular health screening, including NCD and cataract camps.

Health Checkups, Cleanliness Drive and TB Mukt Panchayat Award

CHALLENGES FACED

- Last-mile healthcare delivery issues related to follow-up and emergency response.
- Irregular meetings of Village Health and Sanitation Committees.
- Low awareness of NCD, TB, and other health issues among villagers.
- Incomplete coverage of schemes like AB-PMJAY.
- Sustainability concerns related to waste management and community participation.

APPROACH TAKEN

- Adopted an integrated convergence approach aligning health, ICDS, SBM, TRLM, and other schemes.
- Conducted regular VHNDs and door-to-door outreach by ASHA, AWWs, and Swasthya Sakhis.
- Focused on preventive healthcare, including TB elimination, NCD screening, and maternal-child health.
- Promoted behavior change campaigns on sanitation, waste segregation, and healthy lifestyles.
- Ensured 100% household coverage under government health schemes and insurance.
- Strengthened community health services through Swasthya Sakhis and health clubs.
- Developed community infrastructure like open gyms, safe drinking water ATMs, and organic farming initiatives.
- Promoted environmental health through waste management, organic farming, and plantation drives.

SUPPORT RECEIVED

- Financial and technical aid from schemes like Jal Jeevan Mission, MGNREGA, Swachh Bharat Mission, XV Finance Commission grants, and health schemes like PMJAY.
- Assistance from government departments for infrastructure and health activities.
- Capacity-building programs for digital health, disaster preparedness, and water management.
- Community participation through SHGs, awareness campaigns, and local leadership.

INNOVATIONS

- Complete sanitation coverage with waste segregation and vermi-composting.
- Rainwater harvesting structures in all public and household buildings.
- Use of LPG for clean cooking and promotion of organic farming.
- Digital health initiatives, including health camps, health clubs, and mobile health units.
- Community engagement through awareness campaigns, health clubs, and SHGs.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Continue routine VHNDs, NCD screening, and immunization drives.
- Maintain and upgrade water supply, sanitation, and waste management systems.
- Expand eco-sensitive plantations and bio-shields for disaster mitigation.
- Strengthen community participation and ownership of health and sanitation assets.
- Institutionalize digital monitoring, grievance redressal, and transparency mechanisms.
- Promote renewable energy, rainwater harvesting, and sustainable farming practices.

स्वस्थ पंचायत

वंदसे

ब्लॉक पंचायत: कुंडापुरा
जिला पंचायत: उडुपी
राज्य: कर्नाटक

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 220500
- कुल जनसंख्या: 2,957
- कुल परिवार: 752

मुख्य उपलब्धियाँ

- 100% संस्थागत प्रसव एवं पूर्ण टीकाकरण कवरेज, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर शून्य रही।
- दीर्घकालिक रोगियों, वृद्धजनों एवं मानसिक रूप से विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक उपशामक देखभाल व्यवस्था स्थापित की।
- राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत "तपेदिक मुक्त पंचायत" घोषित।
- आयुष्मान भारत-आरोग्य कर्नाटक योजना के अंतर्गत 100% स्वास्थ्य कार्ड वितरण।
- आंगनवाड़ी निगरानी एवं पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषण मुक्त स्थिति प्राप्त की।
- वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं जैव गैस इकाइयों सहित खुले में शौच मुक्त प्लस प्रमाणन बनाए रखा।
- नियमित योग सत्र, एनीमिया जांच एवं स्वास्थ्य अभियानों से निवारक स्वास्थ्य संस्कृति को बढ़ावा।

विद्यालयी बालिकाओं की हीमोग्लोबिन जांच

चुनौतियाँ

- पहाड़ी एवं तटीय क्षेत्र होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं एवं अपशिष्ट प्रबंधन में कठिनाई।
- वृद्धावस्था एवं दीर्घकालिक रोगों का अधिक भार।
- 100% अपशिष्ट पृथक्करण एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य पंजीकरण हेतु निरंतर जागरूकता की आवश्यकता।
- सामुदायिक उपशामक देखभाल ट्रस्ट की वित्तीय सततता बनाए रखना।

दृष्टिकोण

- चिकित्सकों, नर्सों एवं स्वास्थ्य सहायकों की मोबाइल टीमों द्वारा घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं।
- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा मासिक समीक्षा।
- शिकायत निवारण हेतु "निरामय हेल्पलाइन" की स्थापना।
- गर्भवती महिलाओं, तपेदिक पहचान एवं असंक्रामक रोग जांच हेतु घर-घर स्वास्थ्य जांच।
- आशा कार्यकर्ताओं द्वारा उच्च जोखिम गर्भावस्था एवं एनीमिया मामलों की निगरानी।

प्राप्त समर्थन

- जिला पंचायत उडुपी एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वय एवं समीक्षा।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप-केंद्रों से निरंतर चिकित्सा सहायता।
- मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी एवं कस्तूरबा अस्पताल से तकनीकी प्रशिक्षण।
- स्थानीय दानदाताओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से सहयोग।

नवाचार

- सात पंचायतों में 307 रोगियों को घर-आधारित उपशामक स्वास्थ्य सेवाएं।
- निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा एवं शव संरक्षण इकाई की स्थापना।
- जैविक अपशिष्ट को कम्पोस्ट में बदलने वाली मॉडल इकाई।
- पोषण अभियान, एनीमिया जांच एवं सामुदायिक योग कार्यक्रम।
- डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं हेल्पलाइन आधारित सेवाएं।

सततता के लिए रोडमैप

- सामुदायिक उपशामक देखभाल मॉडल का अन्य पंचायतों तक विस्तार।
- स्वास्थ्य संवर्धन हेतु योग एवं वेलनेस पार्क का विकास।
- वृद्धजनों एवं दीर्घकालिक रोगियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना।
- अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण।
- किशोरियों में एनीमिया शून्य करने का लक्ष्य।

Healthy Panchayat

VANDSE

BLOCK PANCHAYAT: KUNDAPURA
DISTRICT PANCHAYAT: UDUPI
STATE: KARNATAKA

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 220500
- Total Population: 2,957
- Total Households: 752

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% institutional deliveries and full immunization coverage, resulting in zero maternal and infant mortality.
- Established a community-owned, multi-Panchayat trust providing home-based palliative, rehabilitative, and psychosocial care for chronically ill, bedridden, elderly, and mentally challenged individuals.
- Declared a "TB-Free Panchayat" under the National TB Elimination Programme and maintains robust vector-borne disease mitigation for malaria and dengue.
- Attained 100% health card distribution under Ayushman Bharat–Arogya Karnataka (AB-ArK), ensuring access to quality healthcare for all eligible families
- Maintained a "Malnutrition Free" status with Zero SAM/MAM children through Anganwadi monitoring, Nutri-gardens, and community nutrition programs.
- Sustained ODF+ certification with scientific waste processing, featuring Black Soldier Fly Composting, Bio-gas (Gobar Dhan) Unit, and segregated wet-dry waste management at a multi-GP SLRM Unit.
- Regular community yoga sessions, anaemia screening programmes, and wellness drives have strengthened preventive and holistic health culture.

Haemoglobin ascertaining among school girls

CHALLENGES FACED

- The hilly and coastal terrain made accessibility to specialized healthcare and waste management logistics difficult.
- A high burden of age-related illnesses and chronic conditions required long-term community engagement.
- Shift to 100% waste segregation and universal health registration demanded continuous awareness and local mobilization.
- Establishing and sustaining the Niramaya Palliative Care Trust without over-reliance on government funding posed early challenges.

APPROACH TAKEN

- A registered Niramaya Trust was formed, deploying mobile medical teams comprising doctors, nurses, physiotherapists, and health assistants for home visits.
- The Village Health Sanitation and Nutrition Committee conducts monthly reviews on health indicators and ensures participatory monitoring.
- A "Niramaya Helpline" was established for grievance redressal and patient support.
- Organized door-to-door health screenings and camps for pregnant women, TB detection, NCD assessment, and Ayushman card drives.
- ASHA workers track high-risk pregnancies, immunization, and anaemia cases through performance-based incentives.

SUPPORT RECEIVED

- The Zilla Panchayat Udupi and its CEO led review mechanisms and interdepartmental coordination.
- The District Health Department, PHC Vandse, and Sub-centres provided continuous medical and logistical assistance.
- Collaboration with Manipal Academy of Higher Education (MAHE) and Kasturba Hospital brought specialized training for community palliative care.
- Local donors, NGOs, and CSR funds contributed generously to the financial sustainability of the Niramaya model.

INNOVATIONS

- Provided doorstep tertiary and palliative healthcare to 307 patients across seven Panchayats, ensuring humane care for bedridden, elderly, and terminally ill individuals.
- Introduction of free ambulance service and a dead body freezer unit for economically weaker households — a rare and compassionate community adaptation.
- Model unit under the Multi-GP SLRM Cluster transforming organic waste into compost, generating monthly revenues of ₹20,000–₹25,000.
- Periodic Poshan Abhiyan baby showers, health check camps, anaemia detection drives, and community yoga events reinforce public health awareness and engagement.
- Use of digital health records, PHC dashboards, and helplines (181/1098/1090) for responsive health and social services.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Plans to scale up the community palliative care trust to nearby Gram Panchayats, forming a district-level chronic care network.
- Development of a Yoga & Wellness Park under the 15th Finance Commission funds for ongoing health promotion.
- Building a digital database of elderly and chronic care patients for proactive case tracking.
- Continuous reinforcement of SLRM protocols, IEC campaigns, and training of Self-Help Groups for waste management.
- Targeting Zero Anaemia among adolescent girls by 2026 through periodic haemoglobin testing and nutrition interventions.

स्वस्थ
पंचायत

निरणम

ब्लॉक पंचायत: पुलिकीज्हु
जिला पंचायत: पथानामथिट्टा
राज्य: केरल

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 221740
- कुल जनसंख्या: 13,445
- कुल परिवार: 2,837

3rd PRIZE

तृतीय पुरस्कार - संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- सभी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पूर्णत: कार्यरत हैं तथा उनमें पृथक शौचालय, बिजली एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- इंटरनेट, कंप्यूटर एवं ऑनलाइन सेवा मंचों सहित पूर्णत: कार्यशील कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई।
- घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों के माध्यम से 100% खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखी गई।
- अपशिष्ट पृथक्करण एवं कम्पोस्टिंग सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की गई।
- टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य, तपेदिक उन्मूलन एवं स्वास्थ्य जांच जैसी नियमित स्वास्थ्य एवं पोषण गतिविधियां संचालित की गईं।
- खेल मैदान, सामुदायिक भवन, वर्षा जल संचयन एवं जैविक सुरक्षा पट्टी जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं रखरखाव किया गया।
- पंचायत में ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गईं।
- ग्राम सभा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया गया।

योग का आयोजन

चुनौतियाँ

- जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- जल जीवन मिशन प्रमाणन जैसी दस्तावेजी एवं प्रमाणन संबंधी कमियां।
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की सामुदायिक भागीदारी एवं सततता बनाए रखना।
- सीमित संसाधनों के साथ बाढ़ प्रभावित निम्न क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का प्रबंधन।

दृष्टिकोण

- ग्राम सभा एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सहभागी योजना निर्माण।
- समेकित आधारभूत संरचना विकास हेतु केंद्र एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण।
- अपशिष्ट पृथक्करण, स्वच्छता, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा।
- पारदर्शिता एवं नागरिक सहभागिता हेतु कॉमन सर्विस सेंटर, क्यूआर कोड एवं व्हाट्सएप समूहों का उपयोग।
- आपदा सहनशीलता हेतु जैविक सुरक्षा पट्टी, पर्यावरण अनुकूल वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा।
- आधारभूत परिसंपत्तियों के नियमित रखरखाव एवं सामुदायिक स्वामित्व को सुनिश्चित किया गया।

प्राप्त समर्थन

- केरल राज्य सरकार एवं जल जीवन मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा स्वास्थ्य योजनाओं से सहयोग।
- सरकारी विभागों एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदारों से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता।
- डिजिटल प्रशासन, जल प्रबंधन एवं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- स्वयं सहायता समूहों, ग्राम सभा एवं स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से सक्रिय सामुदायिक सहभागिता।

नवाचार

- अपशिष्ट पृथक्करण, कम्पोस्टिंग एवं प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण के साथ 100% खुले में शौच मुक्त स्थिति।
- चक्रवात एवं खारे पानी के प्रभाव को कम करने हेतु वृक्षारोपण एवं जैविक सुरक्षा पट्टी विकास।
- सभी सार्वजनिक एवं घरेलू भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं।
- ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग एवं पर्यावरण अनुकूल विकास पहल।
- वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सामुदायिक सहभागिता।
- क्यूआर कोड, व्हाट्सएप समूह एवं कॉमन सर्विस सेंटर आधारित डिजिटल प्रशासन।

सतत्ता के लिए रोडमैप

- जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सड़क आधारभूत संरचना का नियमित रखरखाव एवं उन्नयन।
- पर्यावरण अनुकूल वृक्षारोपण, जैविक सुरक्षा पट्टी एवं वर्षा जल संचयन का विस्तार।
- सामुदायिक स्वामित्व एवं निरंतर जागरूकता अभियानों को बढ़ावा।
- डिजिटल निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र को संस्थागत रूप देना।
- ईको-टूरिज्म, सूक्ष्म उद्यम एवं सतत कृषि के माध्यम से आय के स्रोतों में विविधता।
- आपदा तैयारी एवं सामुदायिक सहनशीलता गतिविधियों को मजबूत करना।

Healthy Panchayat

NIRANAM

BLOCK PANCHAYAT: PULIKEEZHU
DISTRICT PANCHAYAT: PATHANAMTHITTA
KERALA

3rd PRIZE

Third Prize- Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 221740
- Total Population: 13,445
- Total Households: 2,837

KEY ACHIEVEMENTS

- All 11 Community Health Centres (CHC) and Health & Wellness Centres (HWCs) are functional, equipped with basic facilities, including separate toilets, electricity, and drinking water.
- Achieved 100% coverage of households with safe drinking water under Jal Jeevan Mission (Har Ghar Jal).
- Established a fully operational Common Service Centre (CSC) with internet, computers, and online service platforms, promoting digital governance.
- Maintained 100% open defecation free (ODF) status with household toilets and public sanitation facilities.
- Implemented effective solid and liquid waste management systems, including waste segregation and composting.
- Conducted regular health and nutrition activities, including immunizations, maternal health, TB elimination, and health screening.
- Developed and maintained infrastructure such as playgrounds, burial grounds, community halls, rainwater harvesting, and bio-shield plantations.
- Installed energy-efficient LED street lights throughout the Panchayat.
- Promoted community participation through Gram Sabha, Health & Sanitation Committees, and awareness campaigns.

Conduct of Yoga

CHALLENGES FACED

- Ensuring last-mile access to water, sanitation, and health services.
- Documentation and certification gaps, such as Jal Jeevan certification pending.
- Maintaining community participation and sustainability of waste management systems.
- Managing infrastructure in dispersed low-lying flood-prone areas with limited resources.

APPROACH TAKEN

- Conducted participatory planning through Gram Sabha and community engagement.
- Converged schemes from central and state governments for integrated infrastructure development.
- Promoted community involvement in waste segregation, sanitation, plantation, and water conservation.
- Leveraged digital platforms such as CSC, QR codes, WhatsApp groups for transparency, monitoring, and citizen engagement.
- Implemented eco-sensitive plantation, bio-shield development, and rainwater harvesting for disaster resilience.
- Ensured routine maintenance, asset management, and community ownership of infrastructure assets.

SUPPORT RECEIVED

- Support from Kerala State Government, Central schemes like Jal Jeevan Mission, MGNREGA, Swachh Bharat Mission, XV Finance Commission grants, and health schemes such as AB-PMJAY.
- Technical and financial assistance from government departments and CSR partners.
- Capacity-building programs for digital governance, water management, and waste processing.
- Active community participation via SHGs, Gram Sabha, and local leadership.

INNOVATIONS

- Achieved 100% ODF status with waste segregation, composting, and plastic waste recycling.
- Plantation drives and bio-shield development for cyclone and saltwater intrusion mitigation.
- Rainwater harvesting infrastructure in all public and household buildings.
- Use of energy-efficient LED street lighting and eco-sensitive development initiatives.
- Community-led plantation, sanitation, and disaster risk reduction activities.
- Digital governance via QR codes, WhatsApp groups, and CSC services.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Regular maintenance and upgradation of water, sanitation, health, and road infrastructure.
- Expansion of eco-sensitive plantation, bio-shield development, and rainwater harvesting.
- Promote community ownership and continuous awareness campaigns.
- Institutionalize digital monitoring, grievance redressal, and transparency mechanisms.
- Diversify income sources through eco-tourism, micro-enterprises, and sustainable agriculture.
- Strengthen disaster preparedness and community resilience activities.

स्वस्थ
पंचायत

पोटलमपुर

ब्लॉक पंचायत: छत्रपुर
जिला पंचायत: गंजम
राज्य: ओडिशा

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 117687
- कुल जनसंख्या: 9,639
- कुल परिवार: 1,913

3rd PRIZE

तृतीय पुरस्कार - संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- सभी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उप-केंद्र पूर्णत: कार्यरत हैं तथा उनमें पृथक शौचालय, बिजली एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- इंटरनेट, कंप्यूटर एवं ऑनलाइन सेवा सुविधाओं सहित पूर्णत: कार्यशील कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किया गया।
- पंचायत की सभी आंतरिक सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव सुनिश्चित किया गया तथा उन्हें मुख्य सड़कों से जोड़ा गया।
- घरेलू एवं सार्वजनिक शौचालयों सहित 100% खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखी गई।
- अपशिष्ट पृथक्करण, कम्पोस्टिंग एवं संग्रहण सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की गई।
- स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य एवं तपेदिक उन्मूलन पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण को बढ़ावा दिया गया।
- खेल मैदान, सामुदायिक भवन एवं वर्षा जल संचयन प्रणालियों जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया।
- पंचायत में ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गईं।
- चक्रवात एवं आपदा प्रभावों को कम करने हेतु वृक्षारोपण एवं जैविक सुरक्षा पट्टी विकास किया गया।
- ग्राम सभा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया गया।

रोगों की जांच

चुनौतियाँ

- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता आधारभूत संरचना की अंतिम छोर तक पहुंच एवं रखरखाव सुनिश्चित करना।
- जल जीवन मिशन प्रमाणन जैसी दस्तावेजी कमियों को दूर करना।
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सामुदायिक भागीदारी एवं सततता बनाए रखना।
- सीमित संसाधनों के साथ बिखरी हुई बस्तियों में आधारभूत संरचना का प्रबंधन।

दृष्टिकोण

- ग्राम सभा एवं सामुदायिक बैठकों के माध्यम से सहभागी योजना निर्माण।
- समग्र आधारभूत संरचना विकास हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का अभिसरण।
- अपशिष्ट पृथक्करण, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियानों में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा।
- पारदर्शिता एवं नागरिक सहभागिता हेतु कॉमन सर्विस सेंटर, क्यूआर कोड एवं व्हाट्सएप समूहों का उपयोग।
- आपदा सहनशीलता एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य हेतु पर्यावरण अनुकूल वृक्षारोपण एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा।
- सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली को मजबूत किया गया।

प्राप्त समर्थन

- ओडिशा राज्य सरकार एवं जल जीवन मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा स्वास्थ्य योजनाओं से सहयोग।
- सरकारी विभागों एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदारों से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता।
- डिजिटल प्रशासन, जल प्रबंधन एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- स्वयं सहायता समूहों, ग्राम सभा एवं स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से सक्रिय सामुदायिक सहभागिता।

नवाचार

- अपशिष्ट पृथक्करण, कम्पोस्टिंग एवं प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण के साथ 100% खुले में शौच मुक्त स्थिति।
- चक्रवात एवं खारे पानी के प्रभाव को कम करने हेतु वृक्षारोपण एवं जैविक सुरक्षा पट्टी विकास।
- सभी सार्वजनिक भवनों एवं घरों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं।
- ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग एवं पर्यावरण अनुकूल विकास पहल।
- वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सामुदायिक सहभागिता।

सतत्ता के लिए रोडमैप

- जल, स्वच्छता एवं सड़क आधारभूत संरचना का नियमित रखरखाव एवं उन्नयन।
- आपदा न्यूनीकरण हेतु पर्यावरण अनुकूल वृक्षारोपण एवं जैविक सुरक्षा पट्टी का विस्तार।
- परिसंपत्तियों के सामुदायिक स्वामित्व एवं निरंतर जागरूकता अभियानों को बढ़ावा।
- डिजिटल निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र को संस्थागत रूप देना।
- ईको-टूरिज्म, सूक्ष्म उद्यम एवं सतत कृषि के माध्यम से आय के स्रोतों में विविधता।
- आपदा तैयारी, सामुदायिक अभ्यास एवं सहनशील आधारभूत संरचना को मजबूत करना।

Healthy Panchayat

POTALAMPUR

BLOCK PANCHAYAT: CHATRAPUR
DISTRICT PANCHAYAT: GANJAM
ODISHA

3rd PRIZE

Third Prize- Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 117687
- Total Population: 9,639
- Total Households: 1,913

KEY ACHIEVEMENTS

- All 11 Community Health Centres (CHC) and Health Sub Centers (HSC) are functional, equipped with basic facilities including separate toilets, electricity, and drinking water.
- Established a fully operational Common Service Centre (CSC) with internet, computers, and online service facilities, promoting digital governance.
- Constructed and maintained roads within the panchayat, with all internal roads verified to be in good condition, and connected to main roads.
- Maintained 100% open defecation free (ODF) status with proper sanitation facilities, including household toilets and public toilets.
- Implemented effective solid and liquid waste management systems, including waste segregation, composting, and collection.
- Promoted health and nutrition through regular health camps, immunization, maternal health, and TB elimination initiatives.
- Developed infrastructure such as playgrounds, burial grounds, community halls, and rainwater harvesting systems.
- Installed LED street lights, ensuring energy-efficient lighting across the panchayat.
- Conducted plantation drives, bio-shield development, and eco-sensitive initiatives to mitigate cyclone and disaster impacts.
- Promoted community participation through Gram Sabha, health and sanitation committees, and awareness campaigns.

Screening of diseases

CHALLENGES FACED

- Ensuring last-mile connectivity and maintenance of water supply and sanitation infrastructure.
- Addressing gaps in documentation and certification, such as Jal Jeevan certification.
- Maintaining community participation and sustainability of waste management systems.
- Managing infrastructure in dispersed habitations with limited resources.

APPROACH TAKEN

- Conducted participatory planning through Gram Sabha and community meetings for inclusive decision-making.
- Converged schemes from central and state governments for holistic infrastructure development.
- Promoted community engagement in waste segregation, sanitation, and plantation drives.
- Implemented digital platforms such as CSC, QR codes, and WhatsApp groups for transparency and citizen engagement.
- Used eco-sensitive plantation, bio-shield development, and rainwater harvesting for disaster resilience and environmental health.
- Strengthened routine maintenance, asset management, and monitoring systems with community ownership.

SUPPORT RECEIVED

- Support from Odisha State Government, Central schemes such as Jal Jeevan Mission, MGNREGA, Swachh Bharat Mission, XV Finance Commission grants, and health schemes like AB-PMJAY.
- Technical and financial assistance from government departments and CSR partners.
- Capacity-building for digital governance, water management, and waste processing.
- Active community participation through SHGs, Gram Sabha, and local leadership.

INNOVATIONS

- Achieved 100% ODF status with effective waste segregation, composting, and plastic waste recycling.
- Plantation drives and bio-shield development for cyclone and saltwater intrusion mitigation.
- Rainwater harvesting infrastructure in all public buildings and households.
- Use of energy-efficient LED street lighting and eco-sensitive development initiatives.
- Community participation in plantation, sanitation, and disaster risk reduction.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Maintain and upgrade water, sanitation, and road infrastructure regularly.
- Expand eco-sensitive plantation and bio-shield initiatives for disaster mitigation.
- Promote community ownership of assets and ongoing awareness campaigns.
- Institutionalize digital monitoring, grievance redressal, and transparency mechanisms.
- Diversify income sources via eco-tourism, micro-enterprises, and sustainable agriculture.
- Strengthen disaster preparedness, including community drills and resilient infrastructure.

बाल-हितैषी
पंचायत

बाल हितैषी पंचायत वह है जो यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे अपने अस्तित्व, विकास, सहभागिता एवं संरक्षण के अधिकारों का पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए अपनी क्षमता का पूर्ण विकास कर सकें।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- विद्यालयों में 100% नामांकन।
- बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम एवं बच्चों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा के मामलों में कमी/उन्मूलन।
- दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच।
- अभिभावक-शिक्षक संघ एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- पाँच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की निगरानी।
- एकीकृत बाल विकास सेवा एवं स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं की निगरानी।
- आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में पोषण वाटिका का विकास।
- अवरुद्ध वृद्धि एवं बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी हेतु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
- विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल एवं हाथ धोने की इकाइयों की व्यवस्था।
- स्वास्थ्य, संरक्षण एवं शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रभावी संचालन।
- बच्चों को हिंसा, शोषण, बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करना तथा मामलों की सूचना संबंधित कानूनी प्राधिकरणों को देना।
- बच्चों को अपनी समस्याएं रखने हेतु मंच प्रदान करने के लिए बाल सभा का आयोजन।

CHILD-FRIENDLY PANCHAYAT

A Child-Friendly Panchayat is one which ensures that all children are able to enjoy their rights for survival, development, participation and protection to reach their full potential. The Local Goal and Targets under the theme are:

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- 100% enrolment in schools
- Reducing/Eliminating cases of child marriage, trafficking and child labor and all kinds of violence against children
- Equal access to education for children with disabilities
- Quality education through Parent Teacher Association (PTA)/ School Management Committee (SMCs)

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Quality nutritious food to all children aged under five years; monitor quality of Mid-Day Meal
- Monitor services of ICDS & Health Centres
- Developing Nutri-Garden in Anganwadi Centres & Schools
- Organize health camps to monitor regarding stunted growth routine immunization of children
- Provision of safe drinking water and hand-washing units in school
- Constitution Health, Protection and Education Committees and its functioning
- Protection of children from all violence, abuses and incidents of child marriage, trafficking and child labor and its reporting to appropriate legal authorities
- Organize Bal Sabha for providing a platform to children to put forth their issues

बाल हितैषी पंचायत

इटगांव (पु.)

ब्लॉक पंचायत: भंडारा
जिला पंचायत: भंडारा
राज्य: महाराष्ट्र

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 171985
- कुल जनसंख्या: 750
- कुल परिवार: 195

मुख्य उपलब्धियाँ

- आंगनवाड़ी में नियमित स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से 9ख12 माह आयु वर्ग के बच्चों का 100% टीकाकरण।
- मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत कोई भी कम वजन या कुपोषित बच्चा नहीं पाया गया।
- अवरुद्ध वृद्धि वाले एक बच्चे में निरंतर हस्तक्षेप के माध्यम से सुधार सुनिश्चित किया गया।
- प्राथमिक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात 25:1 बनाए रखा गया।
- विद्यालय में बिजली, पेयजल, पृथक शौचालय एवं दिव्यांग अनुकूल शौचालय उपलब्ध।
- स्मार्ट/डिजिटल आंगनवाड़ी, खिलौने, शिक्षण सामग्री एवं "बोलकी आंगनवाड़ी" जैसी सुविधाओं सहित पूर्णत: कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्र।

आंगनवाड़ी में स्वास्थ्य अभियान

चुनौतियाँ

- गोसीखुर्द बांध परियोजना के कारण पुनर्वासित छोटे गांव में सीमित संस्थागत आधारभूत संरचना।
- भौगोलिक दूरी एवं प्रारंभिक जागरूकता की कमी।
- उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु बच्चों को निकटवर्ती गांवों में जाना पड़ता है।
- बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना।
- अवरुद्ध वृद्धि के मामलों के लिए निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता।
- व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर जागरूकता एवं परामर्श की आवश्यकता।

दृष्टिकोण

- महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों के बीच समन्वित सेवा वितरण।
- ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की सक्रिय भागीदारी।
- स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु नियमित घर-घर संपर्क एवं परामर्श।
- अवरुद्ध वृद्धि वाले बच्चे के लिए निरंतर परामर्श एवं निगरानी।
- डिजिटल एवं खेल आधारित शिक्षण पद्धतियों से स्मार्ट आंगनवाड़ी का विकास।
- ताजा सब्जियों एवं पोषण शिक्षा हेतु पोषण वाटिका की स्थापना।
- बाल सभा के माध्यम से बच्चों की सहभागिता एवं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी।
- नुक्कड़ नाटक, ग्राम सभा एवं सामुदायिक बैठकों के माध्यम से जागरूकता अभियान।

प्राप्त समर्थन

- महिला एवं बाल विकास विभाग से पोषण एवं मातृ देखभाल संबंधी मार्गदर्शन।
- स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग।
- पंद्रहवें वित्त आयोग निधि से आंगनवाड़ी उन्नयन।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन सहयोग।
- विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना।
- शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मचारियों का पंचायत के साथ समन्वय।
- बाल सभा एवं महिला सभा के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता।

नवाचार

- "लिटिल हैंड्स, ग्रोइंग प्लांट्स" पहल, जिसमें प्रत्येक बच्चा पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है।
- डिजिटल एवं इंटरैक्टिव शिक्षण पद्धतियों से युक्त स्मार्ट आंगनवाड़ी।
- ताजी सब्जियां एवं व्यावहारिक पोषण शिक्षा उपलब्ध कराने वाली पोषण वाटिका।
- बाल अधिकार एवं संरक्षण जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक एवं सामुदायिक सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां।
- पुस्तकालय एवं पठन पहल के माध्यम से शैक्षिक विकास को बढ़ावा।
- संस्थागत अभिसरण आधारित सामुदायिक मॉडल, जो अन्य पंचायतों के लिए अनुकरणीय है।

सतत्ता के लिए रोडमैप

- स्मार्ट आंगनवाड़ी गतिविधियों एवं डिजिटल शिक्षण उपकरणों को मजबूत करना।
- पोषण वाटिका का रखरखाव एवं परिवारों में पोषण शिक्षा को बढ़ावा।
- बाल सभा एवं जागरूकता अभियानों को संस्थागत रूप देना।
- बच्चों की स्थानीय शासन एवं विकास में भागीदारी बढ़ाना।
- दीर्घकालिक बाल विकास हेतु विभागीय अभिसरण को मजबूत करना।
- नियमित स्वच्छता अभियान एवं पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा।
- सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से बाल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर निरंतर ध्यान।

Child Friendly Panchayat

ITGAON (PU.)

BLOCK PANCHAYAT: BHANDARA
DISTRICT PANCHAYAT: BHANDARA
STATE: MAHARASHTRA

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 171985
- Total Population: 750
- Total Households: 195

KEY ACHIEVEMENTS

- 100% immunization coverage for children aged 9–12 months through regular health campaigns in Anganwadi.
- No underweight or wasted children reported under Mission Poshan 2.0; continuous monitoring ensures early detection.
- One previously stunted child successfully improved through sustained WCD and health department coordination.
- Primary school PTR maintained at 25:1 within prescribed norms.
- School has electricity, drinking water, and separate toilets including a CWSN-friendly toilet, along with handwashing facilities.
- Fully functional Anganwadi Centre with enhanced facilities including Smart/ Digital Anganwadi, toys, learning materials, and interactive wall paintings ("Bolki Anganwadi").

Health campaigns in Anganwadi

CHALLENGES FACED

- Limited institutional infrastructure as the village is small and resettled due to the Gosikhurd Dam project.
- Geographic remoteness and initial lack of awareness among the community.
- Children must travel to nearby villages for upper primary and higher classes.
- Ensuring continuous monitoring of child nutrition and health in a small population base.
- Addressing stunting cases with sustained interventions.
- Behavioural change among villagers required continuous effort through awareness and counselling.

APPROACH TAKEN

- Close coordination with WCD, Health, and Education departments ensuring convergent service delivery.
- Active involvement of VCPC and SMC in planning, monitoring, and implementation.
- Regular home visits, counseling, and follow-up for health and nutrition interventions.
- Counseling and follow-up for the identified stunted child until full recovery.
- Development of Smart Anganwadi using digital, play-based, and interactive learning methods.
- Establishment of Poshan Vatika to enhance nutrition through fresh, locally grown vegetables.
- Regular Bal Sabha enabling children to express issues and participate in decision-making.
- Awareness campaigns through street plays (Pathnatya), Gram Sabha, and community meetings.

SUPPORT RECEIVED

- Guidance and support from WCD Department for addressing stunting, maternal care, and nutrition services.
- Health Department support for immunization, adolescent health campaigns, and MCH services.
- Utilization of 15th Finance Commission grants for Anganwadi upgradation (digital tools, infrastructure, learning materials).
- Support under Swachh Bharat Mission (Grameen) for solid waste management and sanitation improvements.
- Installation of rainwater harvesting systems in school and Anganwadi.
- Teachers and school staff coordinating closely with Panchayat.
- Community participation through Bal Sabha, Mahila Sabha, and local awareness initiatives.
- Technical and educational support extended through various government departments.

INNOVATIONS

- "Little Hands, Growing Plants" initiative where each child plants and nurtures a sapling, promoting environmental awareness.
- Smart Anganwadi equipped with digital and interactive learning methods.
- Poshan Vatika providing fresh vegetables and practical nutrition education.
- Use of street plays (Pathnatya) and community-based IEC for awareness on child rights and protection.
- Library and reading initiatives supporting educational growth and future aspirations.
- Strong community-led model with institutional convergence, making the Panchayat a replicable model for Child-Friendly Villages.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthen Smart Anganwadi activities and expand digital and play-based learning tools.
- Continue Poshan Vatika maintenance and promote nutrition education among families.
- Institutionalize regular Bal Sabha, Gram Sabha, and awareness campaigns for sustained behavioral change.
- Enhance children's participation in community development and local governance.
- Strengthen convergence with line departments for long-term child development outcomes.
- Continue weekly cleanliness drives and promote environmental sustainability practices.
- Ensure continuous focus on child safety, health, nutrition, and education through community ownership.

बाल हितैषी पंचायत

हलनायकनहल्ली

ब्लॉक पंचायत: बेंगलुरु पूर्व
जिला पंचायत: बेंगलुरु शहरी
राज्य: कर्नाटक

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 245242
- कुल जनसंख्या: 15,476
- कुल परिवार: 5,157

मुख्य उपलब्धियाँ

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 100% नामांकन तथा शून्य ड्रॉपआउट।
- सभी नवजात बच्चों का पूर्ण टीकाकरण एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी।
- स्मार्ट टीवी, शिक्षण सामग्री एवं डिजिटल सेवा प्रणाली से युक्त आंगनवाड़ी केंद्र।
- विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में सुरक्षित पेयजल हेतु फिल्ट्रेशन इकाइयां।
- पोषण एवं स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से कम वजन एवं कुपोषण के मामलों में उल्लेखनीय कमी।
- बाल सभा एवं मक्कला ग्राम सभा के माध्यम से बच्चों की संरचित सहभागिता।

स्वास्थ्य शिविर एवं किट वितरण

चुनौतियाँ

- बाल अधिकार एवं संरक्षण के प्रति निरंतर जागरूकता की आवश्यकता।
- सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता संदेशों की बेहतर दृश्यता की आवश्यकता।
- कुपोषण मुक्त स्थिति बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयास।
- शहरी क्षेत्र के निकट होने के बावजूद डिजिटल विभाजन की समस्या।
- बिखरी हुई आबादी में सेवा वितरण सुनिश्चित करना।
- पोषण एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करना।

दृष्टिकोण

- आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षक एवं गैर-सरकारी संगठनों के बीच मजबूत अभिसरण।
- बाल संरक्षण समिति एवं मक्कला ग्राम सभा जैसे सहभागी मंचों को मजबूत करना।
- गर्भवती महिलाओं एवं अभिभावकों के लिए पोषण एवं बाल विकास पर परामर्श।
- बच्चों की वृद्धि, टीकाकरण एवं विद्यालय उपस्थिति की निरंतर निगरानी।
- स्मार्ट कक्षाओं, कोडिंग शिक्षा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण सहित डिजिटल शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था।
- बच्चों के मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण हेतु परामर्श सेवाओं की शुरुआत।
- बाल सभा एवं विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की सहभागिता।
- बाल मेला एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता।

प्राप्त समर्थन

- स्वास्थ्य, पोषण एवं टीकाकरण सेवाओं हेतु स्वास्थ्य केंद्र, आशा एवं आंगनवाड़ी कर्मचारियों का सहयोग।
- डिजिटल शिक्षण एवं जागरूकता के लिए गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग।
- एकीकृत बाल विकास सेवा एवं शिक्षा विभाग के साथ समन्वय।
- बाल केंद्रित पहलों हेतु पंचायत निधियों से वित्तीय सहायता।
- शिक्षकों, अभिभावकों एवं सामुदायिक नेताओं की सक्रिय भागीदारी।

नवाचार

- डिजिटल समावेशन हेतु डिजिटल पुस्तकालय एवं कंप्यूटर शिक्षण केंद्र।
- बच्चों को भविष्य के अवसरों हेतु तैयार करने वाली कोडिंग कक्षाएं एवं स्मार्ट कक्षाएं।
- इंटरैक्टिव एवं खेल आधारित शिक्षण के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में टीवी की व्यवस्था।
- बाल मेला एवं सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता।
- शारीरिक विकास हेतु आउटडोर खेल उपकरण।
- विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं।
- पंचायत की स्वयं की आय से छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं।
- तकनीक आधारित सहभागी शासन मॉडल, जो अन्य पंचायतों के लिए अनुकरणीय है।

सतत्ता के लिए रोडमैप

- बाल संरक्षण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियानों को मजबूत करना।
- कोडिंग एवं डिजिटल साक्षरता सहित डिजिटल शिक्षण पहल का विस्तार।
- प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप हेतु डेटा आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करना।
- मक्कला ग्राम सभा एवं बाल संसद को संस्थागत रूप देना।
- बिखरी हुई आबादी तक पहुंच हेतु नवाचारी सेवा वितरण मॉडल विकसित करना।
- नियमित स्वास्थ्य शिविर एवं पोषण हस्तक्षेप जारी रखना।
- बच्चों द्वारा संचालित पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा।
- गैर-सरकारी संगठनों एवं सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी मजबूत करना।

Child Friendly Panchayat

HALANAYAKANAHALLI

BLOCK PANCHAYAT: BENGALURU EAST
DISTRICT PANCHAYAT: BENGALURU URBAN
STATE: KARNATAKA

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 245242
- Total Population: 15,476
- Total Households: 5,157

KEY ACHIEVEMENTS

- 100% enrollment at both Primary and Upper Primary levels with zero dropout cases, supported by active re-enrolment mechanisms.
- All live births fully immunized as verified through PHC records, with continuous tracking of maternal and child health.
- Anganwadi Centres equipped with Smart TVs, learning materials, well-maintained kitchens, and digitised service delivery systems.
- Provision of safe drinking water through filtration units in schools and Anganwadi Centres.
- Significant reduction in underweight, stunting, and wasting cases through sustained nutrition and health interventions.
- Regular Bal Sabha and Makkala Gramasabha (Children's Gram Sabha) promoting structured child participation in governance.

Health Camps and kits distribution

CHALLENGES FACED

- Need for consistent awareness on child rights, protection, and social issues.
- Requirement for improved visibility of awareness messages in public areas.
- Ongoing efforts needed to maintain zero malnutrition status.
- Addressing digital divide despite proximity to an urban ecosystem.
- Managing service delivery across scattered population clusters.
- Overcoming social stigma related to nutrition and mental health interventions.

APPROACH TAKEN

- Strong convergence between Anganwadi, ASHA, PHC staff, teachers, NGOs, and Panchayat ensuring integrated service delivery.
- Institutional strengthening through Child Protection Committee and participatory platforms like Makkala Gramasabha.
- Counselling for pregnant women and parents on nutrition, vaccination, and child development.
- Continuous monitoring of child growth, immunization, and school attendance using systematic tracking.
- Provision of digital learning tools including smart classrooms, coding education, and computer training.
- Introduction of professional counselling services in schools to support children's mental and emotional well-being.
- Regular child participation through Bal Sabha, Gram Sabha, and school-level engagement activities.
- Community mobilization via Bal Mela, awareness campaigns, and parent meetings.

SUPPORT RECEIVED

- Support from PHC, ANMs, ASHA, and Anganwadi staff for health, nutrition, and immunization services.
- Educational and technical support from NGOs for digital learning and awareness initiatives.
- Collaboration with ICDS, Education Department, and other line departments.
- Financial and operational support through Panchayat own funds for child-centric initiatives.
- Active involvement of teachers, parents, and community leaders in implementation and monitoring.

INNOVATIONS

- Digital Library and Computer Learning Centre promoting digital inclusion.
- Coding classes and smart classrooms preparing children for future opportunities.
- TVs in Anganwadi Centres enabling interactive and play-based learning.
- Bal Mela and community events promoting child participation and social awareness.
- Outdoor play equipment ensuring physical development and engagement.
- Introduction of mental health counselling services in schools.
- Financial incentives and scholarships supported through Panchayat own-source revenue.
- Strong 360-degree, technology-enabled and participatory governance model, making the Panchayat a replicable example.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthen awareness campaigns on child protection, education, and health.
- Expand digital learning initiatives including advanced skill development (coding, digital literacy).
- Introduce data-driven monitoring systems (Child Development Dashboard) for early identification and intervention.
- Institutionalize Children's Parliament / Makkala Gramasabha for sustained participatory governance.
- Enhance outreach mechanisms for scattered populations through innovative service delivery models.
- Continue regular health camps, counselling services, and nutrition interventions.
- Promote environmental awareness through child-led initiatives and school activities.
- Strengthen partnerships with NGOs and government agencies for long-term sustainability.

बाल हितैषी पंचायत

ओट्टूर

ब्लॉक पंचायत: वर्कला
जिला पंचायत: तिरुवनंतपुरम
राज्य: केरल

3rd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 221814
- कुल जनसंख्या: 16,085
- कुल परिवार: 6,687

मुख्य उपलब्धियाँ

- 100% जन्म पंजीकरण एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा।
- स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय एवं बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध।
- नियमित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच।
- वर्ष में चार बार बाल सभा आयोजित, जिसमें बच्चों की समस्याओं को ग्राम सभा योजना एवं बजट में शामिल किया गया।
- बच्चों की आवश्यकताओं को पंचायत विकास योजनाओं में समाहित करने वाला मजबूत बाल केंद्रित योजना मॉडल।
- विद्यालय पुस्तकालय, जिम एवं स्मार्ट शिक्षण आधारभूत संरचना जैसी शिक्षा संबंधी पहल।

स्वास्थ्य शिविर एवं किट वितरण

चुनौतियाँ

- पोषण ट्रैकर ऐप में तकनीकी त्रुटियों के कारण अवरुद्ध वृद्धि संबंधी गलत आंकड़े।
- पोषण संकेतकों के अद्यतन में पोर्टल संबंधी विसंगतियां।
- दो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित।
- कई अभिलेख केवल मलयालम भाषा में उपलब्ध होने से दस्तावेजी कठिनाइयां।
- आंगनवाड़ी एवं बाल देखभाल सुविधाओं हेतु भूमि की कमी।
- बच्चों में मानसिक तनाव, मोबाइल की लत एवं असामाजिक गतिविधियों जैसी नई चुनौतियां।

दृष्टिकोण

- एकीकृत बाल विकास सेवा पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी शिक्षकों द्वारा बच्चों की पोषण स्थिति का सत्यापन।
- नियमित ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से टीकाकरण एवं पोषण परामर्श।
- बाल सभा एवं ग्राम सभा के माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं को वार्षिक योजनाओं में शामिल करना।
- बच्चों की अपशिष्ट प्रबंधन एवं जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी।
- पुस्तकालय, जिम, डिजिटल कक्षाओं एवं मानसिक स्वास्थ्य सत्रों के माध्यम से शैक्षिक सुदृढ़ीकरण।
- बाल सभा को संस्थागत रूप देकर बच्चों को सीधे मुद्दे उठाने का अवसर।

प्राप्त समर्थन

- एकीकृत बाल विकास सेवा, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं कृषि भवन के साथ मजबूत समन्वय।
- केंद्र एवं राज्य योजनाओं, त्रिस्तरीय पंचायतों एवं गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग।
- पंचायत द्वारा क्रेच, परामर्श सेवाएं एवं महिला-बाल संरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
- विद्यालय अभिभावक-शिक्षक संघ, पूर्व छात्र नेटवर्क एवं सामुदायिक स्वयंसेवकों की भागीदारी।
- आधारभूत संरचना, पोषण एवं खेल विकास हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता।

नवाचार

- विभिन्न खेलों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर का इनडोर स्टेडियम।
- प्रारंभिक बाल देखभाल एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने वाला स्मार्ट आंगनवाड़ी-सह-क्रेच।
- बच्चों में कृषि सीखने को बढ़ावा देने वाला "कुट्टी कृषक" कार्यक्रम।
- पुनः उपयोग एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने वाली "स्वैप शॉप" पहल।
- बाल एवं मातृ स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों का समन्वय।
- मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता एवं बाल अधिकारों पर संरचित जागरूकता प्रणाली।
- थुम्बूरमुजी प्रणाली एवं विद्यालय आधारित अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों जैसे नवाचार।

सततता के लिए रोडमैप

- डिजिटल निगरानी प्रणाली को मजबूत करना एवं पोषण ट्रैकर विसंगतियों का समाधान।
- बच्चों की आवश्यकताओं को पंचायत विकास योजनाओं में प्रतिवर्ष शामिल करना।
- प्रारंभिक बाल देखभाल सेवाओं एवं आंगनवाड़ी आधारभूत संरचना का विस्तार।
- कृषि, खेल एवं जीवन कौशल शिक्षा सहित कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा।
- मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सामाजिक मुद्दों पर निरंतर जागरूकता।
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु खेल अवसंरचना में निवेश।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी कार्यक्रमों को मजबूत करना।
- बहु-हितधारक साझेदारी आधारित विकास को निरंतर बढ़ावा देना।

Child Friendly Panchayat

OTTOOR

BLOCK PANCHAYAT: VARKALA
DISTRICT PANCHAYAT: THIRUVANANTHAPURAM
STATE: KERALA

3rd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 221814
- Total Population: 16,085
- Total Households: 6,687

KEY ACHIEVEMENTS

- 100% birth registration; institutional deliveries widely preferred.
- Health Sub Centre and Anganwadi centres well-maintained with proper drinking water, toilets, and electricity.
- Regular Village Health and Nutrition Days (VHND) ensuring immunization, health check-ups, and nutrition awareness.
- Bal Sabha conducted four times a year, with children's concerns integrated into Gram Sabha planning and budgeting.
- Strong child-centric planning model, where children's needs are identified through consultations and incorporated into Panchayat development plans.
- Significant initiatives in education including establishment of school libraries, gym, and smart learning infrastructure.

Facilities available such as library and gym

CHALLENGES FACED

- Major discrepancy in portal data showing 132 stunted and 4 wasted children; ICDS verification confirmed 0 cases due to technical errors in the Poshan Tracker app.
- Updates in nutrition indicators not reflected properly on the portal, causing verification inconsistencies.
- Two Anganwadi centres still operating from rented buildings due to limited infrastructure availability.
- Documentation challenges because several registers and records are available only in Malayalam.
- Limited availability of land for infrastructure development such as Anganwadi and childcare facilities.
- Addressing emerging challenges like child mental stress, mobile addiction, and exposure to anti-social activities.

APPROACH TAKEN

- Verification of child nutrition status through ICDS Supervisor and Anganwadi teachers, with written undertaking confirming zero stunting/wasting cases.
- Regular VHND to ensure immunization coverage, maternal counselling, and nutrition promotion.
- Adoption of participatory planning approach, where children's needs identified through Bal Sabha, school discussions, and Gram Sabha are integrated into annual plans and budgets.
- Children deeply involved in waste management initiatives, flash mobs, and community awareness activities.
- Educational strengthening through library, gym, digital classrooms, motivational classes, financial literacy, and mental well-being sessions.
- Institutionalized Bal Sabha enabling children to raise issues directly and participate in governance.

SUPPORT RECEIVED

- Strong collaboration with ICDS, Health Department, Education Department, and Krishibhavan.
- Multi-stakeholder support including Central/State Government schemes, three-tier Panchayats, NGOs, and community contributions.
- Panchayat-supported facilities including creche, counselling services, and women-child protection mechanisms.
- Participation of school PTA, alumni networks, and community volunteers in child development initiatives.
- Technical and financial support for infrastructure, nutrition, sanitation, and sports development.

INNOVATIONS

- International-standard Indoor Stadium providing free professional training in multiple sports disciplines.
- Smart Anganwadi-cum-creche ensuring early childcare, medical support, and safe environment for infants.
- Kutti Karshaka programme promoting experiential agricultural learning among children.
- Swap Shop initiative promoting reuse, social responsibility, and community sharing.
- Integration of traditional (Ayurveda/Homeopathy) and modern healthcare systems for child and maternal care.
- Structured awareness ecosystem covering mental health, gender, addiction, and child rights.
- Waste management innovations including Thumboormuzhi system and school-based waste handling units.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthen digital monitoring systems and resolve nutrition indicator discrepancies in Poshan Tracker.
- Continue participatory planning by integrating children's needs into Panchayat Development Plans annually.
- Expand early childhood care services and strengthen Anganwadi infrastructure (own buildings).
- Further enhance skill development activities including agriculture, sports, and life skills education.
- Promote sustained awareness on mental health, sanitation, menstrual hygiene, and social issues.
- Maintain long-term investment in sports ecosystem to nurture talent at state and national levels.
- Strengthen inclusion programmes for children with special needs and ensure equitable access to services.
- Continue convergence-based development through multi-stakeholder partnerships.

जल पर्याप्त

पंचायत

जल पर्याप्त पंचायत वह है जो यह सुनिश्चित करे कि:

- सभी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण नल जल कनेक्शन उपलब्ध हों।
- जल का समुचित प्रबंधन हो।
- कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो।
- जल पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाए।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- सभी को पर्याप्त स्वच्छ एवं पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता।
- सभी को स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता।
- घरेलू शौचालयों का 100% उपयोग सुनिश्चित करना।
- ग्रे-वाटर उपचार एवं शुद्धिकरण की व्यवस्था विकसित करना।
- भूजल दोहन, आर्सेनिक प्रदूषण को रोकना तथा वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना।
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन।

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- जल एवं स्वच्छता परिसंपत्तियों के उपयोग एवं प्रबंधन पर लोगों को जागरूक करना।
- विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक एवं कार्यशील शौचालय सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- मैजिक पिट, किचन गार्डन आदि जैसी तकनीकों को अपनाकर जलापूर्ति एवं ग्रे-वाटर प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित एजेंसियों से समन्वय करना।
- परिसंपत्ति प्रबंधन हेतु जन समितियों का गठन एवं क्षमता निर्माण।
- जल निकायों की सुरक्षा एवं जल परीक्षण के माध्यम से जल गुणवत्ता की निगरानी।

WATER SUFFICIENT PANCHAYAT

A WATER SUFFICENT PANCHAYAT IS ONE WHICH ENSURES:

- Functional House Tap Connections of quality water supply to all
- Good water management
- Abundant water availability for agriculture and all needs
- Conserving its water ecosystem.

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Access to adequate clear water and potable water facilities to all
- Access to sanitation facilities to all
- Ensure 100% usage of Household Latrines
- Develop mechanism on grey water treatment & purification
- Prevent groundwater depletion, arsenic contamination, rainwater harvesting and groundwater recharge
- Constitution of Water & Sanitation Committees for conservation of natural resources

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Educating people on usage and management of water and sanitation assets
- Ensure adequate and separate functional toilet facilities for boys and girls in schools and Anganwadi Centres
- Ensure maintenance of public toilets
- Adopting water supply and grey water management technology like magic pits, kitchen gardening etc. and promoting modern agriculture and water use technologies
- Liaise with respective agencies for ensuring adequate and potable water supply
- Constitution of People's committee and their capacity building for assets management
- Safeguarding water bodies and monitoring water quality through water testing

जल पर्याप्त पंचायत

खरीवाली

ब्लॉक पंचायत: खालापुर
जिला पंचायत: रायगढ़
राज्य: महाराष्ट्र

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 186775
- कुल जनसंख्या: 2,934
- कुल परिवार: 615

मुख्य उपलब्धियाँ

- सभी 615 परिवारों को 100% कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध; "हर घर जल" घोषित।
- 7 नए जल स्रोत विकसित एवं 14 पारंपरिक जल स्रोत पुनर्जीवित।
- निधियों के अभिसरण से 3 चेक डैम, 3 परकोलेशन टैंक एवं 4 सीमेंट कंक्रीट चेक डैम का निर्माण।
- सार्वजनिक भवनों पर 13 वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना।
- सरोवर संवर्धन योजना के अंतर्गत 2 तालाबों का खुदाई एवं पुनर्भरण।
- ग्राम पंचायत द्वारा संचालित जल जीवन मिशन की 5 योजनाएं पूर्ण।
- 28 किलोवाट सौर पंप प्रणाली स्थापित कर शून्य बिजली बिल सुनिश्चित किया गया।
- सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में 100% नल जल एवं हाथ धोने की सुविधा।
- सुरक्षित पेयजल हेतु वाटर एटीएम की स्थापना।
- प्रत्येक परिवार द्वारा शौचालय उपयोग के साथ खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल गांव घोषित।
- स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु 475 सोख गड्ढे एवं 55 लीच पिट का निर्माण।

वॉटर एटीएम मशीन

चुनौतियाँ

- पर्याप्त वर्षा के बावजूद भूजल स्तर में गिरावट।
- संरक्षण संरचनाओं के अभाव में वर्षा जल का बहाव।
- जल संकट के कारण गांव से पलायन।
- भूजल पुनर्भरण एवं वर्षा जल उपयोग के प्रति सीमित जागरूकता।
- वित्तीय एवं तकनीकी विशेषज्ञता में देरी एवं कमी।

दृष्टिकोण

- ग्राम स्तर पर जल बजट हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई।
- ग्राम सभा एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से जागरूकता।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को जल संरक्षण अभियान से जोड़ा गया।
- श्रमदान, वृक्षारोपण एवं जल निकायों की गाद सफाई के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी।
- जल प्रबंधन हेतु जल मीटर स्थापना एवं रिसाव की त्वरित मरम्मत।
- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा।

प्राप्त समर्थन

- जल जीवन मिशन, राज्य योजनाओं, जिला योजना समिति निधि एवं पंद्रहवें वित्त आयोग निधियों का अभिसरण।
- फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल परीक्षण एवं प्लंबर प्रशिक्षण।
- गैर-सरकारी संगठनों एवं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व साझेदारों से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग।

नवाचार

- सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति प्रणाली से ऊर्जा सततता एवं शून्य बिजली लागत।
- सुरक्षित पेयजल हेतु वाटर एटीएम।
- जल संरक्षण एवं जवाबदेही हेतु जल मीटर प्रणाली।
- सरोवर संवर्धन योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर तालाब पुनर्भरण।
- जल जनित रोगों की रोकथाम हेतु "फ्राइडे ड्राई डे" पहल।

सतत्ता के लिए रोडमैप

- जल संरक्षण संरचनाओं एवं योजनाओं का नियमित रखरखाव।
- मानसून पूर्व सभी जल निकायों की गाद सफाई।
- सुरक्षित पेयजल हेतु नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण।
- स्वयं सहायता समूहों एवं जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से निरंतर सामुदायिक भागीदारी।
- वर्षा एवं मृदा स्वास्थ्य के आधार पर वैज्ञानिक फसल योजना।

Water Sufficient Panchayat

KHARIWALI

BLOCK PANCHAYAT: KHALAPUR
DISTRICT PANCHAYAT: RAIGAD
STATE: MAHARASHTRA

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 186775
- Total Population: 2,934
- Total Households: 615

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% Functional Household Tap Connections across all 615 families; declared "Har Ghar Jal"
- Developed 7 new water sources and revived 14 traditional water sources
- Constructed 3 check dams, 3 percolation tanks, and 4 cement concrete check dams through fund convergence
- Installed 13 rainwater harvesting systems on public buildings
- Excavated and recharged 2 ponds under Sarovar Samvardhan Yojana (₹2.17 Crore)
- Completed 5 JJM schemes worth ₹1.77 Crore, operated by the Gram Panchayat
- Installed 28 kW solar pump system (₹26 Lakh) on JJM scheme, resulting in zero electricity bills
- Ensured 100% tap water access and handwash stations in all 5 schools and 5 Anganwadis
- Installed Water ATM for safe drinking water access
- Declared ODF Plus Model village with every household using a toilet
- Constructed 475 soak pits and 55 leach pits for sanitation and environmental protection

Water ATM Machine

CHALLENGES FACED

- Declining groundwater levels despite adequate annual rainfall
- Rainwater wasted as surface runoff due to lack of conservation structures
- Water scarcity forcing migration from the village
- Limited community awareness on groundwater recharge and rainwater utilisation
- Delays in fund availability and gaps in technical expertise

APPROACH TAKEN

- Adopted Participatory Rural Appraisal (PRA) for village-level water budgeting
- Raised awareness through Gram Sabha and Village Water and Sanitation Committee (VWSC)
- Mobilised Women SHGs to drive water conservation and groundwater recharge messaging
- Promoted community participation through Shramdaan, tree plantation, Vanrai Bandhaare construction, and desilting of water bodies
- Installed water meters for efficient water management and prompt leakage repairs
- Promoted micro-irrigation through drip and sprinkler systems for optimal water use

SUPPORT RECEIVED

- Financial convergence of JJM, State schemes, DPC funds, 15th Finance Commission grants, and GP own-source funds
- Training on FTK water testing through JJM and plumber/handyman skills through District Skill Centre
- Funding, awareness, and technical support from NGOs and CSR partners
- Roadmap for Sustainability
- Regular maintenance and timely repair of water conservation structures and JJM schemes
- Periodic desilting of all water bodies before the onset of monsoon
- Continuous water quality testing to ensure safe drinking water supply
- Sustained community participation through SHGs and public awareness drives
- Scientific cropping pattern planning based on rainfall data and soil health studies

INNOVATIONS

- Solar-powered water supply system ensuring energy sustainability and zero electricity cost
- Water ATM installation for accessible and safe drinking water
- Water metering system promoting conservation and accountability
- Large-scale pond excavation and recharge under Sarovar Samvardhan Yojana
- "Friday Dry Day" initiative to combat water-borne diseases and promote health awareness

जल पर्याप्त पंचायत

मदमक्की

ब्लॉक पंचायत: हेबरी
जिला पंचायत: उडुपी
राज्य: कर्नाटक

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 220487
- कुल जनसंख्या: 4,427
- कुल परिवार: 1,120

मुख्य उपलब्धियाँ

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी परिवारों को 100% कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन; "हर घर जल" घोषित।
- पारंपरिक तालाबों का पुनर्जीवन एवं भूजल पुनर्भरण हेतु चेक डैम निर्माण।
- 100% जल कर संग्रहण से संचालन एवं रखरखाव निधि सुदृढ़।
- ग्रे-वाटर प्रबंधन हेतु सामुदायिक एवं व्यक्तिगत मैजिक पिट का निर्माण।
- प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकों द्वारा फील्ड टेस्ट किट से नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण।

प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवक एवं पंप ऑपरेटर फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल गुणवत्ता की जांच करते हुए

चुनौतियाँ

- पश्चिमी घाट के दुर्गम क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने में कठिनाई।
- बिखरी हुई आबादी के कारण अंतिम छोर तक अवसंरचना पहुंचाना चुनौतीपूर्ण।
- गर्मियों में बोरवेल सूखने से मौसमी जल संकट।
- जल मीटर एवं नियमित उपयोग शुल्क को लेकर प्रारंभिक विरोध।

दृष्टिकोण

- जल जीवन मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पंद्रहवें वित्त आयोग निधियों का अभिसरण।
- 100% जल मीटरिंग एवं नल जल मित्रों की नियुक्ति।
- ग्राम सभा एवं जल दूतों के माध्यम से जल संरक्षण जागरूकता।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सामुदायिक निगरानी हेतु मजबूत करना।

प्राप्त समर्थन

- जल जीवन मिशन से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग।
- ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से तकनीकी सहायता।
- पंद्रहवें वित्त आयोग से संचालन एवं रखरखाव निधि।
- स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा सामुदायिक निगरानी।

नवाचार

- विकेंद्रीकृत बिलिंग एवं रखरखाव हेतु नल जल मित्र प्रणाली।
- घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर वैज्ञानिक ग्रे-वाटर प्रबंधन हेतु मैजिक पिट।
- जल संरक्षण एवं वित्तीय सततता हेतु 100% जल मीटरिंग।
- जल उपयोग एवं कर भुगतान पर व्यवहार परिवर्तन हेतु जल दूत अभियान।
- पारंपरिक तालाबों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक तकनीकों का समन्वय।

सततता के लिए रोडमैप

- जल कर संग्रहण के माध्यम से संचालन एवं रखरखाव निधि को मजबूत बनाए रखना।
- वर्षा जल संचयन संरचनाओं का विस्तार।
- पाइपलाइन मरम्मत हेतु बहु-कुशल कर्मियों का प्रशिक्षण।
- सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- नल जल मित्रों एवं फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से निरंतर जल गुणवत्ता निगरानी।

Water Sufficient Panchayat

MADAMAKKI

BLOCK PANCHAYAT: HEBRI
DISTRICT PANCHAYAT: UDUPI
STATE: KARNATAKA

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 220487
- Total Population: 4,427
- Total Households: 1,120

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% Functional Household Tap Connections (FHTC) across all 1,120 households under Jal Jeevan Mission; declared "Har Ghar Jal"
- Rejuvenated traditional Madakas (ponds) and constructed multiple check dams and vented dams for groundwater recharge
- Achieved 100% water tax collection efficiency, building an O&M fund balance of over ₹6.5 Lakhs
- Constructed community and individual soak pits (Magic Pits) for scientific greywater treatment and prevention of stagnation
- Institutionalised regular water quality testing using Field Test Kits (FTK) by trained women volunteers

Trained women volunteer and pump operators testing water quality using Field Test Kits

CHALLENGES FACED

- Rugged and undulating terrain of the Western Ghats made pipeline laying logistically difficult and costly
- Scattered settlement pattern across 6,000+ hectares required extensive last-mile infrastructure
- Seasonal water stress during summer months due to drying borewells
- Initial community resistance to water meters and regular user charge payments

APPROACH TAKEN

- Adopted a Convergence Framework utilising JJM, MGNREGS, and 15th Finance Commission funds for durable infrastructure
- Implemented 100% water metering and deployed Nal Jal Mitras for regular billing and maintenance
- Conducted IEC campaigns through Gram Sabhas and Jal Doots to promote water conservation and tax compliance
- Strengthened Village Water and Sanitation Committee (VWSC) for community-led monitoring

SUPPORT RECEIVED

- Core funding and vision through Jal Jeevan Mission (Har Ghar Jal)
- Technical expertise from Rural Drinking Water and Sanitation Department (RDWSD) for hydraulic design in hilly terrain
- O&M funding through 15th Finance Commission grants
- Community mobilisation and quality monitoring by SHGs and VWSC

INNOVATIONS

- Nal Jal Mitra system for decentralised billing, maintenance, and last-mile accountability
- Magic Pits for scientific greywater management at household and community level
- 100% water metering promoting conservation, accountability, and financial sustainability
- Jal Doot-led IEC campaigns driving community behaviour change on water use and tax compliance
- Rejuvenation of traditional Madakas integrating indigenous water knowledge with modern recharge techniques

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Sustain dedicated O&M fund through robust water tax collection to cover repairs and staff salaries
- Intensify Catch the Rain campaign to saturate the village with rooftop rainwater harvesting structures
- Continue training of multi-skilled staff for prompt pipeline repairs and system maintenance
- Conduct regular Social Audits to ensure transparency and accountability in water resource management
- Maintain continuous water quality monitoring through Nal Jal Mitras and FTK testing

जल पर्याप्त पंचायत

पडुआ

ब्लॉक पंचायत: चंपुआ
जिला पंचायत: क्योंझर
राज्य: ओडिशा

3rd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका कोड: 119300
- कुल जनसंख्या: 5,016
- कुल परिवार: 1,265

मुख्य उपलब्धियाँ

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी परिवारों को 100% कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन।
- पाइप जलापूर्ति योजनाएं, 115 नलकूप, 27 सामुदायिक टैंक एवं 3 सौर द्वि-बिंदु प्रणालियों का निर्माण।
- 620 किलोलीटर एवं 290 किलोलीटर क्षमता वाले ऊंचे जलाशय एवं 60 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित।
- सभी गांवों में वर्षभर विश्वसनीय पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित।
- प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह सदस्यों एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण।
- 50% महिला प्रतिनिधित्व वाली ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन।
- सोख गड्ढों एवं जल निकासी प्रणालियों के माध्यम से ग्रे-वाटर प्रबंधन।
- नियमित निगरानी एवं जागरूकता से जल जनित रोगों में कमी।

पंचायत में जल शोधन संयंत्र

चुनौतियाँ

- मौसमी जल संकट एवं दूरस्थ जल स्रोतों पर निर्भरता।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए समावेशी कवरेज सुनिश्चित करना।
- बिखरे हुए गांवों में व्यापक अवसंरचना की आवश्यकता।
- ऊर्जा दक्षता एवं संचालन लागत कम करना।

दृष्टिकोण

- जल जीवन मिशन, राज्य योजनाओं एवं जिला खनिज फाउंडेशन निधियों का अभिसरण।
- ग्राम पंचायत विकास योजना में जल सुरक्षा योजना को शामिल करना।
- महिलाओं की भागीदारी के साथ ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को मजबूत करना।
- ऊर्जा निर्भरता कम करने हेतु सौर ऊर्जा आधारित प्रणालियों का उपयोग।
- जल संरक्षण एवं सुरक्षित जल उपयोग पर जागरूकता अभियान।

प्राप्त समर्थन

- जल जीवन मिशन एवं राज्य ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से वित्तीय सहयोग।
- जिला खनिज फाउंडेशन से अवसंरचना निर्माण सहायता।
- जिला प्रशासन से तकनीकी एवं रखरखाव सहयोग।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा निगरानी एवं जल गुणवत्ता परीक्षण में सक्रिय भागीदारी।

नवाचार

- ऊर्जा दक्ष एवं विश्वसनीय सेवा हेतु सौर द्वि-बिंदु जलापूर्ति प्रणाली।
- 50% महिला प्रतिनिधित्व वाली विकेंद्रीकृत जल शासन प्रणाली।
- प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा सामुदायिक जल गुणवत्ता परीक्षण।
- जल जीवन मिशन, जिला खनिज फाउंडेशन एवं राज्य निधियों का अभिसरण आधारित संसाधन प्रबंधन।
- ग्राम सभा में जल गुणवत्ता परीक्षण परिणामों का सार्वजनिक प्रदर्शन।

सततता के लिए रोडमैप

- भूजल पुनर्भरण एवं संरक्षण पहलों को मजबूत करना।
- ग्रे-वाटर प्रबंधन अवसंरचना का विस्तार।
- ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से जल बजट एवं मौसमी मांग मूल्यांकन को संस्थागत रूप देना।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी मजबूत करना।
- संचालन लागत कम करने हेतु सौर प्रणालियों का सतत उपयोग।

Water Sufficient Panchayat

PADUA

BLOCK PANCHAYAT: CHAMPUA
DISTRICT PANCHAYAT: KEONJHAR
STATE: ODISHA

3rd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 119300
- Total Population: 5,016
- Total Households: 1,265

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% Functional Household Tap Connections (FHTC) across all 1,265 households under Jal Jeevan Mission
- Created mega piped water supply schemes, 115 tube wells, 27 community tanks, and 3 solar dual-point systems
- Developed overhead reservoirs of 620 KL (Baliposi) and 290 KL (Nisagadia) with 60+ km pipeline network
- Ensured year-round reliable piped water supply, eliminating seasonal scarcity across all 7 villages
- Institutionalised water quality testing through trained SHG members and health workers using Field Test Kits
- Formed VWSCs with 50% women representation for decentralised water governance
- Promoted greywater management through soak pits and drainage systems
- Reduced water-borne diseases through regular monitoring and community awareness

Water treatment plant in Panchayat

CHALLENGES FACED

- Seasonal water scarcity and dependence on distant water sources
- High SC/ST population requiring special focus on inclusive and equitable coverage
- Need for extensive infrastructure across 7 dispersed villages
- Ensuring energy efficiency and reducing recurring operational costs

APPROACH TAKEN

- Leveraged convergence of JJM, State schemes, and District Mineral Foundation funds for universal tap connectivity
- Integrated water security planning into the Gram Panchayat Development Plan with Gram Sabha-led water budgeting
- Formed and strengthened VWSCs with women at the centre of monitoring and governance
- Deployed solar-powered systems to reduce energy dependency and ensure sustainability
- Conducted community awareness campaigns on water conservation and safe water use

SUPPORT RECEIVED

- Core funding through Jal Jeevan Mission and State rural water supply schemes
- Financial support from District Mineral Foundation for infrastructure creation
- Technical convergence support from district authorities for planning and maintenance
- Active participation of SHGs in monitoring, awareness, and community-led water quality testing

INNOVATIONS

- Solar dual-point water supply systems for energy-efficient and reliable service delivery
- VWSC-led decentralised water governance with 50% women representation
- Community-based FTK water quality testing by trained SHG members and health workers
- Convergence-based resource mobilisation integrating JJM, DMF, and State funds
- Transparent public sharing of water quality test results through Gram Sabha meetings

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthen source sustainability through groundwater recharge and protection initiatives
- Expand greywater management infrastructure through continued scheme convergence
- Institutionalise water budgeting and seasonal demand assessment through regular Gram Sabha meetings
- Reinforce community-led monitoring through VWSCs and periodic water quality testing shared publicly
- Sustain energy-efficient solar systems to minimise recurring operational costs

स्वच्छ एवं हरित पंचायत

एक स्वच्छ एवं हरित पंचायत वह है जो सुनिश्चित करती है:

- जैव विविधता का मानचित्रण एवं संरक्षण
- नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना एवं बढ़ावा देना

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- सभी परिवारों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तक 100% पहुंच एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देना
- जलाऊ लकड़ी के उपयोग में कमी लाना
- खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ+) स्थिति प्राप्त करना
- वनीकरण को बढ़ावा देना
- जैव विविधता रजिस्टर का संधारण, निगरानी एवं संरक्षण

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना
- पात्र लाभार्थियों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) उपलब्ध कराना
- बिजली का प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करना
- स्थानीय जल संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग
- वन, जल स्रोत एवं पवित्र उपवन सहित प्राकृतिक संसाधनों का सामुदायिक प्रबंधन
- ढलान वाले क्षेत्रों, सड़कों के किनारे एवं बंजर भूमि पर पौधारोपण
- जैविक खेती एवं सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना
- मत्स्य पालन हेतु सामुदायिक तालाबों को प्रोत्साहित करना
- प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु गठित स्थायी समितियों/कार्य समितियों को सशक्त बनाना
- एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाना

CLEAN AND GREEN PANCHAYAT

A CLEAN AND GREEN PANCHAYAT IS ONE WHICH ENSURES:

- Mapping and conservation of its biodiversity
- Adoption and promotion of renewable energy

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- 100 % access to renewable sources of energy to all households and promoting its usage
- Reducing use of firewood
- Achieving Open Defecation Free+ status
- Afforestation
- Maintenance of bio-diversity registers and its monitoring and conservation

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Promote use of solar energy
- Provide Individual House Hold Latrine (IHHL) to all eligible beneficiaries
- Efficient distribution of electricity
- Developing effective liquid and solid waste management system
- Harnessing local water resources
- Community-based management of natural resources including forests, water bodies and sacred groves.
- Planting of natural vegetation in high-slope areas, alongside roads and barren and other common lands
- Promote organic farming and sustainable fishing
- Encourage community ponds for fisheries
- Empower standing committee / working committee constituted for restoration of natural conservation
- Prohibit single-use plastic usage

स्वच्छ एवं हरित पंचायत

कावर्थाह नॉर्थ

ब्लॉक: जोल्नुअम
जिला: ममित
राज्य: मिजोरम

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 264555
- कुल जनसंख्या: 1225
- कुल परिवार: 281

मुख्य उपलब्धियाँ

- फलदार एवं स्थानीय प्रजातियों के पौधों की नर्सरी स्थापित, जिससे पौधारोपण एवं पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा मिला।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वृक्षारोपण, भूमि विकास, ट्रेंच निर्माण, टैरेस सुदृढ़ीकरण एवं चेक डैम जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य।
- सुपारी पत्तों से जैव-अवक्रमणीय प्लेट निर्माण, जिससे आजीविका एवं प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा मिला।
- अधिकांश परिवार स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) का उपयोग करते हैं, जिससे जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता कम हुई।
- लगभग सभी परिवारों में कार्यशील व्यक्तिगत घरेलू शौचालय उपलब्ध एवं नियमित उपयोग।
- 100% घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू।
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान स्थापित।
- ओडीएफ प्लस स्थिति सतत बनाए रखी गई।

चेक डैम का निर्माण

चुनौतियाँ

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वैज्ञानिक पृथक्करण एवं निस्तारण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता।
- स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण की सीमित व्यवस्था।
- एकमात्र निस्तारण स्थल पर बढ़ता दबाव।
- एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी अनुपालन की चुनौती।
- भारी वर्षा के कारण निरीक्षण दिवस पर नर्सरी का सत्यापन संभव नहीं हो सका।
- पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कचरा परिवहन एवं अवसंरचना विकास में कठिनाई।

दृष्टिकोण

- दस्तावेजों, भौतिक निरीक्षण एवं सामुदायिक संवाद के माध्यम से सभी दावों का सत्यापन।
- पीएआई द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की वास्तविक क्षेत्र परिस्थितियों के साथ क्रॉस-चेकिंग।
- मनरेगा कार्यों जैसे ट्रेंच, मिट्टी संरक्षण एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निरीक्षण।
- स्वच्छता व्यवहार का मूल्यांकन।
- कचरा पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण पर जागरूकता अभियान।
- सामुदायिक भागीदारी आधारित पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा।

प्राप्त समर्थन

- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों हेतु मनरेगा सहायता।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से पौध सामग्री।
- 15वें वित्त आयोग अनुदान से सार्वजनिक शौचालय निर्माण।
- मिजोरम सरकार के शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा कूड़ेदान उपलब्ध कराना।
- ग्राम परिषद, महिला समूहों एवं बच्चों की सक्रिय भागीदारी।
- एमजीएनआरईजीएस समर्थित कार्यों के माध्यम से स्वच्छता और आजीविका का समन्वय, जिससे रोजगार और पर्यावरणीय संपदा दोनों का सृजन होता है।

नवाचार

- प्लास्टिक बाय-बैक कार्यक्रम ख़ बच्चे प्लास्टिक कचरा एकत्र कर प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं।
- सुपारी पत्तों से पर्यावरण अनुकूल प्लेट निर्माण ख़ महिलाओं द्वारा संचालित पहल।
- मनरेगा के अंतर्गत टैरेस सुदृढ़ीकरण एवं स्टैगर्ड ट्रेंच निर्माण।
- चरणबद्ध खाइयाँ: भूजल पुनर्भरण में सहायता करने और कटाव को कम करने वाली एक प्रभावी जल संरक्षण विधि।
- कृषि भूमि पर चेक डैम निर्माण।

सततता के लिए रोडमैप

- स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण को मजबूत करना।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का विस्तार।
- प्लास्टिक वापसी कार्यक्रम का विस्तार।
- पुनर्चक्रण एवं कचरा न्यूनिकरण को बढ़ावा।
- सौर ऊर्जा आधारित पहलों का विस्तार।
- मिट्टी की स्थिरता और हरियाली बढ़ाने के लिए नर्सरी के पौधों का उपयोग करके वृक्षारोपण प्रयासों को बढ़ावा ।
- जल संरक्षण में सुधार के लिए नालियों, बांधों की सुरक्षा और सीढ़ीदार खेतों को मजबूत करने जैसे जल संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) कार्यों को जारी रखना।

Clean & Green Panchayat

KAWRTHAH NORTH

BLOCK: ZAWLNUAM
DISTRICT: MAMIT
STATE: MIZORAM

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 264555
- Total Population: 1225
- Total Households: 281

KEY ACHIEVEMENTS

- Operational nursery with saplings of fruit-bearing and indigenous tree species supporting plantation drives and ecological restoration.
- Strong Natural Resource Management initiatives under MGNREGS, including plantation, land development, staggered trenches, terrace strengthening, and check dams.
- Preparation of areca nut sheath biodegradable plates, providing income generation and promoting eco-friendly alternatives to plastics.
- High percentage of households using clean cooking fuel (LPG), reducing dependence on firewood and preventing deforestation.
- Nearly universal coverage of Individual Household Latrines (IHHL); toilets functional and in regular use, contributing to sustained ODF Plus status.
- 100% door-to-door waste collection system ensuring clean streets and systematic waste handling.
- Garbage bins strategically placed near roads and public spaces for easy and accessible waste disposal.
- ODF Plus status sustained with clean public spaces and strong sanitation behaviour across households.

Construction of check dams

CHALLENGES FACED

- Solid waste management system exists but requires more structured segregation, collection routes, and disposal mechanisms.
- Limited availability of segregation at source, requiring continuous behavioural change efforts.
- Single disposal site creating pressure on long-term waste management sustainability.
- Enforcement of single-use plastic ban still needs strengthening for complete compliance.
- Heavy rainfall prevented verification of the nursery on the day of visit, though documentary evidence supports its functioning.
- Hilly terrain creates natural difficulty in waste transportation and infrastructure development.

APPROACH TAKEN

- Verification of all claims through documentation review, physical inspection, and discussion with Village Council representatives and community members.
- Cross-checking of PAI-submitted data with actual field conditions.
- Inspections of MGNREGS works including trenching, soil conservation, plantation, and water retention structures.
- Assessment of sanitation behaviour through household interactions and public area checks.
- Continuous awareness campaigns and IEC activities on waste segregation, recycling, and cleanliness practices.
- Promotion of community-led environmental governance, ensuring participation from households, children, and local groups.

SUPPORT RECEIVED

- MGNREGS for NRM and watershed works.
- Environment, Forest & Climate Change Department for nursery saplings.
- 15th Finance Commission Grants for public toilet construction.
- UD&PA Department, Govt. of Mizoram for garbage bins.
- Convergence of sanitation and livelihood through MGNREGS-supported works, creating both employment and environmental assets.
- Community participation through Village Council, women's groups, and children's involvement in environmental activities.

INNOVATIONS

- Plastic Buy-Back Programme: Children collect plastic waste, receive incentives, and promote recycling and environmental responsibility.
- Eco-friendly Areca nut Sheath Plates: Women-led initiative producing biodegradable alternatives, reducing plastic dependency and generating livelihood.
- Terrace Strengthening under MGNREGS: Prevents water runoff, improves water retention, and reduces soil erosion.
- Staggered Trenches: Effective water conservation method aiding groundwater recharge and reducing erosion.
- Check Dams: Built on private agricultural lands to conserve soil, recharge groundwater, and improve productivity.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthen solid waste segregation at source and develop systematic disposal mechanisms, including additional infrastructure.
- Expand and operationalise the Solid Waste Management Centre for scientific waste processing.
- Scale up the plastic buy-back programme to ensure long-term behavioural change.
- Promote reduction in waste generation and encourage recycling practices.
- Expand renewable energy initiatives including additional solar lighting and community solar assets.
- Increase plantation efforts using nursery saplings to improve soil stability and green cover.
- Continue NRM works such as trenches, check dams, and terrace strengthening for improved water conservation

स्वच्छ एवं हरित पंचायत

जुमरमुर

ब्लॉक / मंडल पंचायत: कथिआटोली
जिला पंचायत: नगांव
राज्य: असम

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 302425
- कुल जनसंख्या: 14,000
- कुल परिवार: 4,500

2nd PRIZE

द्वितीय पुरस्कार-संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- अधिकांश परिवारों में कार्यशील शौचालय उपलब्ध।
- सड़कें एवं सार्वजनिक स्थान स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित।
- ग्रामवासियों, विद्यालयों एवं महिला समूहों की सहभागिता से वृक्षारोपण अभियान।
- ग्राम वन एवं सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण।
- प्लास्टिक उपयोग में कमी हेतु प्रयास।
- कई वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में वृद्धि।
- मेगा सोलर परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं का प्रभावी अभिसरण।
- मेगा सोलर परियोजना से स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति।

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना

चुनौतियाँ

- घर-घर कचरा संग्रहण अभी पूर्ण रूप से नियमित नहीं।
- घरेलू स्तर पर कचरा पृथक्करण स्पष्ट नहीं।
- कंपोस्टिंग एवं पुनर्चक्रण गतिविधियां सीमित।
- कचरा संग्रहण शेड का पूर्ण उपयोग नहीं।
- दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण।
- वैज्ञानिक कचरा निस्तारण व्यवस्था की आवश्यकता।
- पेड़ों, ग्राम भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता।

दृष्टिकोण

- वार्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत कचरा संग्रहण शेड निर्माण।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता अभियान।
- ग्राम सभा के माध्यम से सहभागितापूर्ण चर्चा।
- जल निकासी व्यवस्था का रखरखाव।

प्राप्त समर्थन

- डेटा, योजना और कार्यान्वयन के लिए लाइन विभागों से समर्थन।
- विभिन्न विभागों से योजना एवं क्रियान्वयन सहयोग।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से स्वच्छता समर्थन।
- मनरेगा से पौधारोपण एवं पर्यावरणीय कार्य।
- जल जीवन मिशन से पेयजल सुविधा।
- नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं का सहयोग।

नवाचार

- मेगा सोलर परियोजना द्वारा ऊर्जा उत्पादन।
- घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा उपयोग।
- विकेन्द्रीकृत कचरा संग्रहण व्यवस्था।
- सामुदायिक आधारित वृक्ष एवं वन संरक्षण मॉडल।
- विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का मॉडल।

सततता के लिए रोडमैप

- नियमित घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करना।
- घरेलू स्तर पर कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देना।
- कंपोस्टिंग एवं पुनर्चक्रण तंत्र विकसित करना।
- मौजूदा अपशिष्ट संग्रहण शेडों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।
- सौर ऊर्जा का विस्तार।
- वृक्षारोपण अभियान, जल निकायों का रखरखाव और ग्राम साझा भूमि की सुरक्षा जारी रखना ।

Clean & Green Panchayat

JUMARMUR

BLOCK / MANDAL PANCHAYAT: KATHIATOLI
DISTRICT PANCHAYAT: NAGAON
STATE: ASSAM

2nd PRIZE

Second Prize-Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 302425
- Total Population: 14,000
- Total Households: 4,500

KEY ACHIEVEMENTS

- Most households have functional toilet facilities, significantly improving sanitation, dignity, and public health.
- Streets, internal roads, and public places are clean and well-maintained through regular community efforts.
- Plantation drives conducted with active participation of villagers, schools, youth groups, and women's groups, increasing green cover.
- Village forests, common lands, and community resources protected and maintained.
- Measures taken to reduce plastic usage; no significant plastic waste observed in village surroundings.
- Door-to-door waste collection system initiated in multiple wards with decentralized waste collection sheds.
- Community awareness on cleanliness and hygienic behaviour has improved significantly.
- Effective convergence of government schemes including Mega Solar Project, SBM-G, MGNREGA, PMAY-G, Jal Jeevan Mission (JJM), PM-KUSUM type renewable initiatives, and social security schemes.
- Mega Solar Project established to support renewable energy for nearby factories and local needs; some households also using solar power.

Solar pumps installation through PM-KUSUM Yojana

CHALLENGES FACED

- Door-to-door waste collection not yet fully regular as per household feedback.
- Waste segregation practices not clearly evident at household level.
- Composting and recycling initiatives not visibly operational.
- Garbage collection sheds exist but are not fully utilized.
- Sustaining long-term behavioural change in waste management and sanitation practices requires continuous effort.
- Need for stronger prevention of plastic littering and scientific disposal systems.
- Protection of trees, village commons, and natural resources requires ongoing vigilance.

APPROACH TAKEN

- Construction of ward-wise decentralized waste collection sheds (each serving ~250 households).
- Promotion of renewable energy through Mega Solar Project and household solar adoption.
- Community participation in cleanliness drives, plantation campaigns, and public awareness activities.
- Door-to-door awareness campaigns and Gram Sabha discussions on sanitation, waste management, and environmental responsibility.
- Drainage maintenance in one habitation with underground drainage system.
- Regular verification of sanitation, waste management, plantation, and environmental awareness records.

SUPPORT RECEIVED

- Support from Line Departments for data, planning, and implementation.
- Convergence of multiple government schemes for holistic development.
- Swachh Bharat Mission (Gramin) support for sanitation infrastructure and awareness.
- MGNREGA support for plantation, drainage, land development, and environmental works.
- Jal Jeevan Mission support for drinking water access.
- Renewable energy support through solar-related initiatives.

INNOVATIONS

- Mega Solar Project for power generation supporting local factories and community energy needs.
- Household-level solar power systems adopted by several families, demonstrating renewable energy awareness.
- Ward-wise decentralized waste collection infrastructure despite operational gaps.
- Community-led plantation and forest protection model enhancing ecological sustainability.
- Scheme convergence model combining sanitation, housing, water, livelihood, and clean energy interventions.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthen regular and universal door-to-door waste collection.
- Operationalize waste segregation at household level through sustained IEC campaigns.
- Establish composting pits, organic waste management, and recycling mechanisms.
- Ensure full utilization of existing waste collection sheds.
- Continue plantation drives, water body maintenance, and protection of village commons.
- Expand solar energy adoption to more households and public institutions.

स्वच्छ एवं हरित पंचायत

हटिबंधा

ब्लॉक पंचायत: लाठीकाटा
जिला पंचायत: सुंदरगढ़
राज्य: ओडिशा

2nd PRIZE

द्वितीय पुरस्कार-संयुक्त

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 121681
- कुल जनसंख्या: 11,303
- कुल परिवार: 1,791

मुख्य उपलब्धियाँ

- 100% ओडीएफ प्लस स्थिति।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित ख्र घर-घर संग्रहण, पृथक्करण, कंपोस्टिंग एवं पुनर्चक्रण।
- प्लास्टिक मुक्त पंचायत हेतु ग्राम सभा संकल्प एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग।
- 12,000 से अधिक पौधारोपण एवं मियावाकी वन विकसित।
- 62,000 पौधों की स्थायी नर्सरी।
- सौर स्ट्रीट लाइट, सौर पंप एवं सौर ऊर्जा आधारित सार्वजनिक संस्थान।
- "अमा सुंदरगढ़ ख्र स्वच्छ सुंदरगढ़ ऐप" के माध्यम से डिजिटल निगरानी।
- ग्रे वाटर प्रबंधन एवं वर्षा जल संचयन।

बैटरी चालित वाहनों द्वारा "स्वच्छ साथी" के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण

चुनौतियाँ

- प्रारंभिक चरण में स्वच्छता एवं कचरा पृथक्करण के प्रति प्रतिरोध।
- दुर्गम एवं बिखरी बस्तियों में सेवा वितरण की चुनौती।
- प्रारंभिक चरणों में वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सीमित तकनीकी जागरूकता।
- बढ़ती आबादी के कारण अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का विस्तार आवश्यक।
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के और विस्तार की आवश्यकता।
- प्रारंभिक कार्यान्वयन चरण के दौरान वित्तीय बाधाएँ।

दृष्टिकोण

- स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा एवं जैव विविधता संरक्षण का समग्र दृष्टिकोण।
- ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी।
- "स्वच्छ साथी" द्वारा बैटरी चालित वाहनों से घर-घर कचरा संग्रहण।
- स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण एवं कंपोस्टिंग।
- व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी के लिए जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण।
- भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए मियावाकी तकनीक और ष्एक पेड़ लगाओ और पानी बचाओष् पहल सहित वृक्षारोपण अभियान।
- डिजिटल ट्रैकिंग एवं शिकायत निवारण प्रणाली।

प्राप्त समर्थन

- मनरेगा, प्रधानमंत्री कुसुम, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण आदि योजनाओं का अभिसरण।
- जिला प्रशासन एवं सरकारी विभागों का सहयोग।
- सुंदरगढ़ जिला प्रशासन का सहयोग, जिसमें सीडीओ और बीडीओ का नेतृत्व शामिल है।
- ग्राम सभा के प्रस्ताव और प्लास्टिक प्रतिबंध एवं स्वच्छता प्रथाओं के लिए सामुदायिक प्रवर्तन तंत्र।
- सरकारी कार्यक्रमों और सीएसआर पहलों के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।
- स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी।

नवाचार

- क्यूआर आधारित कचरा ट्रैकिंग प्रणाली।
- "प्लास्टिक रिटर्न डे" पहल।
- "क्लीन जीपी इंडेक्स" प्रतियोगिता।
- "वेस्ट टू वेल्थ" मॉडल।
- पुनर्चक्रित सामग्री से स्वयं सहायता समूह आधारित हरित उद्यम।

सततता के लिए रोडमैप

- अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार।
- सौर ऊर्जा प्रणालियों का विस्तार।
- प्लास्टिक मुक्त अभियान को मजबूत करना।
- क्यूआर-आधारित ट्रैकिंग और डेटा-आधारित निर्णय लेने सहित डिजिटल निगरानी प्रणालियों को बेहतर।
- "अपशिष्ट से धन" और स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित हरित उद्यम मॉडल को अधिक क्षेत्रों में लागू।

Clean & Green Panchayat

HATIBANDHA

BLOCK PANCHAYAT: LATHIKATA
DISTRICT PANCHAYAT: SUNDARGARH
STATE: ODISHA

2nd PRIZE

Second Prize-Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 121681
- Total Population: 11,303
- Total Households: 1,791

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% ODF Plus status with universal toilet coverage and sustained behavioural change.
- Established a comprehensive solid waste management system including door-to-door collection, segregation sheds, composting, and linkage to Material Recovery Facility (MRF) for recycling.
- Plastic-free Panchayat through Gram Sabha resolutions, community enforcement, and promotion of eco-friendly alternatives like leaf plates and steel utensils.
- Plantation of over 12,000 trees across community lands and roadsides, including Miyawaki forest patches and biodiversity enhancement initiatives.
- Permanent nursery with 62,000 saplings of 168 varieties (including medicinal plants and Rakt Chandan), supporting plantation and livelihoods.
- Solar energy infrastructure including solar streetlights, solar pumps, and adoption of solar power in public institutions under schemes like PM Kusum and PM Suryaghar.
- Digital monitoring system through "Ama Sundargarh – Swachha Sundargarh App" for QR-based waste tracking, route monitoring, and grievance redressal.
- Functional liquid waste management through greywater reuse, leach pits, recharge pits, and rainwater harvesting systems.

Door-to-door waste collection by "Swachh Sathis" using battery-operated vehicles

CHALLENGES FACED

- Initial resistance to behavioural change in sanitation and waste segregation practices.
- Difficult terrain and scattered habitations affecting service delivery.
- Limited technical awareness on scientific waste management in early stages.
- Increasing waste volume due to population growth requiring scaling of infrastructure.
- Need for further expansion of renewable energy systems.
- Financial constraints during initial implementation phase.

APPROACH TAKEN

- Adoption of a holistic and integrated approach combining sanitation, waste management, renewable energy, and biodiversity conservation.
- Segregation of waste at source, composting of organic waste, and recycling through MRF linkage.
- Awareness campaigns and trainings to promote behavioural change and community ownership.
- Plantation campaigns including Miyawaki technique and "Plant a Tree & Save Water" initiative to enhance groundwater recharge.
- Use of digital tools (mobile app and QR-based tracking) for transparency, monitoring, and grievance redressal.

SUPPORT RECEIVED

- Strong convergence among various government departments and schemes including MGNREGS, PM Kusum, SBM-G, and others.
- Support from Sundargarh District Administration, including leadership of CDO and BDO.
- Gram Sabha resolutions and community enforcement mechanisms for plastic ban and sanitation practices.
- Financial and technical support through government programmes and CSR initiatives.
- Active involvement of Self-Help Groups in waste management, green enterprises, and livelihood generation.

INNOVATIONS

- QR-based waste tracking system for transparent and efficient waste collection monitoring.
- Plastic Return Day initiative to reduce plastic pollution through community participation.
- Clean GP Index – monthly competition encouraging inter-ward performance improvement.
- Waste to Wealth model converting waste into compost and recyclable products.
- SHG-led green enterprises producing handicrafts from recycled materials.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Expand waste processing capacity to manage increasing waste volume effectively.
- Scale up renewable energy initiatives including solar installations in households and public spaces.
- Continue plantation drives, Miyawaki forests, and biodiversity conservation efforts.
- Strengthen waste segregation and recycling systems across all wards.
- Sustain plastic-free initiatives through continuous awareness and enforcement.
- Enhance digital monitoring systems including QR-based tracking and data-driven decision-making.
- Replicate "Waste to Wealth" and SHG-led green enterprise models across more areas.

स्वच्छ एवं हरित पंचायत

सरडीह

ब्लॉक पंचायत: बगीचा
जिला पंचायत: जशपुर
राज्य: छत्तीसगढ़

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 125694
- कुल जनसंख्या: 2,202
- कुल परिवार: 454

3rd PRIZE

द्वितीय पुरस्कार-संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- 100% ओडीएफ प्लस स्थिति।
- सभी परिवारों में कचरा पृथक्करण व्यवस्था।
- साइकिल रिक्शा आधारित घर-घर कचरा संग्रहण।
- एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध।
- मनरेगा के अंतर्गत व्यापक वृक्षारोपण।
- 11 सौर ऊर्जा संचालित एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित।
- पारंपरिक संरक्षण पद्धतियों के माध्यम से ग्राम वनों का संरक्षण और लघु वन उत्पादों का सतत उपयोग।
- 109 किसानों हेतु सौर सिंचाई पंप।
- ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा।

सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप

चुनौतियाँ

- दूरस्थ आदिवासी एवं वन क्षेत्र में सेवा वितरण कठिन।
- प्रारंभिक चरण में स्वच्छता के प्रति जागरूकता कम।
- पूर्वकाल में सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अभाव।
- सीमित वित्तीय एवं तकनीकी संसाधन।
- कुछ परिवार लगभग 131 परिवार अभी भी एलपीजी से वंचित।
- प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर एमजीएनआरईजीएस का व्यय पीएआई स्कोरकार्ड में पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं।
- परिवारों द्वारा जैव अपघटनीय अपशिष्ट का व्यक्तिगत रूप से प्रबंधन के कारण केंद्रीकृत अपशिष्ट संग्रहण की मात्रा कम।

दृष्टिकोण

- ग्राम सभा आधारित निर्णय एवं सामुदायिक भागीदारी।
- घर-घर जाकर अजैविक अपशिष्ट का संग्रह,
- घर-घर जागरूकता अभियान।
- जैविक एवं अजैविक कचरे का पृथक्करण।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा कचरा प्रबंधन।
- साइकिल रिक्शा, पृथक्करण शेड और अपशिष्ट संग्रहण सुविधाओं सहित बुनियादी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का विकास।
- एसबीएम (जी), एमजीएनआरईजीएस और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों जैसी योजनाओं का समन्वय।

प्राप्त समर्थन

- जनपद कार्यालय द्वारा मनरेगा एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सहयोग।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), प्रधानमंत्री कुसुम एवं सिंचाई योजनाओं का अभिसरण।

नवाचार

- सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप।
- ड्रिप सिंचाई प्रणाली।
- घरेलू स्तर पर जैविक कचरा प्रबंधन।
- रसोई बागवानी हेतु ग्रे वाटर पुन: उपयोग।
- मनरेगा आधारित लकड़ी उत्पादन वृक्षारोपण।

सततता के लिए रोडमैप

- शेष परिवारों को एलपीजी सुविधा उपलब्ध कराना।
- अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना मजबूत करना।
- वृक्षारोपण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जारी रखना।
- पीएआई पोर्टल में एमजीएनआरईजीएस व्यय का सटीक विवरण सुनिश्चित।
- वृक्षारोपण अभियान और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों को जारी रखना ।
- नियमित निगरानी और जागरूकता अभियानों के माध्यम से ओडीएफ प्लस स्थिति को बनाए रखना ।
- निरंतर प्रवर्तन और सूचना एवं संचार शिक्षा (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त स्थिति।
- सौर सिंचाई एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार।

Clean & Green Panchayat

SARDIH

BLOCK PANCHAYAT: BAGICHA
DISTRICT PANCHAYAT: JASHPUR
STATE: CHHATTISGARH

3rd PRIZE

Third Prize-Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 125694
- Total Population: 2,202 (Male: 1,078, Female: 1,124)
- Total Households: 454

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved and sustained 100% ODF Plus status with all 454 households using sanitary latrines.
- 100% household-level waste segregation implemented, supported by compost pits for biodegradable waste.
- Functional solid waste management system with door-to-door collection using cycle-rickshaws and segregation at SWM site.
- Single-use plastic banned through Gram Panchayat and Gram Sabha resolutions, reinforced by wall writings and awareness campaigns.
- Extensive plantation drives under MGNREGS, including timber-producing trees, enhancing green cover and long-term economic benefits.
- Protection of village forests and sustainable use of minor forest produce through traditional conservation practices.
- Installation of 11 solar-powered LED street lights across the Panchayat.
- Solar-powered irrigation pumps installed for 109 farmers, covering approximately 300 acres of agricultural land.
- Promotion of drip irrigation systems with government subsidy (~₹30,000 per farmer), improving water efficiency.

Solar-powered irrigation pumps

CHALLENGES FACED

- Remote tribal and forest terrain with scattered habitations affecting service delivery.
- Initial resistance to sanitation practices and low awareness due to low literacy levels.
- Lack of structured waste management system in earlier years.
- Limited financial and technical resources.
- Around 131 households still not covered under LPG for clean cooking fuel.
- MGNREGS expenditure on Natural Resource Management not fully reflected in PAI scorecard.
- Low volume of centralized waste collection as households manage biodegradable waste individually.

APPROACH TAKEN

- Strong Gram Sabha-based decision-making ensuring community ownership and participation.
- Door-to-door awareness campaigns and behaviour change communication for sanitation and waste management.
- Door-to-door collection of non-biodegradable waste, while biodegradable waste is managed at household level through composting.
- Waste segregation carried out by SHG members at the SWM site.
- Development of basic SWM infrastructure including cycle-rickshaws, segregation shed, and waste collection facilities.
- Convergence of schemes such as SBM(G), MGNREGS, and renewable energy programmes.

SUPPORT RECEIVED

- Support from Janpad (Block) Office for MGNREGS implementation and Natural Resource Management works.
- Convergence of government schemes including SBM(G), PM-KUSUM, and irrigation subsidy programmes.
- Gram Panchayat and Gram Sabha resolutions for sanitation, plastic ban, and environmental protection.
- Village Water & Sanitation Committee (VWSC) support for sustaining ODF Plus status.
- Government subsidy (~₹30,000 per farmer) for drip irrigation systems.

INNOVATIONS

- Solar-powered irrigation pumps enabling cultivation across 300 acres and promoting multi-cropping.
- Drip irrigation systems improving water efficiency and reducing dependence on conventional energy sources.
- Household-level biodegradable waste management minimizing load on centralized systems.
- Greywater reuse integrated with kitchen gardening for sustainable livelihood support.
- Timber-based plantation under MGNREGS combining ecological and economic benefits.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Expand LPG coverage to remaining households for clean cooking fuel.
- Strengthen waste management infrastructure as waste volume increases.
- Ensure accurate reflection of MGNREGS expenditure in PAI portal.
- Continue plantation drives and natural resource management activities.
- Sustain ODF Plus status through regular monitoring and awareness campaigns.
- Maintain plastic-free status through continued enforcement and IEC activities.
- Expand solar irrigation and renewable energy usage among farmers.

स्वच्छ एवं हरित पंचायत

लोहारडी

ब्लॉक पंचायत: बल्ह
जिला पंचायत: मंडी
राज्य: हिमाचल प्रदेश

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 298605
- कुल जनसंख्या: 1,473
- कुल परिवार: 416

3rd PRIZE

द्वितीय पुरस्कार-संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- 100% घरेलू शौचालय कवरेज एवं सतत ओडीएफ स्थिति।
- सभी परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग।
- 100% सौर ऊर्जा संचालित एलईडी स्ट्रीट लाइट।
- घर-घर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण व्यवस्था।
- कंपोस्ट गड्ढों एवं जैविक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा।
- वृक्षारोपण अभियान एवं अमृत सरोवर निर्माण।
- सिंचाई हेतु सौर जल लिफ्ट प्रणाली।
- एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक।

सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप

चुनौतियाँ

- प्रारंभिक चरण में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति कम जागरूकता।
- सीमित वित्तीय एवं तकनीकी संसाधन।
- कचरा परिवहन हेतु ब्लॉक स्तर के वाहन पर निर्भरता।

दृष्टिकोण

- ग्राम सभा एवं वार्ड बैठकों के माध्यम से सहभागितापूर्ण योजना।
- स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान।
- महिला मंडलों द्वारा प्रारंभिक कचरा संग्रहण मॉडल।
- स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण।
- घरेलू एवं सामुदायिक कंपोस्टिंग को बढ़ावा।

प्राप्त समर्थन

- मनरेगा, 15वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं जलागम विकास कार्यक्रमों से सहायता।
- वन विभाग एवं समुदाय का सहयोग।

नवाचार

- सौर ऊर्जा संचालित जल लिफ्ट प्रणाली।
- 100% सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था।
- महिला मंडलों द्वारा सामुदायिक कचरा संग्रहण मॉडल।
- घरेलू स्तर पर कंपोस्टिंग।
- ग्रे वाटर पुनः उपयोग एवं भूजल पुनर्भरण।

सततता के लिए रोडमैप

- स्वच्छता एवं पर्यावरणीय गतिविधियों की निगरानी मजबूत करना।
- कचरा संग्रहण एवं परिवहन व्यवस्था में सुधार।
- प्लास्टिक उन्मूलन एवं स्वच्छता जागरूकता जारी रखना।
- जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार।

Clean & Green Panchayat

LOHARDI

BLOCK PANCHAYAT: BALH
DISTRICT PANCHAYAT: MANDI
STATE: HIMACHAL PRADESH

3rd PRIZE

Third Prize-Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 298605
- Total Population: 1,473
- Total Households: 416

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% household toilet coverage with sustained ODF status; no open defecation observed.
- Universal adoption of clean cooking fuel (LPG) under PMUY and related schemes.
- 100% solar-powered LED street lighting ensuring energy efficiency and reduced carbon footprint.
- Functional door-to-door waste collection system with designated sanitation worker and segregation practices.
- Segregation shed established; waste collected and periodically transported to Block-level facility.
- Compost pits and organic waste management practices adopted at household level for agricultural use.
- Regular plantation drives conducted along roadsides and common lands with support from Forest Department and community groups.
- Construction of Amrit Sarovar and development of irrigation channels (kuhls) under watershed programmes.
- Solar-powered water lifting system supporting irrigation and horticulture.
- Single-use plastic discouraged through Gram Sabha resolutions, awareness campaigns, and adoption of reusable alternatives.

One of the toilets in the GP

CHALLENGES FACED

- Initial lack of public awareness regarding sanitation, waste management, and environmental practices.
- Open dumping of waste and behavioural resistance to waste segregation in early stages.
- Limited financial and technical resources, especially after recent formation of Panchayat.
- Dependence on Block-level vehicle for waste transportation, requiring interim storage arrangements.
- Door-to-door waste collection still evolving in some hamlets.
- Behavioural change required for greywater management and sustained waste segregation practices.

APPROACH TAKEN

- Adoption of a participatory and inclusive approach through Gram Sabha and ward-level meetings.
- Door-to-door awareness campaigns, cleanliness drives, school-based IEC activities, and community interactions.
- Initial voluntary waste collection by Mahila Mandals, later institutionalized with a Panchayat-supported sanitation worker.
- Waste segregation at source into biodegradable and non-biodegradable categories.
- Promotion of composting at household and community levels for sustainable waste management.
- Installation of solar-powered infrastructure for energy efficiency and environmental sustainability.

SUPPORT RECEIVED

- Financial and technical support from MGNREGA, 15th Finance Commission, Swachh Bharat Mission (SBM), PMUY, PMKSY, and Watershed Development programmes.
- Support from Forest Department for plantation activities.
- Block-level support for waste collection and transportation.
- Continuous guidance from Block, District, and State authorities.
- Active involvement of Mahila Mandals, SHGs, and community members.
- Community contribution through voluntary land donation for Panchayat infrastructure.

INNOVATIONS

- Solar-powered water lifting system utilizing natural mountain water for irrigation and horticulture.
- 100% solar-powered LED street lighting ensuring sustainable and energy-efficient rural infrastructure.
- Community-led waste collection model initiated by Mahila Mandals and later institutionalized.
- Household-level composting reducing burden on centralized waste management systems.
- Soak pits and greywater reuse integrated with agriculture and groundwater recharge.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthen documentation and monitoring of sanitation and environmental activities.
- Improve frequency and efficiency of waste collection and transportation.
- Continue awareness programmes on waste segregation, plastic reduction, and sanitation.
- Sustain ODF status through regular monitoring and community engagement.
- Expand plantation drives and maintain green cover
- Promote water conservation through expansion of irrigation channels and water harvesting systems.

आत्मनिर्भर अवसंरचना

युक्त पंचायत

एक आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत वह है जो सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं किफायती आवास तथा बुनियादी सेवाओं एवं संबंधित अवसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- पक्की सड़क एवं स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था
- 100% पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना
- 100% परिवारों में शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग सुनिश्चित करना
- सभी स्थानों पर उचित जल निकासी व्यवस्था विकसित करना
- 100% परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना
- सभी परिवारों को जल एवं स्वच्छता परिसंपत्तियों के उपयोग एवं प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर शिक्षित करना

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों का निर्माण एवं रखरखाव तथा शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था
- बंद एवं ढंकी हुई नालियों का निर्माण कर सीवेज प्रणाली विकसित करना
- उपकेंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करना
- बस स्टैंड एवं प्रमुख गांवों/सड़कों से संपर्क सुनिश्चित करना
- ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करना
- सेवा सर्वेक्षण के माध्यम से अवसंरचना की आवश्यकता का आकलन करना
- पंचायत परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु सामुदायिक समितियों का गठन
- खाना पकाने, प्रकाश, सिंचाई एवं घरेलू एवं व्यावसायिक गतिविधियों हेतु ऊर्जा आवश्यकताओं का आ. कलन करना

SELF-SUFFICIENT
INFRASTRUCTURE IN PANCHAYAT

A Panchayat with Self-Sufficient Infrastructure is one which ensures access to adequate, safe and affordable housing and basic services and related infrastructure for all.

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Provision of pucca roads and street lights
- Availability of housing to 100% eligible families
- Availability and usage of toilets in 100%households
- Provision of proper drainage at all locations
- Availability of clean drinking water to 100% households
- Educate 100% households on key aspects of utilization and management of water and sanitation assets

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Construction and maintenance of Gram Panchayat Bhawan, Anganwadi, School and provision of toilets and drinking water
- Developing sewage system by constructing closed and covered drains
- Ensuring availability of sub-centres and primary health centres with recommended medical facilities (beds, equipments etc.)
- Ensuring connectivity to bus shelter & major villages / roads
- Ensuring computer and internet facility in Gram Panchayat Bhawan
- Assess the need for infrastructure through service surveys
- Formation / constitution of committees with community members for management of Panchayat properties
- Assess needs of energy for cooking, heating, lighting, irrigation, household food processing, industries, commercial establishments like shops and hotels etc.

आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत

मेलुकावु

ब्लॉक पंचायत: एराट्टुपेट्टा
जिला पंचायत: कोट्टायम
राज्य: केरल

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 221364
- कुल जनसंख्या: 11,476
- कुल परिवार: 4,705

मुख्य उपलब्धियाँ

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध।
- सीसीटीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर एवं बैठक कक्ष सहित पंचायत भवन का निर्माण।
- शौचालय, पेयजल एवं बिजली सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना।
- इंटरनेट एवं ऑनलाइन सेवाओं सहित कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना।
- 100% स्वच्छता कवरेज एवं ओडीएफ प्लस स्थिति प्राप्त।
- जल शोधन संयंत्र एवं अमृत सरोवर जैसे जल संरक्षण परियोजनाओं का विकास।
- पंचायत में एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना।
- चक्रवात एवं खारे पानी के प्रभाव को कम करने हेतु जैव सुरक्षा पट्टी एवं पौधारोपण।
- क्यूआर कोड, व्हाट्सऐप समूह एवं डिजिटल प्रमाणपत्रों के माध्यम से डिजिटल शासन।

पंचायत भवन

चुनौतियाँ

- बड़े अवसंरचना परियोजनाओं हेतु सीमित वित्तीय संसाधन।
- पहाड़ी एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण भौगोलिक चुनौतियां।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी।
- सड़क एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव।
- आपदा तैयारी एवं लचीलापन सुनिश्चित करना।

दृष्टिकोण

- सहभागी ग्राम सभा बैठकों के माध्यम से समावेशी योजना निर्माण।
- समय पर मरम्मत एवं परिसंपत्ति प्रबंधन पर ध्यान।
- केंद्र एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण।
- जागरूकता अभियान एवं स्वच्छता गतिविधियों को बढ़ावा।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सऐप समूह एवं क्यूआर कोड का उपयोग।
- संवेदनशील क्षेत्रों में जैव सुरक्षा पट्टी विकसित करना।

प्राप्त समर्थन

- जल जीवन मिशन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन एवं 15वें वित्त आयोग से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।
- सरकारी विभागों से तकनीकी मार्गदर्शन।
- डिजिटल शासन एवं आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण।
- स्वयं सहायता समूहों एवं समुदाय की सहभागिता।

नवाचार

- क्यूआर कोड एवं ऑनलाइन प्रमाणपत्र आधारित डिजिटल शासन।
- वर्मी-कंपोस्टिंग एवं प्लास्टिक प्रतिबंध सहित पूर्ण स्वच्छता मॉडल।
- जैव सुरक्षा पट्टी एवं पौधारोपण।
- सभी सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन।
- ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सौर ऊर्जा आधारित सुविधाएं।
- सामुदायिक सहभागिता आधारित इको-टूरिज्म विकास।

सततता के लिए रोडमैप

- जल, स्वच्छता एवं सड़क अवसंरचना का नियमित रखरखाव।
- इको-टूरिज्म एवं सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा।
- आपदा प्रबंधन एवं लचीले अवसंरचना को मजबूत करना।
- डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
- डिजिटल निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र को संस्थागत बनाना।
- वर्षा जल संचयन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

Self- Sufficient Infrastructure in Panchayat

MELUKAVU

BLOCK PANCHAYAT ERATTUPETTA
DISTRICT PANCHAYAT KOTTAYA
KERALA

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 221364
- Total Population: 11,476
- Total Households: 4,705

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% household coverage under Jal Jeevan Mission, with many households connected through pipelines and water treatment plants.
- Constructed a Panchayat Bhawan, equipped with CCTV, internet, computers, and meeting halls.
- Established a Community Health Centre (CHC) with proper infrastructure, including toilets, water, and electricity.
- Developed a well-structured Common Service Centre (CSC) with internet, computers, and online service facilities.
- Achieved 100% sanitation coverage, declared ODF Plus, with effective waste segregation, collection, and vermi-composting.
- Developed multiple water projects, including water treatment plants and natural reservoirs like Amrit Sarovar.
- Installed LED street lights across the Panchayat for energy efficiency.
- Promoted eco-sensitive plantation and bio-shield development to mitigate cyclone impact and saltwater intrusion.
- Implemented digital governance via digital certificates, QR codes, WhatsApp groups, and grievance redressal systems.

Panchayat Bhawan

CHALLENGES FACED

- Limited financial resources for large infrastructure projects.
- Geographical vulnerability due to being in a hilly and flood-prone area.
- Internet connectivity gaps affecting digital service delivery.
- Maintenance of roads and public facilities.
- Ensuring disaster resilience and preparedness.

APPROACH TAKEN

- Conducted participatory Gram Sabha meetings for inclusive planning and project prioritization.
- Focused on preventive maintenance, timely repairs, and asset management.
- Converged schemes from Central and State governments for holistic development.
- Promoted community awareness through campaigns, plantation drives, and sanitation activities.
- Adopted innovative digital platforms: WhatsApp groups, QR codes, digital certificates for transparency and citizen engagement.
- Developed eco-sensitive plantation and bio-shield at vulnerable sites like Pinni Varipalem Beach.

SUPPORT RECEIVED

- Technical and financial support from Central and State schemes such as Jal Jeevan Mission, MGNREGA, Swachh Bharat Mission, and XV Finance Commission grants.
- Assistance from government departments and agencies for infrastructure and health.
- Capacity-building for digital governance, disaster management, and water resource management.
- Community participation and SHGs for local enterprise development and asset upkeep.

INNOVATIONS

- Digital governance via QR codes, WhatsApp groups, and online certificates.
- Complete sanitation and waste segregation with vermi-composting and plastic waste ban.
- Plantation and bio-shield development for cyclone mitigation and saltwater intrusion prevention.
- Rainwater harvesting structures in all public buildings and households.
- Energy-efficient LED street lighting and solar-powered public facilities.
- Eco-tourism development through plantation drives and community involvement.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Continue regular maintenance; upgrade water, sanitation, and road infrastructure.
- Expand eco-tourism, micro-enterprises, and income-generating activities.
- Strengthen disaster resilience with community drills and resilient infrastructure.
- Promote digital literacy among elders and vulnerable groups.
- Institutionalize digital monitoring, grievance redressal, and transparency mechanisms.
- Promote renewable energy sources and rainwater harvesting to ensure long-term sustainability.

आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत

हुग्रीजन

ब्लॉक पंचायत: तेंगाखाट
जिला पंचायत: डिब्रूगढ़
राज्य: असम

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 302589
- कुल जनसंख्या: 52,610
- कुल परिवार: 1,038

मुख्य उपलब्धियाँ

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% परिवारों को नल जल सुविधा।
- इंटरनेट, कंप्यूटर एवं सीसीटीवी सहित पंचायत भवन।
- आधार, पैन एवं डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने वाला कॉमन सर्विस सेंटर।
- मछली सुखाने इकाइयों एवं सूक्ष्म उद्यमों सहित बाजार परिसर।
- पंचायत क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था।
- डिजिटल कक्षाओं वाले विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र।
- सभी सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं।
- 100% स्वच्छता कवरेज एवं ओडीएफ प्लस स्थिति।
- 100% टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव।

वर्षा जल संचयन संरचना

चुनौतियाँ

- तटीय एवं चक्रवात प्रभावित क्षेत्र होने के कारण संवेदनशीलता।
- बड़े अवसंरचना कार्यों हेतु सीमित वित्तीय संसाधन।
- आपदा से निपटने की क्षमता और तैयारी संबंधी योजनाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता।
- डिजिटल सेवाओं में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या।
- सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव।

दृष्टिकोण

- सहभागी ग्राम सभा आधारित योजना निर्माण।
- परिसंपत्तियों की समयबद्ध मरम्मत एवं रखरखाव।
- विभिन्न योजनाओं का अभिसरण।
- स्वच्छता एवं आपदा प्रबंधन पर जागरूकता अभियान।
- व्हाट्सऐप समूह एवं क्यूआर कोड जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग।
- संवेदनशील क्षेत्रों में जैव सुरक्षा पट्टी विकसित करना।

प्राप्त समर्थन

- जल जीवन मिशन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन एवं 15वें वित्त आयोग से सहायता।
- सरकारी एजेंसियों एवं विभागों का तकनीकी सहयोग।
- डिजिटल शासन एवं आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- स्वयं सहायता समूहों एवं सामुदायिक संस्थाओं की भागीदारी।

नवाचार

- प्लास्टिक प्रतिबंध एवं वर्मी-कंपोस्टिंग।
- जैव सुरक्षा पट्टी एवं पौधारोपण।
- सभी सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन।
- सौर स्ट्रीट लाइट एवं ऊर्जा दक्ष सार्वजनिक परिसंपत्तियां।
- सामुदायिक सहभागिता आधारित इको-टूरिज्म विकास।

सततता के लिए रोडमैप

- जल, स्वच्छता एवं सड़क अवसंरचना का नियमित उन्नयन।
- इको-टूरिज्म एवं स्थानीय सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा।
- आपदा लचीलापन मजबूत करना।
- डिजिटल साक्षरता का विस्तार।
- नवीकरणीय ऊर्जा एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा।

Self- Sufficient Infrastructure in Panchayat

HOOGRIJAN

BLOCK PANCHAYAT TENGAKHAT
DISTRICT PANCHAYAT DIBRUGARH
ASSAM

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 302589
- Total Population: 52,610
- Total Households: 1,038

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% household coverage under Jal Jeevan Mission, ensuring 'Har Ghar Jal.'
- Constructed a well-equipped Panchayat Bhawan with digital facilities including internet, computers, and CCTV surveillance.
- Established a Common Service Centre (CSC) providing Aadhaar, PAN, utility bill payments, and digital services.
- Developed a market complex supporting local businesses such as fish drying units, cattle ponds, and micro-enterprises.
- Installed energy-efficient LED street lights covering entire village area.
- Constructed community facilities including Anganwadi Centres, MPPS Schools with digital classrooms, and public toilets.
- Implemented rainwater harvesting structures in all public buildings, ensuring sustainable water management.
- Achieved 100% sanitation coverage, declared ODF Plus, with effective waste management, vermi-composting, and plastic waste ban.
- Maintained 100% immunization and institutional deliveries, ensuring comprehensive health coverage.

Rainwater Harvesting Structure

CHALLENGES FACED

- Geographical vulnerability, being in a coastal and cyclone-prone area.
- Limited financial resources for large-scale infrastructure projects.
- Need for enhanced disaster resilience and disaster preparedness planning.
- Internet connectivity issues affecting digital service delivery.
- Maintenance of existing roads, infrastructure, and public facilities.

APPROACH TAKEN

- Conducted participatory Gram Sabha meetings for inclusive planning and prioritization.
- Focused on preventive maintenance and timely repairs of infrastructure assets.
- Converged schemes from Central and State governments for integrated development.
- Promoted community awareness campaigns on sanitation, waste management, and disaster preparedness.
- Adopted innovative digital tools such as WhatsApp groups, QR codes, and digital certificates for effective governance.
- Developed eco-sensitive plantation and bio-shield at vulnerable sites to reduce cyclone impact.

SUPPORT RECEIVED

- Financial and technical support from Central and State schemes including Jal Jeevan Mission, MGNREGA, Swachh Bharat Mission, and XV Finance Commission grants.
- Technical guidance from government agencies and departments.
- Capacity-building programs for infrastructure maintenance, digital governance, and disaster management.
- Support from community organizations, SHGs, and local leadership.

INNOVATIONS

- Plastic waste ban and vermi-composting for sustainable waste management.
- Plantation and bio-shield development at Pinni Varipalem Beach to prevent saltwater intrusion.
- Rainwater harvesting structures in all public buildings, including Anganwadi and schools.
- Solar street lighting and energy-efficient public facilities.
- Eco-tourism potential development through plantation and community engagement.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Continue regular maintenance and upgrade of water, sanitation, and roads.
- Expand eco-tourism initiatives and support local micro-enterprises for sustainable income.
- Strengthen disaster resilience through community drills and resilient infrastructure.
- Promote digital literacy among elders and marginalized groups.
- Institutionalize digital monitoring, grievance redressal, and transparent governance mechanisms.
- Expand renewable energy solutions and rainwater harvesting for long-term sustainability.

आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत

गुंडमाला

ब्लॉक पंचायत: कोथापटनम
जिला पंचायत: प्रकासम
राज्य: आंध्र प्रदेश

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 234731
- कुल जनसंख्या: 2,098
- कुल परिवार: 824

3rd PRIZE

तृतीय पुरस्कार-संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% परिवारों को नल जल कनेक्शन।
- चक्रवात आश्रय स्थल, स्वच्छता परिसर एवं वर्षा जल संचयन युक्त सार्वजनिक भवन विकसित।
- नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण और क्लोरीनीकरण के साथ 98% नल जल की उपलब्धता सुनिश्चित।
- 35 सर्व मौसमीय सड़कों का निर्माण।
- ओडीएफ प्लस स्थिति एवं प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन।
- पशुधन केंद्र, मछली सुखाने इकाइयां एवं सामुदायिक खेल मैदान विकसित।
- "गुंडमाला यूनाइटेड" व्हाट्सऐप समूह एवं क्यूआर आधारित सेवाओं के माध्यम से डिजिटल शासन।
- 100% टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव।
- डिजिटल कक्षाओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों सहित बाल अनुकूल सुविधाएं।

रायथु सेवा केंद्रम्

चुनौतियाँ

- तटीय क्षेत्र होने के कारण चक्रवात एवं प्राकृतिक आपदाओं का खतरा।
- सीमित वित्तीय संसाधन।
- आय के स्रोतों और राजस्व सृजन में और अधिक विविधता की आवश्यकता।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी।
- आंगनवाड़ी एवं आपदा आश्रयों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता।

दृष्टिकोण

- सहभागी ग्राम सभा आधारित योजना एवं पारदर्शिता।
- परिसंपत्तियों के रखरखाव को प्राथमिकता।
- स्वच्छता एवं पौधारोपण अभियान।
- विभिन्न योजनाओं का अभिसरण।
- व्हाट्सऐप समूह एवं क्यूआर कोड आधारित डिजिटल शासन।
- वर्षा जल संचयन एवं जैव सुरक्षा पट्टी के माध्यम से आपदा तैयारी।

प्राप्त समर्थन

- केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से वित्तीय सहायता।
- सरकारी विभागों से तकनीकी मार्गदर्शन।
- डिजिटल एवं अवसंरचना विकास हेतु क्षमता निर्माण।
- एकीकृत विकास के लिए योजनाओं का अभिसरण।
- सामुदायिक सहभागिता एवं स्थानीय नेतृत्व।

नवाचार

- वर्मी-कंपोस्टिंग आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- पिन्नी वारिपलेम बीच जैसे संवेदनशील स्थलों पर पर्यावरण के अनुकूल वृक्षारोपण।
- जैव सुरक्षा पट्टी एवं वर्षा जल संचयन।
- ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइट एवं सौर ऊर्जा सुविधाएं।
- सामुदायिक सहभागिता आधारित इको-टूरिज्म विकास।

सततता के लिए रोडमैप

- जल, स्वच्छता एवं सड़क अवसंरचना का उन्नयन।
- इको-टूरिज्म एवं स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा।
- सामुदायिक जागरूकता अभियान जारी रखना।
- जलवायु लचीलापन एवं आपदा प्रबंधन मजबूत करना।
- डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
- डिजिटल निगरानी, शिकायत निवारण और पारदर्शी शासन तंत्र को संस्थागत करना।

Self- Sufficient Infrastructure in Panchayat

GUNDAMALA

BLOCK PANCHAYAT KOTHAPATNAM
DISTRICT PANCHAYAT PRAKASAM
ANDHRA PRADESH

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 234731
- Total Population: 2,098
- Total Households: 824

3rd PRIZE

Third Prize-Joint

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% household water connection under Jal Jeevan Mission, ensuring 'Har Ghar Jal' certification.
- Developed resilient infrastructure including cyclone shelters, sanitation complexes, and public buildings with rainwater harvesting.
- Maintained 98% tap water coverage, with regular water quality testing and chlorination.
- Constructed and maintained 35 all-weather roads, ensuring connectivity.
- Implemented comprehensive waste management, achieving ODF Plus status, with plastic waste ban and vermi-composting.
- Established community assets such as livestock centers, fish drying units, and community playgrounds, promoting local livelihoods.
- Digitized village governance through digital certificates, CSC services, WhatsApp governance group ("Gundamala United"), and QR-based service access.
- Achieved 100% immunization and institutional deliveries, ensuring high standards of health and nutrition.
- Created child-friendly spaces with digital classrooms, Anganwadi centers, and effective mid-day meal schemes.

Raithu Seva Kendram

CHALLENGES FACED

- Coastal region vulnerabilities due to cyclones and natural disasters.
- Limited financial resources for extensive infrastructure expansion.
- Need for further diversification of income sources and revenue generation.
- Infrastructure needs improvement, such as Anganwadi space and disaster shelter capacity.
- Limited internet connectivity affecting digital service efficiency.

APPROACH TAKEN

- Conducted participatory Gram Sabha meetings for needs assessment, transparency, and inclusive planning.
- Prioritized preventive maintenance and timely repairs of key infrastructure assets.
- Promoted community engagement through awareness campaigns, sanitation drives, and eco-plantation programs.
- Converged schemes from Central and State Governments, leveraging financial and technical support.
- Implemented innovative digital governance tools like WhatsApp groups, QR codes, and digital certificates.
- Strengthened disaster preparedness with rainwater harvesting, bio-shield plantation, and improved shelter capacity.

SUPPORT RECEIVED

- Financial support from Central and State Government schemes.
- Technical guidance from government departments and agencies.
- Capacity-building support for infrastructure and digital initiatives.
- Convergence of schemes for integrated development.
- Community participation and local leadership.

INNOVATIONS

- Solid waste processing and vermi-composting for sustainable waste management.
- Eco-sensitive plantation at vulnerable sites like Pinni Varipalem Beach.
- Community-led infrastructure initiatives like rainwater harvesting and bio-shield plantations.
- Use of energy-efficient LED street lighting and solar-powered public facilities.
- Community participation in eco-tourism development and plantation drives.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Maintain and upgrade water supply, sanitation, and road infrastructure.
- Expand eco-tourism and local micro-enterprises for diversified income.
- Continue community mobilization and awareness campaigns.
- Strengthen disaster management and climate resilience measures.
- Enhance digital literacy, especially among elders and marginalized groups.
- Institutionalize digital monitoring, grievance redressal, and transparent governance mechanisms.

आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत

सनूर

ब्लॉक पंचायत: कारकला
जिला पंचायत: उडुपी
राज्य: कर्नाटक

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 220442
- कुल जनसंख्या: 7,371
- कुल परिवार: 1,534

3rd PRIZE

तृतीय पुरस्कार-संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- सभी बस्तियों तक 100% सर्व मौसमीय सड़क संपर्क।
- वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन इकाई।
- कंप्यूटर एवं वाई-फाई सहित डिजिटल पुस्तकालय।
- पंचायत वाणिज्यिक परिसर द्वारा स्वयं के राजस्व में वृद्धि।
- 100% स्ट्रीट लाइट एवं घरेलू विद्युतीकरण।
- "हर घर जल" प्रमाणन के साथ सार्वभौमिक नल जल सुविधा।
- प्रभावी स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ओडीएफ प्लस स्थिति।
- कॉमन सर्विस सेंटर एवं ऑनलाइन सेवाओं द्वारा डिजिटल शासन।
- रिटेनिंग वॉल जैसी आपदा प्रतिरोधी संरचनाएं।
- सामुदायिक भवन, विद्यालय, आंगनवाड़ी एवं खेल मैदानों का उन्नयन।

डिजिटल पुस्तकालय

चुनौतियाँ

- भारी वर्षा से अवसंरचना पर प्रभाव।
- सार्वजनिक परिसंपत्तियों हेतु सीमित भूमि।
- पूंजीगत परियोजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन जुटाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बनाए रखना।

दृष्टिकोण

- मनरेगा, 15वें वित्त आयोग एवं राज्य/केंद्र योजनाओं का अभिसरण।
- ग्राम सभा एवं सामुदायिक भागीदारी आधारित शासन।
- डिजिटल शासन एवं ऑनलाइन सेवा वितरण को मजबूत करना।
- जलवायु अनुकूल एवं आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर ध्यान।
- स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय हितधारकों के साथ साझेदारी।

प्राप्त समर्थन

- केंद्र एवं राज्य सरकार योजनाओं से वित्तीय सहायता।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग से तकनीकी सहयोग।
- जिला एवं ब्लॉक प्रशासन का मार्गदर्शन।
- स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी।
- साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सहायता।

नवाचार

- क्यूआर कोड आधारित पंचायत सेवाएं।
- निःशुल्क शैक्षणिक संसाधनों वाला डिजिटल पुस्तकालय।
- प्रगति ऐप के माध्यम से जल कर संग्रहण।
- सार्वजनिक जल शुद्धिकरण संयंत्र।
- कर संग्रह हेतु पीओएस मशीन एवं डिजिटल भुगतान प्रणाली।
- मोबाइल आधारित ओवरहेड जल टैंक संचालन।
- ओपन जिम एवं सार्वजनिक खेल मैदान।
- स्वयं सहायता समूह आधारित कैटरिंग सेवाएं एवं आजीविका पहल।
- समय पर स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एम्बुलेंस सुविधा।

सततता के लिए रोडमैप

- वाणिज्यिक परिसंपत्तियों के माध्यम से स्वयं के राजस्व को मजबूत करना।
- सौर ऊर्जा आधारित पहलों को बढ़ावा देना।
- परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दीर्घकालिक रखरखाव।
- डिजिटल अवसंरचना एवं ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार।
- सामुदायिक सहभागिता एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
- जलवायु अनुकूल एवं पर्यावरण हितैषी अवसंरचना को बढ़ावा।

Self- Sufficient Infrastructure in Panchayat

SANOOR

BLOCK PANCHAYAT KARKALA
DISTRICT PANCHAYAT UDUPI
STATE KARNATAKA

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 220442
- Total Population: 7,371
- Total Households: 1,534

3rd PRIZE

Third Prize-Joint

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% all-weather road connectivity to all habitations.
- Established a fully functional Solid and Liquid Resource Management (SLRM) Unit for scientific waste processing.
- Constructed a modern Digital Library with computers and Wi-Fi to promote digital literacy.
- Developed a Gram Panchayat Commercial Complex generating sustainable Own Source Revenue (OSR).
- Ensured 100% streetlight coverage and household electrification.
- Achieved Har Ghar Jal certification with universal tap water connections.
- Declared ODF Plus through effective sanitation and waste management systems.
- Strengthened digital governance through Common Service Centres and online citizen services.
- Established disaster-resilient infrastructure such as retention walls.
- Upgraded community assets including meeting halls, schools, Anganwadi centres, and playgrounds.

Digital Library

CHALLENGES FACED

- Heavy monsoon rainfall affecting infrastructure durability.
- Limited land availability for constructing public assets.
- Mobilizing financial resources for capital-intensive projects.
- Ensuring uninterrupted digital connectivity in rural areas.
- Maintenance of infrastructure in high rainfall regions.

APPROACH TAKEN

- Adopted convergence of schemes such as MGNREGS, the 15th Finance Commission, and State and Central Government initiatives.
- Promoted participatory governance through Gram Sabhas and community involvement.
- Strengthened digital governance and online service delivery.
- Encouraged sustainable infrastructure development and asset management.
- Partnered with Self-Help Groups (SHGs) and local stakeholders for service delivery.
- Focused on climate-resilient and disaster-resistant infrastructure.

SUPPORT RECEIVED

- Financial assistance from Central and State Government schemes.
- Technical support from the Rural Development and Panchayat Raj Department.
- Administrative guidance from Zilla Panchayat and Block authorities.
- Community participation through Self-Help Groups and local institutions.
- Digital support through Common Service Centres.

INNOVATIONS

- QR code-based access to Panchayat services for citizens.
- Digital Library providing free educational resources.
- Water tariff collection using the Pragati App.
- Installation of public water purification plants.
- POS machines and digital payment systems for tax collection.
- Mobile-based remote operation of overhead water tanks.
- Open Gym and public playgrounds promoting health and fitness.
- SHG-led catering services and livelihood initiatives.
- Ambulance services ensuring timely healthcare access.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthening Own Source Revenue through commercial assets.
- Promoting renewable energy initiatives such as solar installations.
- Ensuring long-term maintenance through asset management systems.
- Expanding digital infrastructure and e-governance services.
- Encouraging community participation and institutional strengthening.
- Enhancing climate-resilient and eco-friendly infrastructure.

सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत

एक सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत वह है जो निम्न सुनिश्चित करती है:

- बीपीएल, दिव्यांग, निराश्रित एवं सामाजिक रूप से वंचित समूहों के जीवन स्तर में सुधार।
- पात्र समूहों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित करना।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना।
- आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का नामांकन सुनिश्चित करना।
- उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराना।
- उपयुक्त अवसंरचना (शौचालय, आंगनवाड़ी केंद्र आदि) विकसित करना।
- वंचित समूहों के प्रति असमानता एवं सभी प्रकार के भेदभाव को कम करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण को सुगम बनाना।
- गरीब, निराश्रित एवं कमजोर वर्गों की पहचान हेतु मानदंड विकसित करना।
- गरीब एवं कमजोर वर्गों हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी का प्रसार करना।
- उत्तरदायी, समावेशी एवं सहभागी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभा को सशक्त बनाना।
- नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं एवं उनकी निगरानी सुनिश्चित करना।
- दिव्यांगजनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना।

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना।
- पीड़ितों के पुनर्वास में सहयोग एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना सुनिश्चित करना।
- सभी जन्मों का पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित करना।
- समान कार्य अवसर सुनिश्चित करना।
- रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना।

SOCIALLY JUST AND SOCIALLY SECURED PANCHAYAT

SOCIALLY JUST AND SECURED PANCHAYAT IS ONE WHICH ENSURES:

- Improved living standards of BPL, disabled, destitute, socially disadvantaged groups
- Coverage of eligible groups under social protection scheme

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Improve living standards of BPL households through coverage under social protection schemes
- Enrol children and pregnant women under ICDS
- Provide productive employment
- Develop appropriate infrastructure (toilets, anganwadi centres etc.)
- Reduce inequalities and all forms of discrimination of disadvantaged groups
- Facilitate registration of eligible under Public Distribution Scheme
- Develop criteria for identification of the poor, destitute and vulnerable
- Dissemination of information on various schemes for poor and vulnerable groups
- Strengthen Gram Sabha for ensuring responsive, inclusive and participatory representation
- Ensure timely access of services to citizen and its monitoring
- Rehabilitation of differently-abled

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Ensure safe & secured environment for women and girl children
- Support rehabilitation of victim and ensure legal action
- Ensure inclusive and quality education
- Ensure quality infrastructure in schools & health centers
- Ensure complete registration of all births
- Ensure equal work opportunities
- Facilitate employment generation

सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

शांशा

ब्लॉक पंचायत: लाहौल
जिला पंचायत: लाहौल एवं स्पीति
राज्य: हिमाचल प्रदेश

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 9128
- कुल जनसंख्या: 807
- कुल परिवार: 92

मुख्य उपलब्धियाँ

- मनरेगा के अंतर्गत 64 जॉब कार्ड जारी कर ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 53 लाभार्थियों को आच्छादित किया गया, जिनमें 42 वरिष्ठ नागरिक, 6 विधवाएं एवं 5 दिव्यांगजन शामिल हैं।
- पीएम-जय के अंतर्गत 40 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की गईं।
- आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 9 बच्चों (0ख़6 वर्ष), 2 गर्भवती महिलाओं एवं 1 धात्री माता का नामांकन किया गया।
- शून्य अपराध दर्ज होने से सुरक्षित सामाजिक वातावरण सुनिश्चित हुआ।
- महिला ग्राम सभाओं के माध्यम से महिलाओं एवं वंचित समूहों की शासन में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की गई।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच

चुनौतियाँ

- कठोर शीतकालीन परिस्थितियों के कारण मौसमी पलायन, जिससे लाभार्थियों की निगरानी कठिन हुई।
- सीमित स्वयं के राजस्व स्रोत एवं केंद्र एवं राज्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता।
- सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति कम जागरूकता।
- ग्राम सभा में कमजोर सहभागिता के कारण सामुदायिक भागीदारी सीमित रही।
- दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां एवं मौसमी अलगाव के कारण सेवा वितरण प्रभावित हुआ।

दृष्टिकोण

- परिवार प्रमुखों तक कल्याणकारी योजनाओं की समयबद्ध जानकारी पहुंचाने हेतु व्हाट्सऐप समूहों का उपयोग किया गया।
- समावेशी सहभागिता हेतु पूर्व ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा एवं महिला ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के सहयोग से घर-घर सेवा वितरण सुनिश्चित किया गया।
- योजनाओं का प्रचार नोटिस, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं स्थानीय मीडिया के माध्यम से किया गया।
- जागरूकता एवं लाभार्थी पहचान हेतु आईईसी शिविर आयोजित किए गए।

प्राप्त समर्थन

- वित्त आयोग अनुदान, आरजीएसए, वीकेवीएनवाई, एमपीएलएडीएस एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समयबद्ध निधि प्राप्त हुई।
- योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय अधिकारियों एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही।
- जिला प्रशासन के संस्थागत सहयोग से नियमित आईईसी शिविर आयोजित किए गए।

नवाचार

- परिवार प्रमुखों के साथ वास्तविक समय में कल्याणकारी योजनाओं की सूचना साझा करने हेतु व्हाट्सऐप आधारित डिजिटल संपर्क व्यवस्था।
- महिलाओं एवं वंचित समूहों की संरचित सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु महिला ग्राम सभाएं।
- दूरस्थ एवं मौसमी रूप से दुर्गम बस्तियों में घर-घर सेवा वितरण व्यवस्था।
- सतत कल्याणकारी सेवा वितरण हेतु विभिन्न अनुदान स्रोतों (आरजीएसए, एमपीएलएडीएस, वित्त आयोग) का अभिसरण।

सततता के लिए रोडमैप

- दिव्यांगजन, वृद्धजन, विधवाओं एवं अनाथों सहित कमजोर वर्गों का व्यापक डाटाबेस तैयार एवं संधारित करना।
- सामाजिक सुरक्षा उद्देश्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में एकीकृत करना।
- विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का 100% नामांकन एवं आईसीडीएस की सतत निगरानी सुनिश्चित करना।
- कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी एवं प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
- मौसमी अलगाव के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु शीतकाल-पूर्व सेवा योजना को सुदृढ़ करना।

Socially Just & Socially Secured Panchayat

SHANSHA

BLOCK PANCHAYAT: LAHAUL
DISTRICT PANCHAYAT: LAHAUL & SPITI
STATE: HIMACHAL PRADESH

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 9128
- Total Population: 807
- Total Households: 92

KEY ACHIEVEMENTS

- Issued 64 job cards under MGNREGA, providing employment security to rural households
- Covered 53 beneficiaries under National Social Assistance Programme including 42 senior citizens, 6 widows, and 5 persons with disabilities
- Distributed 40 Ayushman Bharat Health Cards under PM-JAY for cashless healthcare access
- Enrolled 9 children (0–6 years), 2 pregnant women, and 1 lactating mother under ICDS scheme
- Maintained zero reported crimes ensuring a safe social environment
- Ensured strong participation of women and marginalised groups in governance through Mahila Gram Sabhas

Free Health Check-up under Ayushman Bharat scheme

CHALLENGES FACED

- Harsh winter conditions causing seasonal migration, making beneficiary tracking difficult
- Limited own-source revenue with heavy dependence on Central and State grants
- Low awareness among residents about government welfare schemes
- Weak Gram Sabha participation limiting community involvement in planning
- Difficult terrain and seasonal isolation affecting service delivery

APPROACH TAKEN

- Used WhatsApp groups to disseminate timely information on welfare schemes to household heads
- Organised pre-Gram Sabhas, special Gram Sabhas, and Mahila Gram Sabhas for inclusive participation
- Implemented door-to-door service delivery with support from elected representatives and frontline workers
- Publicised schemes through notices, digital platforms, and local media
- Conducted IEC camps for awareness generation and beneficiary identification

SUPPORT RECEIVED

- Timely fund releases under Finance Commission Grants, RGSA, VKVNY, MPLADS, and Swachh Bharat Mission
- Active involvement of line departments and frontline workers in scheme implementation
- Regular IEC camps organised with institutional support from district administration

INNOVATIONS

- WhatsApp-based digital outreach for real-time welfare scheme communication with household heads
- Mahila Gram Sabhas ensuring structured participation of women and marginalised groups
- Door-to-door service delivery mechanism in remote and seasonally inaccessible habitations
- Convergence of multiple grant sources (RGSA, MPLADS, Finance Commission) for sustained welfare delivery

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Create and maintain a comprehensive database of vulnerable groups including Divyangs, elderly, widows, and orphans
- Integrate social security objectives into the Gram Panchayat Development Plan (GPDP)
- Ensure 100% enrolment of children in schools and Anganwadi centres with continued ICDS monitoring
- Conduct training and capacity-building programmes for welfare scheme monitoring and management
- Strengthen pre-winter service planning to ensure uninterrupted access during seasonal isolation

सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

चांभरली

ब्लॉक पंचायत: खालापुर
जिला पंचायत: रायगढ़
राज्य: महाराष्ट्र

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 186760
- कुल जनसंख्या: 4,314
- कुल परिवार: 540

2nd PRIZE

द्वितीय पुरस्कार - संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- महात्मा गांधी तंटा मुक्त गांव अभियान के अंतर्गत तंटा मुक्त (विवाद-मुक्त) गांव घोषित।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 115 आवासों का निर्माण; कोई परिवार बेघर नहीं।
- अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 540 परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित।
- विधवा, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को आच्छादित किया गया।
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के अंतर्गत 655 महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह प्रदान किए गए।
- 100% एफएचटीसी उपलब्धि; हर घर जल एवं ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित।
- 54 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 594 महिलाओं को जोड़ा गया; 160 महिलाएं लखपति दीदी बनीं।
- आपले सरकार सेवा केंद्र के माध्यम से ग्राम स्तर पर 1,165 सेवाएं प्रदान की गईं।
- पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे एवं 320 सौर स्ट्रीट लाइट स्थापित की गईं।
- बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न एवं कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के शून्य मामले दर्ज।

महिला सभा

चुनौतियाँ

- गहरी सामाजिक पूर्वाग्रह, अंधविश्वास एवं समानता आधारित परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध।
- समावेशी एवं न्यायपूर्ण विकास के प्रति कम सामुदायिक जागरूकता।
- समय पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं तकनीकी विशेषज्ञता की कमी।

दृष्टिकोण

- जीपीडीपी निर्माण में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं अल्पसंख्यकों के हितों को शामिल करते हुए सहभागी योजना सुनिश्चित की गई।
- प्रत्येक ग्राम सभा से पूर्व महिला सभाएं एवं बाल सभाएं आयोजित कर महिलाओं एवं बच्चों की संरचित भागीदारी सुनिश्चित की गई।
- महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा जल एवं स्वच्छता समितियों को सक्रिय किया गया।
- ग्राम सभा एवं समितियों के माध्यम से जागरूकता एवं सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया गया।
- पंचायत प्रतिनिधियों ने कमजोर परिवारों को योजनाओं एवं सेवाओं तक पहुंचाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।
- महिला स्वयं सहायता समूहों ने सामाजिक समरसता एवं सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को सुदृढ़ किया।

प्राप्त समर्थन

- केंद्र, राज्य एवं पंचायत के स्वयं के राजस्व स्रोतों के अभिसरण से सभी योजनाओं में 100% लाभार्थी संतृप्ति प्राप्त हुई।
- एनजीओ एवं सीएसआर साझेदारों से वित्तीय एवं जागरूकता संबंधी सहयोग प्राप्त हुआ।
- आंगनवाड़ी केंद्रों, आशा कार्यकर्ताओं एवं ब्लॉक एवं जिला अधिकारियों से संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ।

नवाचार

- महिला सभा एवं बाल सभा मॉडल के माध्यम से ग्राम सभा पूर्व संरचित सहभागिता सुनिश्चित।
- सार्वजनिक स्थलों एवं भवनों में सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व्यवस्था।
- आपले सरकार सेवा केंद्र के माध्यम से ग्राम स्तर पर 1,165 सरकारी सेवाएं उपलब्ध।
- दिव्यांग पेंशन एवं सहायक उपकरणों हेतु पंचायत के स्वयं के राजस्व का उपयोग।
- सामूहिक भोजन पहल के माध्यम से सामाजिक समरसता को बढ़ावा।

सततता के लिए रोडमैप

- ग्राम सभा एवं समितियों के माध्यम से सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं निगरानी।
- नई कमजोरियों की शीघ्र पहचान एवं समाधान तथा नए लाभार्थियों का समय पर नामांकन।
- सामाजिक समरसता बनाए रखने हेतु स्वयं सहायता समूह आधारित जागरूकता एवं जनभागीदारी अभियान जारी रखना।
- महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर परिवारों की सक्रिय निगरानी के माध्यम से अपराध-मुक्त वातावरण बनाए रखना।
- पेंशन एवं कल्याणकारी अभिलेखों का नियमित सत्यापन एवं समयबद्ध अद्यतन सुनिश्चित करना।

Socially Just & Socially Secured Panchayat

CHAMBHARLI

BLOCK PANCHAYAT: KHALAPUR
DISTRICT PANCHAYAT: RAIGAD
STATE: MAHARASHTRA

2nd PRIZE

Second Prize-Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 186760
- Total Population: 4,314
- Total Households: 540

KEY ACHIEVEMENTS

- Declared Tanta Mukt (Dispute-Free Village) under Mahatma Gandhi Tanta Mukt Gaon Abhiyaan
- Constructed 115 PMAY houses; no family homeless
- Ensured food security for 540 families under Antyodaya Anna Yojana
- Covered all eligible beneficiaries under widow, old age, and disability pension schemes
- Provided ₹1,500/month to 655 women under Mukhya Mantri Majhi Ladki Bahin Yojana
- Achieved 100% FHTC; declared Har Ghar Jal and ODF Plus Model village
- Engaged 594 women through 54 SHGs; 160 became Lakhpati Didis
- Operated Aaple Sarkaar Seva Kendra delivering 1,165 services at village level
- Installed CCTV cameras and 320 solar streetlights across the village
- Maintained zero cases of child marriage, dowry harassment, and crimes against vulnerable groups

Mahila Sabha

CHALLENGES FACED

- Deep-rooted social prejudices, superstitions, and resistance to equitable change
- Low community awareness about the need for inclusive and fair development
- Timely availability of funds and occasional gaps in technical expertise
- Approach Taken
- Ensured participatory GPDP preparation covering interests of women, SC, ST, OBC, senior citizens, Divyangs, and minorities
- Held Mahila Sabhas and Bal Sabhas before each Gram Sabha for structured participation of women and children
- Activated thematic committees including Women and Child, Health and Nutrition, Education, and Water and Sanitation

APPROACH TAKEN

- Inclusive participation in GPDP preparation ensured representation of women, SC, ST, OBC, senior citizens, Divyang persons, and minorities, fostering collective ownership.
- The Gram Sabha and committees played a key role in community awareness and sensitisation.
- Panchayat members actively supported vulnerable families in accessing benefits and services.
- Women SHGs strengthened social cohesion and encouraged positive social change.

SUPPORT RECEIVED

- Convergence of Central, State, and GP own-source funds achieving 100% beneficiary saturation across all schemes
- Support from NGOs and CSR partners for funding and awareness activities
- Institutional support from Anganwadi centres, ASHA workers, and block and district officials

INNOVATIONS

- Mahila Sabha and Bal Sabha model ensuring structured pre-Gram Sabha participation of women and children
- CCTV-enabled village safety system across public spaces and buildings
- Aaple Sarkaar Seva Kendra delivering 1,165 government services at the village level
- GP own-source fund utilisation for Divyang pensions and assistive devices
- Samuh Bhojan initiative fostering social cohesion through community-contributed collective meals

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Regular review and monitoring of all schemes through Gram Sabha and village committees
- Promptly flag and redress new vulnerabilities; identify and enrol new beneficiaries without delay
- Sustain SHG-led awareness and public participation drives for continued social cohesion
- Maintain zero-crime environment through active monitoring of women, children, and vulnerable households
- Continue periodic beneficiary verification and timely updation of pension and welfare records

सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

मंदर

ब्लॉक पंचायत: पोलोसरा
जिला पंचायत: गंजाम
राज्य: ओडिशा

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 117917
- कुल जनसंख्या: 6,032
- कुल परिवार: 1,381

2nd PRIZE

द्वितीय पुरस्कार - संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 227 वृद्धजन, 112 विधवाओं एवं 99 दिव्यांगजनों को लगभग 100% पेंशन कवरेज प्रदान किया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 964 परिवारों एवं 894 पीएचएच/एएवाई परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- कमजोर वर्गों हेतु अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 811 पक्के आवास स्वीकृत किए गए।
- दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए तथा सार्वजनिक संस्थानों में रैंप का निर्माण किया गया।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नागरिकों को प्रति वर्ष 20 के प्रीमियम पर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया गया।
- निरिक्ष्यणा डिजिटल मातृ स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को कैशलेस अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान की गई।
- महिलाओं, बच्चों, एससी/एसटी एवं दिव्यांगजनों के विरुद्ध अपराधों के शून्य मामले दर्ज किए गए।

दिव्यांग अनुकूल संरचनाएँ

चुनौतियाँ

- एससी/एसटी परिवारों में निरंतर गरीबी एवं सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पेंशन योजनाओं के सीमित लक्ष्य।
- ग्राम सभा बैठकों में मध्यम स्तर की सामुदायिक भागीदारी।

दृष्टिकोण

- संतृप्ति आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि पेंशन, खाद्य, स्वास्थ्य एवं आवास योजनाओं से कोई भी पात्र नागरिक वंचित न रहे।
- लाभार्थियों की पहचान एवं योजनाओं से जोड़ने हेतु घर-घर सत्यापन एवं व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए।
- वृद्धजनों की विशेष आवश्यकताओं जैसे सहायक उपकरण एवं पश्चिमी शैली के शौचालय सहायता हेतु वृद्धजन सभाओं का आयोजन किया गया।
- दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाएं, वृद्धजन एवं बच्चों को संबंधित योजनाओं से जोड़ते हुए जीवन-चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया।
- दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस ग्राम सभा में आयोजित कर सामाजिक संवेदनशीलता विकसित की गई।

प्राप्त समर्थन

- जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएसबीवाई, आयुष्मान भारत एवं अंत्योदय गृह योजना सहित केंद्र एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण।
- सामाजिक कल्याण, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं बैंकिंग संस्थानों से सहयोग प्राप्त हुआ।
- बीएसएसओ की उपस्थिति से पेंशन आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित हुई तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने सत्यापन में सहयोग प्रदान किया।
- पीपीपी आधारित निरिक्ष्यणा पहल के माध्यम से डिजिटल मातृ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हुई।

नवाचार

- ट्रांसजेंडर समुदाय के समावेशन एवं सामाजिक पहचान हेतु "स्वीकृति योजना"।
- निरिक्ष्यणा पहल के माध्यम से पीपीपी आधारित कैशलेस डिजिटल मातृ स्वास्थ्य सेवाएं एवं निःशुल्क अल्ट्रासाउंड सुविधा।
- वृद्धजन सभा मॉडल के माध्यम से शिकायत निवारण एवं सहायक सेवाएं सुनिश्चित करना।
- दिव्यांग स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पारस्परिक सहयोग एवं कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच।
- यूडीआईडी कार्ड एवं दिव्यांग प्रमाणन हेतु विशेष शिविरों के माध्यम से सेवाएं घर-घर तक पहुंचाना।

सततता के लिए रोडमैप

- पात्र लाभार्थियों की वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने हेतु डिजिटाइज्ड कमजोर वर्ग रजिस्टर का संधारण।

Socially Just & Socially Secured Panchayat

MANDAR

BLOCK PANCHAYAT: POLOSARA
DISTRICT PANCHAYAT: GANJAM
STATE: ODISHA

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 117917
- Total Population: 6,032
- Total Households: 1,381

2nd PRIZE

Second Prize-Joint

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved near 100% pension coverage for 227 elderly, 112 widows, and 99 PwDs under State and Central schemes
- Ensured food security for 964 households under PDS and 894 PHH/AAY households
- Sanctioned 811 pucca houses under Antyodaya Gruha Yojana for vulnerable families
- Distributed assistive devices to PwDs and constructed ramps in public institutions
- Mobilised citizens under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana providing accident insurance of up to ₹2 lakh at ₹20 per annum
- Provided cashless ultrasound services to pregnant women under NIRIKHYANA digital maternal health initiative
- Maintained zero cases of crime against women, children, SC/ST, and PwDs

Differently-abled friendly structures

CHALLENGES FACED

- Persistent poverty and socio-economic vulnerability among SC/ST households
- Limited targets under PMAY and pension schemes
- Moderate community participation in Gram Sabha meetings

APPROACH TAKEN

- Adopted a saturation-based approach ensuring no eligible citizen is left behind across pension, food, health, and housing schemes
- Conducted door-to-door verification and extensive awareness campaigns for beneficiary identification and linkage
- Convened Elderly Sabha to address distinct needs of senior citizens including assistive devices and western-style toilet support
- Integrated life-cycle approach covering PwDs, pregnant women, elderly, and children under respective schemes
- Observed national and international days for PwDs and elderly in Gram Sabha to build collective empathy

SUPPORT RECEIVED

- Convergence of Central and State schemes including JJM, PMAY, PMSBY, Ayushman Bharat, and Antyodaya Gruha Yojana
- Support from Social Welfare, Food Supply, Health, and Banking institutions
- BSSO presence ensured accuracy of pension data; block-level officials supported verification
- PPP-supported NIRIKHYANA initiative enabling digital maternal health services
- Roadmap for Sustainability
- Maintain a digitised vulnerability register ensuring real-time tracking of eligible beneficiaries

INNOVATIONS

- Sweekruti Scheme for transgender community inclusion and social recognition
- NIRIKHYANA initiative providing cashless, PPP-supported digital maternal health services including free ultrasound
- Elderly Sabha model for targeted grievance redressal and assistive support for senior citizens
- PwD Self-Help Groups enabling peer support and access to welfare benefits
- Special camps for UDID cards and disability certification bringing services to doorsteps

सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

वागूरा

ब्लॉक पंचायत: बी.के. पोरा
जिला पंचायत: बडगाम
केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू एवं कश्मीर

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 241234
- कुल जनसंख्या: लगभग 4,500
- कुल परिवार: 531

3rd PRIZE

तृतीय पुरस्कार - संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- आईएसएसएस एवं एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत 100% संतृप्ति प्राप्त कर सभी पात्र वृद्धजनों एवं विधवाओं को समयबद्ध पेंशन सुनिश्चित की गई।
- लगभग 90% दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराए गए; चिन्हित सभी 5 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं दिव्यांग पेंशन प्रदान की गई।
- आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का लगभग 100% नामांकन सुनिश्चित कर प्रत्येक परिवार को ₹5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया।
- सभी 507 पात्र परिवारों को पीएचएच/एएवाई राशन कार्ड के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- मनरेगा के अंतर्गत 5,193 मानव-दिवस रोजगार सृजित किए गए, जिनमें 40% महिलाओं की भागीदारी रही; पिछले वर्ष 15,000 से अधिक मानव-दिवस रोजगार से लगभग 300 परिवार लाभान्वित हुए।
- समग्र शिक्षा के अंतर्गत निगरानी एवं मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांच के माध्यम से विद्यालय छोड़ने की समस्या समाप्त की गई।
- सभी जॉब कार्ड धारकों को पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई योजनाओं के अंतर्गत जीवन एवं दुर्घटना बीमा से जोड़ा गया।
- विवाद समाधान एवं निष्पक्ष पीडीएस वितरण हेतु मासिक बैठक करने वाली सामाजिक न्याय स्थायी समिति का गठन किया गया।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ

चुनौतियाँ

- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाओं एवं आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की जटिलता, विशेषकर वृद्धजनों के लिए।
- आयु प्रमाणपत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण जैसे दस्तावेजों की कमी के कारण लाभार्थी नामांकन में बाधा।
- पारंपरिक सामाजिक बाधाएं एवं वंचित समूहों में कल्याणकारी अधिकारों को लेकर झिझक।
- पंचायत भवन के अभाव में अभिलेख प्रबंधन एवं सेवा वितरण प्रभावित हुआ।
- कुछ क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता संबंधी समस्याएं एवं योजनाओं के आंकड़ों में मामूली विसंगतियां।

दृष्टिकोण

- "पंचायत आपके द्वार" पहल के अंतर्गत घर-घर सत्यापन एवं दस्तावेज संग्रह अभियान चलाया गया।
- पंचायत घर को डिजिटल हब में परिवर्तित कर ऑनलाइन पंजीकरण हेतु नि:शुल्क तकनीकी सहायता प्रदान की गई।
- नियमित जन सुनवाई आयोजित कर सामुदायिक विश्वास एवं पारदर्शी लाभार्थी चयन सुनिश्चित किया गया।
- स्वास्थ्य, बीमा एवं कल्याणकारी शिविरों हेतु धार्मिक नेताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया।
- एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कमजोर महिलाओं की पहचान एवं योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया।

प्राप्त समर्थन

- बडगाम जिला प्रशासन द्वारा पेंशन अनुमोदन में तेजी लाने हेतु विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से डेटा समन्वयन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
- सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाणन हेतु स्थल पर मेडिकल बोर्ड आयोजित किए गए।
- आशा कार्यकर्ताओं, धार्मिक नेताओं एवं स्वयं सहायता समूहों से सामुदायिक जागरूकता एवं जनसहभागिता में सहयोग प्राप्त हुआ।

नवाचार

- "पंचायत आपके द्वार" मॉडल के माध्यम से सक्रिय घर-घर कल्याणकारी सेवा एवं दस्तावेज संग्रह व्यवस्था।
- पंचायत स्तर पर स्थायी शिकायत निवारण एवं नामांकन सहायता हेतु सामाजिक सुरक्षा सहायता केंद्र की अवधारणा।
- दिव्यांगजनों हेतु आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए पंचायत के स्वयं के राजस्व से ग्राम दिव्यांग निधि।
- "बैक टू विलेज (बी2वी)" एवं "ब्लॉक दिवस" कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रशासनिक पहुंच एवं शिकायत निवारण।
- पोषण वाटिका एवं सामुदायिक अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छता एवं पंचायत राजस्व सृजन को बढ़ावा।

सततता के लिए रोडमैप

- पंचायत घर में स्थायी सामाजिक सुरक्षा सहायता केंद्र स्थापित कर नए पंजीकरण, संशोधन एवं लाभार्थी सहायता सुनिश्चित करना।
- दिव्यांगजनों की आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं हेतु पंचायत के स्वयं के राजस्व से "ग्राम दिव्यांग निधि" का निर्माण।
- जीपीडीपी में सामाजिक न्याय संकेतकों का एकीकरण कर सभी भविष्य की अवसंरचना परियोजनाओं को दिव्यांग अनुकूल बनाना।
- अभिलेख प्रबंधन एवं कॉमन सर्विस सेंटर के बेहतर संचालन हेतु पंचायत भवन निर्माण को प्राथमिकता देना।
- पीएमएमवीवाई एवं आवास पोर्टल संबंधी विसंगतियों का समाधान तथा पेयजल अवसंरचना हेतु 15वें वित्त आयोग निधियों का पूर्ण उपयोग।

Socially Just & Socially Secured Panchayat

WAGOORA

BLOCK PANCHAYAT: B.K. PORA
DISTRICT PANCHAYAT: BUDGAM
UNION TERRITORY: JAMMU & KASHMIR

3rd PRIZE

Third Prize-Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 241234
- Total Population: ~4,500
- Total Households: 531

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% saturation under ISSS and NSAP schemes ensuring timely pension to all eligible senior citizens and widows through dedicated camps
- Facilitated UDID cards for ~90% of PwDs ensuring physical and digital accessibility; all 5 identified PwDs provided assistive devices and disability pensions
- Achieved near 100% Ayushman Bharat Golden Card enrolment providing ₹5 lakh annual health insurance cover per household
- Ensured 100% food security with all 507 eligible households covered under PHH/ AAY ration cards
- Generated 5,193 person-days of wage employment under MGNREGA with 40% women participation; over 15,000 person-days in the past year benefitting nearly 300 households
- Eliminated school dropouts through Samagra Shiksha monitoring and regular mid-day meal quality checks
- Enrolled all job card holders under PMJJBY and PMSBY for life and accident insurance coverage
- Formed a Social Justice Standing Committee meeting monthly for dispute resolution and fair PDS distribution

Women engaged in SHGs

CHALLENGES FACED

- Procedural complexity of online applications and Aadhaar-based biometric authentication for elderly residents
- Documentation gaps such as missing age certificates and disability proofs stalling beneficiary enrolment
- Traditional social barriers and hesitance among marginalised groups to claim welfare entitlements
- Lack of functional Panchayat Bhawan affecting record management and service delivery
- Drinking water quality concerns in some areas and minor discrepancies in scheme data reporting

APPROACH TAKEN

- Implemented Panchayat at your Doorstep initiative with door-to-door verification and document collection by GRS and local activists
- Transformed Panchayat Ghar into a Digital Hub offering free technical assistance for online registrations
- Held regular Jan Sunwais (Public Hearings) to build community trust and ensure transparent scheme selection
- Engaged religious leaders and ASHA workers for health, insurance, and welfare camp mobilisation
- Leveraged NRLM SHGs to identify and enrol vulnerable women into welfare schemes

SUPPORT RECEIVED

- Specialised Nodal Officers from District Administration Budgam for fast-tracking pension approvals
- Technical guidance from National Informatics Centre (NIC) for data synchronisation
- On-site medical boards organised by Social Welfare Department for disability certifications
- Active support from ASHA workers, religious leaders, and SHGs for community mobilisation

INNOVATIONS

- Panchayat at your Doorstep model for proactive door-to-door welfare outreach and document collection
- Social Security Help-Desk concept for permanent grievance and enrolment support at Panchayat level
- Village Disability Fund from OSR for emergency medical support to PwDs
- Back to Village (B2V) and Block Diwas programmes for direct administrative outreach and grievance redressal
- Poshan Vatika kitchen gardens and community-driven waste management generating OSR and improving sanitation

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Establish a permanent Social Security Help-Desk at Panchayat Ghar for new entries, corrections, and beneficiary assistance
- Create a Village Disability Fund from Panchayat OSR for emergency medical needs of PwDs
- Integrate GPDP with social justice indicators ensuring all future infrastructure projects are Divyang-friendly
- Prioritise Panchayat building completion to improve records management and CSC functioning
- Rectify PMMVY and housing-related portal discrepancies and fully utilise 15th Finance Commission funds for drinking water infrastructure

सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

हकलादी

ब्लॉक पंचायत: कुंडापुर
जिला पंचायत: उडुपी
राज्य: कर्नाटक

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 220462
- कुल जनसंख्या: 7,050
- कुल परिवार: 1,461

3rd PRIZE

तृतीय पुरस्कार - संयुक्त

मुख्य उपलब्धियाँ

- संध्या सुरक्षा, मैत्री एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत 1,320 लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए 100% पेंशन संतृप्ति प्राप्त की गई।
- चिन्हित 172 दिव्यांगजनों को 100% यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए तथा 25 दिव्यांगजनों को आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु मनरेगा रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- पात्र परिवारों हेतु 4,800 आयुष्मान भारत कार्ड वितरित कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- एससी/एसटी लाभार्थियों हेतु 18 आवास निर्मित कर सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया गया।
- 12 बिस्तर पर आश्रित मरीजों हेतु राशन एवं पेंशन की घर-घर आपूर्ति व्यवस्था संस्थागत की गई।
- एससी/एसटी बच्चों के बीच शून्य ड्रॉपआउट दर सतत निगरानी एवं सहयोग से सुनिश्चित की गई।
- कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के कोई महत्वपूर्ण मामले दर्ज न होने से मजबूत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

विशेष महिला ग्राम सभा

चुनौतियाँ

- वृद्ध एवं वंचित व्यक्तियों के पास जन्म प्रमाणपत्र एवं अद्यतन आधार जैसे दस्तावेजों की कमी।
- दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के लिए सरकारी कार्यालयों तक पहुंच में भौतिक बाधाएं।
- सामाजिक कलंक के कारण कमजोर वर्गों की ग्राम सभा में सीमित भागीदारी।
- सभी दिव्यांगजनों के लिए समयबद्ध चिकित्सा मूल्यांकन एवं यूडीआईडी प्रमाणन में कठिनाइयां।

दृष्टिकोण

- पेंशन अदालतों एवं स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से "कैंप मोड" दृष्टिकोण अपनाकर तत्काल दस्तावेज सत्यापन एवं नामांकन सुनिश्चित किया गया।
- समुदाय स्वयंसेवकों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर बिस्तर पर आश्रित एवं निराश्रित व्यक्तियों की पहचान एवं सहायता की गई।
- महिलाओं, एससी/एसटी एवं दिव्यांगजनों हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर समर्पित शिकायत निवारण मंच उपलब्ध कराया गया।
- यूडीआईडी प्रमाणन हेतु स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से स्थल पर चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।

प्राप्त समर्थन

- सामाजिक कल्याण एवं राजस्व विभागों द्वारा पेंशन एवं आवास आवेदन प्रक्रिया में सहयोग।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी में सहयोग।
- एससी/एसटी समुदाय नेतृत्व द्वारा शिविरों एवं सर्वेक्षणों हेतु लाभार्थियों को प्रेरित किया गया।
- वरिष्ठ नागरिक पार्क सहित सामुदायिक परिसंपत्तियों हेतु स्थानीय दानदाताओं का सहयोग प्राप्त हुआ।

नवाचार

- पेंशन अदालतों के माध्यम से तत्काल दस्तावेज समाधान एवं योजना नामांकन।
- बिस्तर पर आश्रित मरीजों हेतु राशन एवं पेंशन की घर-घर आपूर्ति व्यवस्था।
- महिलाओं, एससी/एसटी एवं दिव्यांगजनों हेतु विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से समावेशी निर्णय प्रक्रिया।
- यूडीआईडी प्रमाणन हेतु स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से स्थल पर चिकित्सा शिविर।
- स्थानीय दानदाताओं के सहयोग से वरिष्ठ नागरिक पार्क एवं कौशल केंद्र की परिकल्पना।

सततता के लिए रोडमैप

- वृद्धजनों के स्वास्थ्य एवं सम्मान को बढ़ावा देने हेतु वॉकिंग ट्रैक सहित वरिष्ठ नागरिक पार्क विकसित करना।
- एससी/एसटी एवं दिव्यांग युवाओं हेतु कौशल केंद्र स्थापित कर दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- कल्याणकारी सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु नियमित सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करना।
- वंचित युवाओं के सशक्तिकरण हेतु विशेष कौशल विकास शिविर आयोजित करना।
- अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पेंशन अदालत एवं घर-घर पहचान अभियान जारी रखना।

Socially Just & Socially Secured Panchayat

HAKLADI

BLOCK PANCHAYAT: KUNDAPUR
DISTRICT PANCHAYAT: UDUPI
STATE: KARNATAKA

3rd PRIZE

Third Prize-Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 220462
- Total Population: 7,050
- Total Households: 1461

KEY ACHIEVEMENTS

- Achieved 100% pension saturation with 1,320 beneficiaries receiving monthly financial aid under Sandhya Suraksha, Maitri, and other schemes
- Issued UDID cards to 100% of 172 identified PwDs and provided MGNREGS employment to 25 PwDs for financial independence
- Distributed 4,800 Ayushman Bharat cards ensuring universal health coverage for eligible families
- Constructed 18 houses specifically for SC/ST beneficiaries ensuring secure shelter for the most vulnerable
- Institutionalised doorstep delivery of rations and pensions for 12 bedridden patients
- Maintained zero dropout rate among SC/ST children through continuous monitoring and support
- Maintained strong social protection with no significant cases of crime against vulnerable groups

Special Mahila Gram Sabha

CHALLENGES FACED

- Documentation gaps among elderly and marginalised residents lacking birth certificates or updated Aadhaar for scheme enrolment
- Physical accessibility barriers preventing PwDs and elderly from visiting government offices
- Social stigma limiting active participation of vulnerable groups in Gram Sabhas
- Logistical hurdles in conducting timely medical assessments for UDID certification for all PwDs

APPROACH TAKEN

- Adopted Camp Mode approach organising Pension Adalats and health camps for on-the-spot documentation and enrolment
- Conducted door-to-door surveys using community volunteers to identify and assist bedridden and destitute individuals
- Held special Gram Sabhas exclusively for women, SC/STs, and PwDs to provide dedicated grievance platforms
- Collaborated with health officials for on-site medical camps for UDID generation minimising travel for PwDs

SUPPORT RECEIVED

- Social Welfare and Revenue Departments facilitated pension and housing application processing
- Women and Child Development Department assisted in tracking nutritional and health indicators
- SC/ST community leaders actively mobilised beneficiaries for camps and surveys
- Local donors committed support for community assets including a Senior Citizen Park

INNOVATIONS

- Pension Adalats for on-the-spot documentation resolution and scheme enrolment
- Doorstep delivery model for bedridden patients ensuring rations and pensions without hardship
- Special Gram Sabhas exclusively for women, SC/STs, and PwDs for inclusive decision-making
- On-site medical camps in collaboration with health officials for hassle-free UDID certification
- Senior Citizen Park and Skill Hub planned from local donor support for sustained community welfare

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Develop a Senior Citizen Park with walking tracks to promote wellness and dignity among the elderly
- Establish a Skill Hub for SC/ST and PwD youth providing vocational training for long-term economic security
- Conduct regular Social Audits to ensure transparency and accountability in welfare delivery
- Organise special skill development camps for further empowerment of marginalised youth
- Sustain Pension Adalats and door-to-door identification drives for continuous last-mile outreach

सुशासन युक्त पंचायत

सुशासन युक्त पंचायत वह है जो प्रभावी शासन / ई-गवर्नेंस के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के विकासात्मक लाभ एवं उत्तरदायी सेवा वितरण ग्राम पंचायत के सभी निवासियों तक सुनिश्चित करती है।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- आधुनिक ई-प्रौद्योगिकी/प्रणालियों (सीएससी सह-स्थित / नागरिक चार्टर के अनुसार सेवा वितरण) के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करना
- नियमित वार्ड सभा / महिला सभा / बाल-बालिका सभा / ग्राम सभा आयोजित करना
- स्थायी समितियों को क्रियाशील बनाना
- सतत विकास लक्ष्यों (कै्ळे) के स्थानीयकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों / ग्राम समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- जीपीडीपी निर्माण हेतु विभिन्न संस्थाओं / हितधारकों के बीच समन्वय एवं अभिसरण सुनिश्चित करना
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के बीच अभिसरण स्थापित करना
- नागरिक संगठनों के साथ साझेदारी एवं सहयोग स्थापित करना

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- पंचायत सचिवालय में ई-गवर्नेंस एवं आईसीटी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- स्थायी समितियों को सशक्त बनाना
- नागरिक चार्टर के अनुसार प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करना
- शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना
- सहभागी एवं अभिसरण आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना

PANCHAYAT WITH GOOD GOVERNANCE

A Panchayat with Good Governance is one which ensures developmental benefits of various schemes and responsive service delivery to all the residents of Gram Panchayat through effective Governance / e-Governance.

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Ensure better service delivery to citizens through modern e-technologies/systems (CSC co-located / service delivered as per citizen charter)
- Regular ward/Mahila/ Bal-Balika/Gram Sabha
- Functional standing committees
- Involvement of SHG/ village committees for localization of SDGs
- Coordination & convergence among various institutions/ stakeholders for preparation of GPDP
- Panchayati Raj Institution and SHG convergence
- Establishing partnership and collaboration with civil organizations

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Ensuring availability of e-Governance and ICT tools in Panchayat Secretariat
- Strengthening of Standing Committees
- Effective delivery as per Citizen Charter
- Developing Grievance Redressal Mechanism
- Participatory and convergent Gram Panchayat Development Plan

सुशासन युक्त पंचायत

श्रृंगावरम

ब्लॉक पंचायत: नक्कापल्ली (मंडल: नाथावरम)
जिला पंचायत: अनकापल्ली
राज्य: आंध्र प्रदेश

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 212170
- कुल जनसंख्या: 1,837
- कुल परिवार: 650

मुख्य उपलब्धियाँ

- एपी सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2,311 नागरिक सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें 1,949 राजस्व सेवाएं एवं 188 नागरिक आपूर्ति सेवाएं शामिल।
- 7 ग्राम सभाएं, 10 पंचायत बैठकें एवं 4 बाल ग्राम सभाएं आयोजित कर सहभागी एवं समावेशी शासन को सशक्त बनाया गया।
- 24 जन्म, 13 मृत्यु एवं 16 विवाहों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित कर प्रशासनिक दक्षता एवं कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
- 640 राशन कार्डों के माध्यम से पात्र परिवारों को प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- एपी स्वर्ण पंचायत पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर, प्रमाणपत्र एवं अन्य नागरिक सेवाओं की घर-घर डिजिटल सेवा उपलब्ध कराई गई।
- रायतु सेवा केंद्रम के माध्यम से फसल पंजीकरण, सब्सिडी एवं किसान सहायता योजनाओं द्वारा कृषि एवं आजीविका को सशक्त किया गया।
- ओडीएफ स्थिति एवं 100% घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त किए गए।
- 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किए गए।
- 55 स्वयं सहायता समूहों एवं 469 महिला सदस्यों के माध्यम से मजबूत एसएचजी नेटवर्क विकसित किया गया।

स्वर्ण ग्रामम पहल के माध्यम से नागरिक सेवाओं का घर-घर सेवा वितरण

चुनौतियाँ

- सीमित डिजिटल जागरूकता एवं मैनुअल प्रणालियों पर निर्भरता के कारण समयबद्ध सेवा वितरण में कठिनाई।
- शासन एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रति नागरिकों की कम भागीदारी एवं सीमित जागरूकता।
- बिखरे हुए परिवारों में शिकायत निवारण एवं जन्म-मृत्यु पंजीकरण से संबंधित प्रशासनिक चुनौतियां।
- कृषि, स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं के वितरण में विभागों के बीच समन्वय की कमी।
- विद्यालय अवसंरचना में सुधार एवं नामांकन बढ़ाने की आवश्यकता।

दृष्टिकोण

- एपी सेवा एवं स्वर्ण पंचायत पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी घर-घर डिजिटल सेवा वितरण आधारित शासन अपनाया गया।
- नागरिक सहभागिता हेतु नियमित ग्राम सभाएं, पंचायत बैठकें एवं बाल ग्राम सभाएं आयोजित की गईं।
- समयबद्ध पंजीकरण एवं सेवा ट्रैकिंग हेतु संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ किया गया।
- रायतु सेवा केंद्रम एवं विभागीय समन्वय के माध्यम से किसानों तक सक्रिय पहुंच सुनिश्चित की गई।
- दस्तावेज सत्यापन, भौतिक सत्यापन एवं लाभार्थी सत्यापन सहित त्रिकोणीय सत्यापन पद्धति अपनाई गई।

प्राप्त समर्थन

- एपी सेवा एवं स्वर्ण पंचायत डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ।
- कृषि, स्वास्थ्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों से तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता प्राप्त हुई।
- किसान सब्सिडी, फसल सेवाओं एवं वित्तीय योजनाओं हेतु रायतु सेवा केंद्रम का सहयोग प्राप्त हुआ।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम सभाओं एवं स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हुई।

नवाचार

- पारदर्शी घर-घर डिजिटल सेवा वितरण हेतु एपी सेवा एवं स्वर्ण पंचायत पोर्टल का एकीकरण।
- बाल ग्राम सभाओं के माध्यम से बच्चों की सहभागी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- जमीनी स्तर पर कृषि एवं आजीविका सहायता हेतु रायतु सेवा केंद्रम मॉडल।
- शासन मूल्यांकन हेतु दस्तावेज, भौतिक एवं लाभार्थी सत्यापन आधारित त्रिकोणीय सत्यापन पद्धति।
- 55 सक्रिय समूहों एवं 469 महिला सदस्यों के माध्यम से शासन एवं आजीविका गतिविधियों में स्वयं सहायता समूहों का एकीकरण।

सततता के लिए रोडमैप

- नियमित प्रशिक्षण एवं प्रणाली रखरखाव के माध्यम से डिजिटल शासन प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ बनाए रखना।
- स्पष्ट ट्रैकिंग, समयसीमा एवं फॉलो-अप तंत्र के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना।
- संपत्ति अभिलेख अद्यतन एवं डिजिटल कर संग्रहण सुदृढ़ कर स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि करना।
- विद्यालय अवसंरचना मरम्मत एवं नामांकन सुधार जैसे प्रमुख सेवा अंतरालों को प्राथमिकता देना।
- कल्याणकारी सेवाओं एवं नागरिक सेवाओं हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार जारी रखना।

Panchayat with Good Governance

SRUNGAVARAM

BLOCK PANCHAYAT: NAKKAPALLI (MANDAL: NATHAVARAM)
DISTRICT PANCHAYAT: ANAKAPALLI
STATE: ANDHRA PRADESH

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 212170
- Total Population: 1,837
- Total Households: 650

KEY ACHIEVEMENTS

- Delivered 2,311 citizen services through AP Seva platforms including 1,949 revenue services and 188 civil supplies services
- Conducted 7 Gram Sabhas, 10 Panchayat meetings, and 4 Bala Gram Sabhas strengthening participatory and inclusive governance
- Ensured timely registration of 24 births, 13 deaths, and 16 marriages reflecting administrative efficiency and legal compliance
- Implemented PDS effectively with 640 ration cards ensuring food security for eligible families
- Facilitated doorstep digital service delivery through AP Swarna Panchayat portal for property tax, certificates, and citizen services
- Strengthened agriculture and livelihoods through Raithu Seva Kendram covering crop booking, subsidies, and farmer support schemes
- Achieved ODF status and 100% household tap connections
- Achieved 100% institutional deliveries
- Built strong SHG network with 55 SHGs and 469 women members

Door step delivery of citizen services through Swarna Gramam initiative

CHALLENGES FACED

- Limited digital awareness and dependency on manual systems affecting timely service delivery
- Low citizen participation in governance and insufficient awareness about welfare schemes
- Administrative challenges in grievance redressal and vital statistics registration across dispersed households
- Gaps in inter-departmental coordination for agricultural, health, and welfare service delivery
- School infrastructure requiring improvement and scope for increased enrolment

APPROACH TAKEN

- Adopted digital governance through AP Seva and Swarna Panchayat portals for transparent doorstep citizen services
- Conducted regular Gram Sabhas, Panchayat meetings, and Bala Gram Sabhas for citizen engagement
- Strengthened institutional systems for timely vital event registration and service tracking
- Ensured proactive farmer outreach through Raithu Seva Kendram with improved line department coordination
- Applied triangulation methodology including document verification, physical verification, and beneficiary validation

SUPPORT RECEIVED

- State Government support through AP Seva and Swarna Panchayat digital governance platforms
- Technical and administrative assistance from Agriculture, Health, and Civil Supplies line departments
- Raithu Seva Kendram support for farmer subsidies, crop services, and financial schemes
- Community participation through elected representatives, Gram Sabhas, and local officials

INNOVATIONS

- AP Seva and Swarna Panchayat portal integration for transparent doorstep digital service delivery
- Bala Gram Sabhas ensuring child-inclusive participatory governance
- Raithu Seva Kendram model for proactive agriculture and livelihood support at grassroots level
- Triangulation methodology combining document, physical, and beneficiary verification for governance assessment
- SHG integration into governance and livelihood activities with 55 active groups and 469 women members

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Sustain digital governance platforms through regular staff training and system maintenance
- Strengthen grievance redressal with clear tracking, timelines, and follow-up mechanisms
- Improve own-source revenue through updated property records and stronger digital tax collection
- Prioritise closure of key service gaps including school infrastructure repairs and enrolment improvement
- Continue expanding digital platform integration for welfare delivery and citizen services

सुशासन युक्त पंचायत

निम्बाले

ब्लॉक पंचायत: चांदवड
जिला पंचायत: नासिक
राज्य: महाराष्ट्र

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 182776
- कुल जनसंख्या: 2,388
- कुल परिवार: 384

मुख्य उपलब्धियाँ

- आपले सरकार सेवा केंद्र एवं सीएससी के माध्यम से 155 समयबद्ध नागरिक सेवाएं प्रदान कर बिचौलियों पर निर्भरता कम की गई।
- ग्राम सभा के 100% प्रस्तावों को डिजिटाइज कर जीएस निर्णय एप पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया (11 बैठकें अपलोड)।
- ग्राम सभा सत्यापन के माध्यम से प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत 250 लाभार्थियों का चयन कर शून्य शिकायत एवं पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।
- क्यूआर आधारित कर भुगतान प्रणाली लागू कर सुविधा एवं अनुपालन में सुधार किया गया।
- 39 में से 31 कार्य समयसीमा में पूर्ण कर 79% जीपीडीपी कार्यान्वयन प्राप्त किया गया।
- ₹1.64 लाख की स्वयं के स्रोत राजस्व वृद्धि प्राप्त कर वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ किया गया।
- स्वच्छ भारत मिशन, टीबी मुक्त पंचायत एवं हर घर नल से जल पहल के अंतर्गत मान्यता प्राप्त की गई।

नागरिक सेवाओं के लिए आदर्श आपले सेवा केंद्र

चुनौतियाँ

- कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण डिजिटल सेवा वितरण में बाधाएं।
- पंचायत कर्मचारियों में डिजिटल शासन उपकरणों के संचालन हेतु सीमित तकनीकी क्षमता।
- नागरिकों में सीमित डिजिटल जागरूकता के कारण शासन प्रक्रियाओं में कम सहभागिता।

दृष्टिकोण

- आरजीएसए एवं जिला प्रशासन के सहयोग से संरचित सुशासन कार्ययोजना लागू की गई।
- निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सौर अवसंरचना स्थापित कर इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया गया।
- जीपीडीपी योजना, जीईएम खरीद एवं ऑनलाइन सेवा वितरण हेतु कर्मचारियों का क्षमता निर्माण किया गया।
- पारदर्शिता, वित्तीय प्रबंधन एवं नागरिक सेवा वितरण हेतु एसओपी को संस्थागत बनाया गया।
- डिजिटल साक्षरता एवं नागरिक सहभागिता बढ़ाने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए।

प्राप्त समर्थन

- वित्त आयोग अनुदान, पीएमएवाई, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम कुसुम, मनरेगा एवं आयुष्मान भारत के अभिसरण से समग्र विकास सुनिश्चित हुआ।
- राज्य सरकार की पहलों एवं विधायक निधि से स्थानीय अवसंरचना एवं विकास को सुदृढ़ किया गया।
- सुशासन कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु आरजीएसए एवं जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त हुआ।

नवाचार

- सुविधाजनक एवं पारदर्शी राजस्व संग्रहण हेतु क्यूआर आधारित कर भुगतान प्रणाली।
- ग्राम सभा निर्धारण, निर्णय अभिलेखन एवं सार्वजनिक पहुंच हेतु जीएस निर्णय एप।
- समयबद्ध नागरिक सेवा वितरण हेतु आपले सरकार सेवा केंद्र एवं सीएससी का एकीकरण।
- निर्बाध डिजिटल शासन संचालन हेतु सौर ऊर्जा आधारित अवसंरचना।
- सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने हेतु जीईएम पोर्टल आधारित खरीद प्रणाली।

सततता के लिए रोडमैप

- अगले चरण के लक्ष्य के रूप में 100% डिजिटल सेवा वितरण एवं डेटा आधारित शासन को बढ़ावा देना।
- नियमित कर पुनर्मूल्यांकन एवं क्यूआर आधारित डिजिटल संग्रहण के माध्यम से स्वयं के स्रोत राजस्व को सुदृढ़ करना।
- ग्राम सभाओं में वित्त, कार्यों एवं शिकायत स्थिति का नियमित खुलासा कर पारदर्शिता बनाए रखना।
- जल प्रणालियों, डिजिटल अवसंरचना एवं प्रमुख परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु स्थानीय राजस्व से समर्पित रखरखाव निधि बनाना।
- संस्थागत निरंतरता हेतु स्वयं सहायता समूहों, युवा समूहों एवं स्थायी समितियों के माध्यम से द्वितीय पंक्ति नेतृत्व विकसित करना।

Panchayat with Good Governance

NIMBALE

BLOCK PANCHAYAT: CHANDWAD
DISTRICT PANCHAYAT: NASHIK
STATE: MAHARASHTRA

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 182776
- Total Population: 2,388
- Total Households: 384

KEY ACHIEVEMENTS

- Delivered 155 time-bound citizen services through Aaple Sarkar Seva Kendra and CSC, reducing dependency on intermediaries
- Digitised 100% of Gram Sabha resolutions publicly accessible through GS Nirnay App (11 meetings uploaded)
- Selected 250 beneficiaries under major schemes through Gram Sabha validation ensuring zero grievances and full transparency
- Introduced QR-based tax payment system improving convenience and compliance
- Achieved 79% GPDP implementation with 31 out of 39 works completed within timeline
- Increased own-source revenue by ₹1.64 lakh reflecting improved financial discipline
- Achieved recognition under Swachh Bharat Mission, TB-Free Panchayat, and Har Ghar Nal Se Jal initiatives

Aadarsh Aaple Seva Kendra for citizen services

CHALLENGES FACED

- Weak internet connectivity and irregular electricity supply limiting digital service delivery
- Limited technical capacity among Panchayat staff for digital governance tools
- Low digital awareness among citizens constraining participation in governance processes

APPROACH TAKEN

- Implemented a structured Good Governance Action Plan with RGSA and District Administration support
- Installed solar infrastructure for uninterrupted power supply and improved internet connectivity
- Conducted capacity-building for staff on GPDP planning, GeM procurement, and online service delivery
- Institutionalised SOPs for transparency, financial management, and citizen service delivery
- Launched extensive awareness campaigns to improve digital literacy and citizen participation

SUPPORT RECEIVED

- Convergence of Finance Commission Grants, PMAY, Swachh Bharat Mission, PM Kusum, MGNREGS, and Ayushman Bharat for holistic development
- State initiatives and MLA funds strengthening local infrastructure and development
- RGSA and District Administration support for Good Governance Action Plan implementation

INNOVATIONS

- QR-based tax payment system for convenient and transparent revenue collection
- GS Nirnay App for real-time Gram Sabha scheduling, decision recording, and public accessibility
- Aaple Sarkar Seva Kendra integration with CSC for time-bound citizen service delivery
- Solar-powered infrastructure ensuring uninterrupted digital governance operations
- GeM portal procurement ensuring transparency and efficiency in public purchasing

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Pursue 100% digital service delivery and data-driven governance as next-phase goals
- Strengthen own-source revenue through regular tax reassessment and continued QR-based digital collection
- Sustain transparency through regular Gram Sabha disclosure of finances, works, and grievance status
- Create dedicated maintenance fund from local revenues for water systems, digital infrastructure, and key assets
- Build second-line leadership through SHGs, youth groups, and standing committees for institutional continuity

सुशासन युक्त पंचायत

मोथुकुपल्ले

ब्लॉक पंचायत: कोटेपल्ली
जिला पंचायत: विकाराबाद
राज्य: तेलंगाना

3rd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 209912
- कुल जनसंख्या: 2,376
- कुल परिवार: 703

मुख्य उपलब्धियाँ

- 15 विभागों की सहभागिता से समग्र एवं एकीकृत जीपीडीपी तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदित कराया गया तथा पोर्टल पर अपलोड किया गया।
- ग्राम पंचायत के 100% व्यय का ऑनलाइन अपलोड सुनिश्चित कर ई-ग्राम स्वराज में खातों का अद्यतन एवं समापन किया गया।
- पारदर्शिता एवं निगरानी हेतु ग्राम पंचायत की सभी परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग किया गया।
- कार्यशील सीएससी के माध्यम से डिजिटल सेवाएं, दस्तावेजीकरण एवं सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित की गई।
- समावेशी सहभागी शासन हेतु महिला सभा एवं बाल सभा आयोजित की गई।
- पारदर्शिता हेतु सार्वजनिक सूचना बोर्ड के माध्यम से मूलभूत नागरिक सेवाओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया गया।
- दिव्यांगजनों हेतु तकनीक आधारित सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

नियमित ग्राम सभाओं का आयोजन

चुनौतियाँ

- स्थानीय शासन संस्थाओं में विनियम एवं नवाचारी शासन पद्धतियां विकसित करने की सीमित क्षमता।
- केंद्रीकृत सेवा वितरण प्रणाली स्थानीय परिस्थितियों एवं समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को समुचित रूप से संबोधित नहीं कर पाती थी।
- नागरिकों में अधिकारों, कर्तव्यों एवं उपलब्ध डिजिटल सेवाओं के प्रति सीमित जागरूकता।

दृष्टिकोण

- एसआईआरडी एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल प्रबंधन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- स्थानीय स्तर पर पारदर्शी निधि प्रबंधन हेतु जल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया गया।
- ग्राम की आवश्यकताओं के आधार पर सड़क, जलापूर्ति एवं स्वच्छता जैसी आवश्यक अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई।
- ऑनलाइन सेवा पहुंच, पारदर्शिता एवं सुगम शासन हेतु ई-पंचायत प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया।

प्राप्त समर्थन

- भारतनेट, सीएससी, उमंग एवं डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना सहयोग प्राप्त हुआ।
- पीएमजेडीवाई, पीएम-मुद्रा, पीएम-किसान एवं डीबीटी के माध्यम से बिना बिचौलियों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया।
- मनरेगा डिजिटलीकरण, ई-ग्राम स्वराज एवं जीईएम पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी शासन को बढ़ावा मिला।
- पीएमजीडिशा के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया तथा वित्त आयोग अनुदानों के अभिसरण से राज्य योजनाओं का ऑनलाइन कार्यान्वयन किया गया।

नवाचार

- सार्वजनिक पारदर्शिता हेतु आय, व्यय, योजनाओं एवं लाभार्थी सूची प्रदर्शित करने वाली पंचायत सूचना दीवार।
- योजनाओं एवं पंचायत जानकारी तक सुगम पहुंच हेतु क्यूआर कोड आधारित ग्राम सेवाएं।
- क्रमांकित परिसंपत्तियों के माध्यम से नागरिकों द्वारा खराबी रिपोर्टिंग हेतु स्ट्रीट लाइट निगरानी प्रणाली।
- वास्तविक समय निगरानी एवं जवाबदेही हेतु पंचायत परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग।
- नियमित समीक्षा एवं संरचित समाधान तंत्र सहित ग्राम शिकायत पंजी प्रणाली।

सततता के लिए रोडमैप

- पारदर्शी निधि प्रबंधन एवं वास्तविक समय निगरानी हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को डिजिटल उपकरणों एवं टी-गवर्नेंस पहलों में प्रशिक्षित करना।
- विशेष रूप से वृद्ध एवं निरक्षर नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
- योजना कार्यान्वयन में सुधार एवं समस्याओं में कमी हेतु नागरिक फीडबैक तंत्र को सुदृढ़ करना।
- सहभागी एवं पारदर्शी स्थानीय शासन हेतु ग्राम स्तरीय समितियों का नियमित संचालन जारी रखना।
- नियमित ग्राम सभा आधारित शिकायत निवारण एवं सहभागी योजना प्रक्रिया को बनाए रखना।

Panchayat with Good Governance

MOTHUKUPALLE

BLOCK PANCHAYAT: KOTEPALLY
DISTRICT PANCHAYAT: VIKARABAD
STATE: TELANGANA

3rd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 209912
- Total Population: 2,376
- Total Households: 703

KEY ACHIEVEMENTS

- Prepared a holistic, integrated GPDP with participation of 15 departments, approved by Gram Sabha and uploaded to portal
- Achieved 100% online upload of GP expenditure with accounts updated and closed in e-Gram Swaraj
- Geo-tagged all assets created in the Gram Panchayat for transparency and monitoring
- Operated functional CSC providing digital services, documentation, and access to government schemes
- Conducted Mahila Sabha and Bal Sabha for inclusive participatory governance
- Ensured timely delivery of basic citizen services with public information board for transparency
- Ensured accessibility of technologically integrated services for persons with disabilities

Conduct of regular Gram Sabhas

CHALLENGES FACED

- Limited capacity among local government to design regulations and innovative governance practices
- Centralised delivery mechanisms failing to account for local conditions and specific community needs
- Low awareness among residents about their rights, duties, and available digital services

APPROACH TAKEN

- Conducted capacity-building programmes on financial literacy and digital management in collaboration with SIRD and NGOs
- Formed village-level committees for water, sanitation, and waste management for localised transparent fund management
- Prioritised essential infrastructure development including roads, water supply, and sanitation based on village needs
- Utilised e-Panchayat platforms for online service access, transparency, and ease of governance

SUPPORT RECEIVED

- Digital infrastructure support through BharatNet, CSCs, UMANG, and DigiLocker
- Scheme benefits delivered directly through PMJDY, PM-MUDRA, PM-KISAN, and DBT without intermediaries
- Transparent governance enabled through MGNREGA digitalisation, e-Gram Swaraj, and GeM portal
- Digital literacy promoted through PMGDISHA; State schemes implemented online in convergence with Finance Commission grants

INNOVATIONS

- Panchayat Information Wall displaying income, expenditure, schemes, and beneficiary lists for public transparency
- QR Code-based Village Services for easy access to schemes and Panchayat information
- Street Light Monitoring System with numbered assets enabling fault reporting by citizens
- Geo-tagging of all Panchayat assets for real-time monitoring and accountability
- Village Complaint Register System with regular review and structured resolution mechanism

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Train elected representatives in digital tools and T-Governance initiatives for transparent fund management and real-time monitoring
- Improve digital literacy especially among elderly and illiterate residents
- Strengthen citizen feedback mechanisms to improve scheme implementation and reduce friction
- Continue village-level committee functioning for participatory and transparent local governance
- Sustain regular Gram Sabha-led grievance redressal and participatory planning

महिला हितैषी पंचायत

एक महिला हितैषी पंचायत वह है जो सुनिश्चित करती है:

- महिलाओं को समान अवसर
- गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण
- 100% संस्थागत प्रसव
- महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध शून्य अपराध
- महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- पाँच वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना
- महिलाओं हेतु बैंकिंग सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना
- मातृ मृत्यु दर में कमी लाना
- बालिकाओं के विद्यालयों में पूर्ण नामांकन एवं निरंतर उपस्थिति हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- महिला सभा का आयोजन एवं ग्राम सभाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना
- महिलाओं हेतु सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना
- महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु जागरूकता एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना
- सभी विकास कार्यक्रमों के लाभों तक महिलाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करना
- सभी बालिकाओं को निःशुल्क, समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कराना सुनिश्चित करना
- गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर सृजित करना
- सभी महिलाओं को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना
- महिला विकास हेतु बजट में पर्याप्त निधि सुनिश्चित करना (प०) महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन सुनिश्चित करना

WOMEN FRIENDLY PANCHAYAT

A WOMEN FRIENDLY PANCHAYAT IS ONE WHICH ENSURES:

- Equal opportunities to women
- 100% immunization of pregnant women
- 100% institutional delivery
- Zero crimes against women and girls
- Participation of women in socio-political, economic activities etc.

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Ensure quality nutritious food to all girl children aged under five years
- Facilitate banking service for woman
- Reduce the maternal mortality ratio
- Create environment for total enrolment and retention of girl children in school

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Ensure conduct of Mahila Sabha and their participation in Gram Sabhas
- Ensure safe and secured environment to women
- Create awareness and provide better health care facilities to women and girl child
- Ensure equal access to women for benefits under all development programs
- Ensure that all girls complete free, equitable and quality primary and secondary education
- Enroll poor women in SHGs and create opportunities for economic development activities
- Ensure equal access for all women to affordable and quality technical, vocational and tertiary education
- Earmark adequate funds in the budget for women development
- Ensuring equal wages for equal work to women

सुशासन युक्त पंचायत

बोक्कासमपालेम

ब्लॉक पंचायत: श्रीकालहस्ती
जिला पंचायत: तिरुपति
राज्य: आंध्र प्रदेश

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 197764
- कुल जनसंख्या: 650
- कुल परिवार: 215

मुख्य उपलब्धियाँ

- पिछले पाँच वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध दर्ज नहीं, जिससे सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण सुनिश्चित हुआ।
- 100% संस्थागत प्रसव के साथ शून्य मातृ मृत्यु एवं शून्य नवजात मृत्यु प्राप्त।
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित।
- बालिकाओं का 100% नामांकन एवं निरंतर उपस्थिति; कोई ड्रॉपआउट मामला नहीं।
- पाँच वर्ष से कम आयु की सभी बालिकाएं कम वजन की श्रेणी से बाहर; किशोरियों में एनीमिया में उल्लेखनीय कमी।
- पिछले पांच वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
- सभी परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध।
- 55% निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों एवं महिला सरपंच के सक्रिय नेतृत्व के साथ सशक्त महिला नेतृत्व आधारित शासन।
- 17 स्वयं सहायता समूहों का मजबूत वित्तीय आधार (लगभग 4 करोड़ कोष; 145 लाख बैंक लिंकेज; 37.05 लाख सहायता वितरित)।
- डेयरी (639 पशु), पशुपालन एवं कलमकारी कला संवर्धन जैसी महिला-केंद्रित आजीविका गतिविधियां।

गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए टीकाकरण अभियान

चुनौतियाँ

- महिला उद्यमिता विस्तार हेतु उन्नत कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता।
- स्वयं सहायता समूह उत्पादों (कलमकारी, डेयरी आदि) हेतु सीमित बाजार संपर्क, ब्रांडिंग एवं भंडारण अवसंरचना।
- महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के विस्तार हेतु औपचारिक ऋण तक सीमित पहुंच।
- कुछ महिला समूहों में डिजिटल साक्षरता की कमी।
- महिला नेतृत्व भागीदारी के प्रति प्रारंभिक सामाजिक संकोच एवं सांस्कृतिक बाधाएं।
- सीसीटीवी निगरानी जैसी उन्नत सुरक्षा अवसंरचना की आवश्यकता।
- महिला संसाधन केंद्र एवं प्रशिक्षण सुविधाओं जैसी अतिरिक्त अवसंरचना की आवश्यकता।

दृष्टिकोण

- नियमित महिला सभाओं एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से सहभागी शासन को अपनाया गया, जिससे योजना निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई।
- शक्ति ऐप स्थापना एवं नामित अधिकारियों द्वारा नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान।
- आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर स्वास्थ्य निगरानी एवं जागरूकता, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित हुए।
- आयरन युक्त आहार (सहजन पत्ती, रागी), एनीमिया जांच एवं पोषण अभियान अभिसरण सहित पोषण हस्तक्षेप।
- क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाना।

प्राप्त समर्थन

- पीएमएमवीवाई, पीएमजेएवाई (आभा), पीएमएवाई-जी, आईसीडीएस, पोषण अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, स्त्री शक्ति, दीपम एवं मनरेगा सहित केंद्र एवं राज्य योजनाओं का अभिसरण।
- बैंक लिंकेज, सामुदायिक निवेश कोष (₹13.60 लाख) एवं ट्री निधि (₹6.5 लाख) के माध्यम से वित्तीय सहयोग।
- एनएचएम, आईसीडीएस एवं अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं (आशा, आंगनवाड़ी) के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं।
- महिला सुरक्षा हेतु ग्राम सचिवालय, स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग।
- डेयरी आधारित आजीविका हेतु श्रीकालहस्ती दुग्ध सहकारी समिति के साथ सहयोग।

नवाचार

- महिला सुरक्षा हेतु शक्ति ऐप ख़ एसओएस अलर्ट, लाइव ट्रैकिंग एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया सक्षम करने हेतु सार्वभौमिक स्थापना एवं नियमित प्रशिक्षण सहयोग।
- महिला-नेतृत्व वाली डेयरी अर्थव्यवस्था ख़ महिलाओं द्वारा संचालित 639 पशुओं से स्थायी आय एवं परिवार की अर्थव्यवस्था को मजबूती।
- कलमकारी कला संवर्धन ख़ महिलाओं हेतु सतत आजीविका के रूप में पारंपरिक वस्त्र कला का पुनर्जीवन।
- स्वच्छ रथम् परिपत्र अर्थव्यवस्था मॉडल ख़ सूखे कचरे के बदले आवश्यक वस्तुओं का वितरण, जिससे कचरे से संपदा की अवधारणा को बढ़ावा।
- महिलाओं हेतु गोकुलम शेड ख़ मनरेगा के अंतर्गत पशु शेड निर्माण द्वारा आजीविका सुरक्षा।

सततता के लिए रोडमैप

- महिलाओं हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार।
- स्वयं सहायता समूह उत्पादों हेतु बाजार संपर्क, ब्रांडिंग एवं मूल्य संवर्धन को मजबूत करना।
- महिलाओं की डिजिटल साक्षरता एवं ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
- महिला संसाधन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं भंडारण सुविधाओं जैसी अतिरिक्त अवसंरचना विकसित करना।
- सीसीटीवी निगरानी एवं सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों सहित सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- सतत निगरानी के माध्यम से शून्य अपराध, शून्य मातृ एवं नवजात मृत्यु की स्थिति बनाए रखना।
- महिला-नेतृत्व वाले डेयरी, पशुपालन एवं कलमकारी उद्यमों का विस्तार।

Women Friendly Panchayat

BOKKASAMPALEM

BLOCK PANCHAYAT: SRIKALAHASTI
DISTRICT PANCHAYAT: TIRUPATI
STATE: ANDHRA PRADESH

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 197764
- Total Population: 650
- Total Households: 215

KEY ACHIEVEMENTS

- Zero crime against women reported in the last five years, ensuring a safe and secure environment.
- Zero maternal deaths and zero neonatal deaths achieved with 100% institutional deliveries.
- Full immunisation coverage for pregnant and lactating women.
- 100% enrolment and retention of girl children with zero dropout cases.
- No child marriage reported in the last five years.
- All girl children under 5 years are not underweight; anaemia significantly reduced among adolescent girls.
- 100% households have access to safe drinking water through tap connections.
- Strong women-led governance with 55% elected women representatives and active leadership of a woman Sarpanch.
- 17 SHGs with strong financial base (approx. ₹4 crore corpus; ₹145 lakh bank linkage; ₹37.05 lakh assistance provided).
- Women-centric livelihood activities including dairy (639 cattle), livestock, and Kalamkari art promotion.

Immunisation drives for pregnant and lactating women

CHALLENGES FACED

- Need for enhanced skill development programs to expand women entrepreneurship.
- Limited market linkages, branding, and storage infrastructure for SHG products (Kalamkari, dairy, etc.).
- Limited access to formal credit for scaling women-led enterprises.
- Digital literacy gaps among certain groups of women.
- Initial social hesitation and cultural barriers to women's leadership participation.
- Need for advanced safety infrastructure such as CCTV surveillance.
- Requirement for additional infrastructure like women resource centres and training facilities.

APPROACH TAKEN

- Adoption of participatory governance through regular Mahila Sabhas and Gram Sabhas ensuring women's involvement in planning and decision-making.
- Strong focus on women safety through Shakti App installation and periodic training by designated officials.
- Door-to-door health monitoring and awareness by ASHA and Anganwadi workers ensuring maternal and child health outcomes.
- Nutritional interventions including iron-rich diet (moringa leaves, ragi), anaemia screening, and POSHAN Abhiyaan convergence.
- Strengthening SHGs through capacity building, financial inclusion, and bank linkages.

SUPPORT RECEIVED

- Convergence of Central and State schemes including PMMVY, PMJAY (ABHA), PMAY-G, ICDS, POSHAN Abhiyaan, Sukanya Samriddhi Yojana, Stree Sakthi, Deepam, and MGNREGS.
- Financial support through bank linkages, Community Investment Fund (₹13.60 lakh), and Tree Nidhi (₹6.5 lakh).
- Health and nutrition services through NHM, ICDS, and frontline workers (ASHA, Anganwadi).
- Support from Village Secretariat, local police, and administration for women safety.
- Collaboration with Srikalahasti Milk Cooperative for dairy-based livelihoods.

INNOVATIONS

- Shakti App for Women Safety — Universal installation enabling SOS alerts, live tracking, and emergency response with regular training support.
- Women-led Dairy Economy — 639 cattle managed by women providing steady income and strengthening household economy.
- Kalamkari Art Promotion — Revival of traditional textile art as a sustainable livelihood for women.
- Swachh Ratham Circular Economy — Dry waste exchanged for essential commodities, promoting waste-to-wealth practices.
- Gokulam Sheds for Women — Asset creation through cattle sheds under MGNREGS supporting livelihood security.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Expand skill development and entrepreneurship training programs for women.
- Strengthen market linkages, branding, and value addition for SHG products.
- Enhance digital literacy and access to online services for women.
- Develop additional infrastructure such as women resource centres, training centres, and storage facilities.
- Strengthen safety infrastructure including CCTV surveillance and safe public spaces.
- Continue zero crime, zero maternal and neonatal death status through sustained monitoring.
- Expand women-led dairy, livestock, and Kalamkari enterprises.

महिला हितैषी पंचायत

झिकरहाटी पूर्व

ब्लॉक पंचायत: पाकुड़
जिला पंचायत: पाकुड़
राज्य: झारखंड

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 114229
- कुल जनसंख्या: 12,528
- कुल परिवार: 5,990

मुख्य उपलब्धियाँ

- पिछले पाँच वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं घरेलू हिंसा के शून्य मामले।
- 100% संस्थागत प्रसव एवं पूर्ण एएनसी कवरेज के साथ शून्य मातृ मृत्यु।
- 100% आईएफए पूरक पोषण एवं पोषण सहायता; टीबी, कालाजार एवं फाइलेरिया का उन्मूलन।
- बालिकाओं में अत्यंत कम एनीमिया प्रसार (1,845 में केवल 5 मामले)।
- सभी शैक्षणिक स्तरों पर बालिकाओं का 100% नामांकन एवं उच्च संक्रमण दर; नामांकन में लिंग अनुपात बालिकाओं के पक्ष में।
- 100% महिलाएं स्वयं सहायता समूहों, बैंक खातों एवं वित्तीय समावेशन प्रणाली से जुड़ी।
- 29 से अधिक महिला-नेतृत्व वाले उद्यम संचालित (पिंक टोटो, सखी मार्ट, सीएसपी, पोल्ट्री, दीदी बाड़ी आदि)।
- मनरेगा में 61.05% महिला भागीदारी (राज्य में सर्वोच्च)।
- 190-220 प्रतिभागियों के साथ मासिक महिला सभाएं, जिससे सहभागी शासन सुनिश्चित हुआ।
- महिला नेतृत्व सुदृढ़ ख 25 वार्ड सदस्यों में 14 महिलाएं; मुखिया एवं उप-मुखिया दोनों महिलाएं।
- पंचायत में सीसीटीवी कैमरे एवं स्ट्रीट लाइट स्थापना द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित।
- प्रत्येक माह (24 तारीख) रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसे जिला प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त।

महिला सभा

चुनौतियाँ

- दूरस्थ, जनजातीय एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र; कम साक्षरता एवं गहरी लैंगिक असमानताएं।
- मासिक धर्म स्वच्छता, लैंगिक मुद्दों एवं महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रारंभिक सामाजिक कलंक।
- महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों हेतु सीमित बाजार पहुंच।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों हेतु उन्नत नेतृत्व प्रशिक्षण की आवश्यकता।
- जागरूकता गतिविधियों के दस्तावेजीकरण एवं अभिलेख प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता।
- आर्थिक निर्भरता एवं उन्नत वित्तीय एवं विपणन अवसंरचना तक सीमित पहुंच।

दृष्टिकोण

- एलएसडीजी ढांचे के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका एवं लैंगिक पहलों के एकीकरण के माध्यम से अभिसरण आधारित शासन।
- प्रोजेक्ट प्राण (संस्थागत सुधार) एवं प्रोजेक्ट बदलाव (व्यवहार परिवर्तन एवं महिला सशक्तिकरण) का क्रियान्वयन।
- सहभागी योजना एवं निर्णय प्रक्रिया हेतु नियमित महिला सभा, सखी संवाद एवं सखी दिवस।
- "बात तो करनी होगी" जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियान, जिनके माध्यम से मासिक धर्म, घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह जैसे मुद्दों पर संवाद।
- वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास हेतु सार्वभौमिक स्वयं सहायता समूह लामबंदी।
- आशा/सहिया कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर स्वास्थ्य निगरानी, मासिक स्वास्थ्य शिविर एवं निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।

प्राप्त समर्थन

- एनएचएम, आईसीडीएस, एनआरएलएम, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एवं आरएसईटीआई से स्वास्थ्य एवं आजीविका पहलों हेतु अभिसरण सहयोग।
- प्रोजेक्ट प्राण एवं प्रोजेक्ट बदलाव के अंतर्गत जिला प्रशासन का रणनीतिक सहयोग।
- स्वयं सहायता समूह सुदृढ़ीकरण एवं जेंडर रिसोर्स पर्सन हेतु जेएसएलपीएस का सहयोग।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर, टीकाकरण एवं पोषण सेवाओं हेतु सहयोग।
- बाल विवाह, घरेलू हिंसा एवं लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता हेतु सीडीपीओ एवं जिला टीमों का सहयोग।
- वित्तीय समावेशन हेतु बैंकिंग संस्थानों एवं एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रमों का सहयोग।

नवाचार

- प्रोजेक्ट प्राण एवं प्रोजेक्ट बदलाव ख एकीकृत शासन एवं व्यवहार परिवर्तन मॉडल।
- मेरी पंचायत ऐप ख वास्तविक समय शिकायत निवारण एवं शासन में पारदर्शिता।
- मासिक रक्तदान शिविर - समुदाय आधारित स्वास्थ्य पहल, जिसे जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त।
- पिंक टोटो पहल ख आजीविका सृजन हेतु महिला-नेतृत्व वाली परिवहन सेवा।
- मैय्या कक्ष एवं मदर-चाइल्ड कॉर्नर ख स्वास्थ्य एवं परामर्श हेतु लैंगिक उत्तरदायी अवसंरचना।

सततता के लिए रोडमैप

- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों हेतु संरचित नेतृत्व एवं शासन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- दस्तावेजीकरण, निगरानी प्रणालियों एवं डिजिटल डैशबोर्ड को मजबूत करना।
- दीर्घकालिक सततता हेतु एलएसडीजी संकेतकों को जीपीडीपी योजना में एकीकृत करना।
- स्वयं सहायता समूह उद्यमों का विस्तार एवं आजीविका अवसरों का विविधीकरण।
- पिंक टोटो, दीदी कैफे, सखी मार्ट एवं बर्तन बैंक जैसे सफल मॉडलों का विस्तार।
- व्यवहार परिवर्तन अभियान एवं लैंगिक जागरूकता पहलों को निरंतर जारी रखना।
- संस्थागत गुणवत्ता एवं पर्यावरणीय मानकों हेतु आईएसओ प्रमाणन (9001 एवं 14001) की दिशा में कार्य करना।

JHIKARHATI EAST

BLOCK PANCHAYAT: PAKUR
DISTRICT PANCHAYAT: PAKUR
STATE: JHARKHAND

Women Friendly Panchayat

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 114229
- Total Population: 12,528
- Total Households: 5,990

KEY ACHIEVEMENTS

- Zero crime against women and no domestic violence cases reported in the last five years.
- Zero maternal deaths with 100% institutional deliveries and full ANC coverage.
- 100% IFA supplementation and nutrition support; elimination of TB, Kala-azar, and Filariasis.
- Extremely low anaemia prevalence among girls (only 5 out of 1,845 cases).
- 100% enrolment and high transition rates of girls across all school levels; gender ratio in enrolment favourable to girls.
- 100% women linked to SHGs, bank accounts, and financial inclusion systems.
- 29+ women-led enterprises operational (Pink TOTO, Sakhi Mart, CSP, poultry, Didi Badi, etc.).
- 61.05% women participation in MGNREGS (State topper).
- Monthly Mahila Sabhas with 190–220 participants ensuring participatory governance.
- Women leadership strengthened: 14 out of 25 ward members are women; Mukhiya and Up-Mukhiya are women.
- Installation of CCTV cameras and streetlights across Panchayat ensuring safety.
- Monthly blood donation camp (24th of every month), recognized by District Administration.

Mahila Sabha

CHALLENGES FACED

- Remote, tribal, and socio-economically vulnerable region with low literacy and entrenched gender norms.
- Initial stigma around menstrual hygiene, gender issues, and women's participation.
- Limited market access affecting scalability of women-led enterprises.
- Need for enhanced leadership training for Elected Women Representatives (EWRs).
- Documentation and record-keeping of awareness activities require strengthening.
- Economic dependency and limited access to advanced financial and marketing infrastructure.

APPROACH TAKEN

- Convergence-driven governance through integration of health, education, livelihoods, and gender initiatives under LSDG framework.
- Implementation of Project PRAAN (institutional reforms) and Project BADLAOW (behavioural transformation and women empowerment).
- Regular Mahila Sabha, Sakhi Samvad, and Sakhi Diwas for participatory planning and decision-making.
- Behavioural change campaigns like "Baat To Karni Hogi" addressing menstruation, domestic violence, and child marriage.
- Universal SHG mobilization ensuring financial inclusion and enterprise development.
- Door-to-door health tracking, monthly health camps, and continuous follow-up by ASHA/Sahiya workers.

SUPPORT RECEIVED

- Convergence support from NHM, ICDS, NRLM, PMEGP, PMFME, and RSETI for health and livelihood initiatives.
- Strategic support from District Administration under Project PRAAN and Project BADLAOW.
- JSLPS support for SHG strengthening and Gender Resource Persons.
- Health Department support for camps, immunization, and nutrition services.
- CDPO and district teams for awareness on child marriage, domestic violence, and gender issues.
- Banking institutions and SHG-bank linkage programs for financial inclusion.

INNOVATIONS

- Project PRAAN & Project BADLAOW — Integrated governance and behavioural transformation models.
- Meri Panchayat App — Real-time grievance redressal and transparency in governance.
- Monthly Blood Donation Camp — Community-driven health initiative recognized by district.
- Pink TOTO Initiative — Women-led transport services for livelihood generation.
- Mayya Kaksh & Mother-Child Corners — Gender-responsive infrastructure for health and counselling.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Provide structured leadership and governance training for Elected Women Representatives.
- Strengthen documentation, monitoring systems, and digital dashboards.
- Integrate LSDG indicators into GPDP planning for long-term sustainability.
- Expand SHG enterprises and diversify livelihood opportunities.
- Scale up successful models like Pink TOTO, Didi Café, Sakhi Mart, and Bartan Bank.
- Continue behavioural change campaigns and gender awareness initiatives.
- Work towards ISO certification (9001 & 14001) for institutional quality and environmental standards.

महिला हितैषी पंचायत

फसलवाड़ी

ब्लॉक पंचायत: संगारेड्डी
जिला पंचायत: संगारेड्डी
राज्य: तेलंगाना

3rd PRIZE

तृतीय पुरस्कार-संयुक्त

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 206863
- कुल जनसंख्या: 2,844
- कुल परिवार: 802

मुख्य उपलब्धियाँ

- महिलाओं के विरुद्ध शून्य अपराध; हिंसा का कोई मामला दर्ज नहीं।
- 100% संस्थागत प्रसव (38/38) के साथ शून्य मातृ मृत्यु।
- पाँच वर्ष से कम आयु की बालिकाओं में शून्य कुपोषण एवं शून्य एनीमिया।
- सभी शिक्षा स्तरों पर बालिकाओं का 100% नामांकन एवं संक्रमण दर।
- सभी बच्चों (0ख6 वर्ष) का आईसीडीएस के अंतर्गत पंजीकरण; आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मजबूत एएनसी एवं पीएनसी कवरेज।
- सभी पात्र विधवाओं को पेंशन (196 लाभार्थी) उपलब्ध।
- 4.14 करोड़ बैंक लिंकेज (2023ख24)।
- 48 लाख स्त्रीनिधि ऋण।
- 36 लाख सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) सहायता।
- मनरेगा मजदूरी रोजगार में 83.63% महिला भागीदारी।
- मिशन शक्ति का सक्रिय क्रियान्वयन:
- मिशन संबल: हिंसा के शून्य मामले
- मिशन समर्थ्य: महिला उद्यमिता को बढ़ावा
- स्थानीय दुकानों, सूक्ष्म उद्यमों एवं स्वयं सहायता समूह आधारित गतिविधियों सहित महिला-नेतृत्व वाले उद्यम।
- समेकित चिकित्सीय एवं कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु वन स्टॉप सेंटर की स्थापना।

एकीकृत चिकित्सा एवं कानूनी सहायता हेतु वन स्टॉप सेंटर

चुनौतियाँ

- पितृसत्तात्मक सोच एवं सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं की निरंतरता।
- महिलाओं हेतु सीमित आजीविका अवसर एवं भूमि/संपत्ति तक सीमित पहुंच।
- महिला नेताओं हेतु उन्नत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता।
- स्थानीय स्तर पर कौशल आधारित शिक्षा एवं रोजगार अवसरों का अभाव।
- उन्नत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अवसंरचना तक सीमित पहुंच।
- संस्थागत कमियां: सीमित समर्पित बजट, नीतिगत स्पष्टता एवं हितधारक अभिसरण।
- दस्तावेजीकरण संबंधी कमियां (जैसे बाल विवाह जागरूकता अभिलेखों का उचित रखरखाव न होना)।

दृष्टिकोण

- लैंगिक मुद्दों पर निरंतर जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- वित्तीय समावेशन एवं सामूहिक सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह नेटवर्क को मजबूत एवं विस्तारित करना।
- महिलाओं हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- शासन एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- संरक्षण एवं सशक्तिकरण को एकीकृत करते हुए मिशन शक्ति ढांचे का क्रियान्वयन।
- समेकित सहायता सेवाओं हेतु वन स्टॉप सेंटर एवं शक्ति सदन की स्थापना।

प्राप्त समर्थन

- स्वयं सहायता समूह सुदृढ़ीकरण हेतु एसईआरपी (सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी) का मजबूत सहयोग।
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य विभाग (एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) का सहयोग।
- मनरेगा मंच के माध्यम से मजदूरी रोजगार में महिलाओं की उच्च भागीदारी सुनिश्चित।
- बैंक, स्त्रीनिधि एवं सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) के माध्यम से वित्तीय लिंकेज।
- मिशन शक्ति, आईसीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों सहित राज्य एवं केंद्र सरकार योजनाओं का सहयोग।
- महिलाओं के विरुद्ध शून्य अपराध की पुष्टि हेतु पुलिस सत्यापन।

नवाचार

- वन स्टॉप सेंटर + शक्ति सदन ख चिकित्सीय, कानूनी एवं आश्रय सेवाओं सहित समेकित सहायता प्रणाली।
- अम्मा कु अक्षरमाला नाइट स्कूल ख महिलाओं हेतु वयस्क साक्षरता कार्यक्रम।
- महिला ई-हाट (प्रस्तावित) ख महिला उद्यमियों हेतु उत्पाद विपणन का डिजिटल मंच।
- केएसआर इंडस्ट्रीज (मोजा निर्माण इकाई) ख स्थानीय रोजगार सृजन करने वाला महिला-नेतृत्व उद्यम।
- मिशन शक्ति (संबल एवं समर्थ्य) ख एकीकृत संरक्षण एवं सशक्तिकरण मॉडल।

सततता के लिए रोडमैप

- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को मजबूत करना।
- स्थानीय कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र स्थापित करना।
- महिला-केंद्रित पहलों हेतु बजट आवंटन एवं संस्थागत सहयोग बढ़ाना।
- जागरूकता एवं हस्तक्षेप गतिविधियों हेतु दस्तावेजीकरण एवं निगरानी प्रणालियों में सुधार।
- स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यमों का विस्तार एवं बाजार संपर्क को बढ़ावा।
- महिलाओं में डिजिटल समावेशन एवं साक्षरता को प्रोत्साहित करना।
- शून्य मातृ मृत्यु एवं शून्य एनीमिया की स्थिति बनाए रखने हेतु स्वास्थ्य निगरानी जारी रखना।

Women Friendly Panchayat

FASALWADI

BLOCK PANCHAYAT: SANGAREDDY
DISTRICT PANCHAYAT: SANGAREDDY
STATE: TELANGANA

3rd PRIZE

Third Prize-Joint

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 206863
- Total Population: 2,844
- Total Households: 802

KEY ACHIEVEMENTS

- Zero crime against women; no cases of violence reported.
- Zero maternal deaths with 100% institutional deliveries (38/38).
- Zero underweight and zero anaemia among girl children under 5 years.
- 100% enrolment and transition rates of girls across all education levels.
- All children (0–6 years) registered under ICDS; strong ANC and PNC coverage through Anganwadi centres.
- 100% eligible widows receiving pensions (196 beneficiaries).
- ₹4.14 crore bank linkage (2023–24)
- ₹48 lakh Streenidhi loans
- ₹36 lakh CIF support
- 83.63% women participation in MGNREGS wage employment.
- Active implementation of Mission Shakti:
- Mission Sambal: Zero violence cases
- Mission Samarthya: Promotion of women entrepreneurship
- Women-led enterprises including local shops, micro-businesses, and SHG-based activities.
- One Stop Centre providing integrated medical and legal support.

One Stop Centre for integrated medical and legal support

CHALLENGES FACED

- Persistence of patriarchal mindset and socio-cultural barriers.
- Limited livelihood opportunities and restricted access to land/ property for women.
- Need for enhanced training and capacity-building for women leaders.
- Lack of local skill-based education and employment opportunities.
- Limited access to advanced health and hygiene infrastructure.
- Institutional gaps: limited dedicated budget, policy clarity, and stakeholder convergence.
- Documentation gaps (e.g., child marriage awareness records not properly maintained).

APPROACH TAKEN

- Conducted continuous awareness campaigns and training programmes addressing gender issues.
- Strengthened and expanded SHG network for financial inclusion and collective empowerment.
- Ensured access to education, healthcare, and livelihood opportunities for women.
- Promoted women's participation in governance and decision-making processes.
- Implemented Mission Shakti framework integrating protection and empowerment.
- A Established One Stop Centre and Shakti Sadan for integrated support services.

SUPPORT RECEIVED

- Strong support from SERP (Society for Elimination of Rural Poverty) for SHG strengthening.
- Support from Health Department (ANM, Anganwadi workers) for maternal and child health.
- MGNREGA platform enabling high women participation in wage employment.
- Financial linkage through banks, Streenidhi, and Community Investment Fund (CIF).
- Support from State and Central Government schemes including Mission Shakti, ICDS, and welfare programs.
- Police verification confirming zero crime against women.

INNOVATIONS

- One Stop Centre + Shakti Sadan – Integrated support system (medical, legal, shelter).
- Amma Ku Aksharamala Night School – Adult literacy programme for women.
- Mahila E-Haad (Upcoming) – Digital platform for women entrepreneurs to market products.
- KSR Industries (Socks Manufacturing Unit) – Women-led enterprise generating local employment.
- Mission Shakti (Sambal & Samarthya) – Integrated protection and empowerment model.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Strengthen leadership training and capacity-building of Elected Women Representatives.
- Establish local skill development and entrepreneurship facilitation centres.
- Enhance budget allocation and institutional support for women-focused initiatives.
- Improve documentation and monitoring systems for awareness and interventions.
- Expand SHG-based enterprises and promote market linkages.
- Promote digital inclusion and literacy among women.
- Continue health monitoring to sustain zero maternal deaths and zero anaemia.

महिला हितैषी पंचायत

बैकुंठापुर

ब्लॉक पंचायत: हेजामारा
जिला पंचायत: पश्चिम त्रिपुरा
राज्य: त्रिपुरा

3rd PRIZE

तृतीय पुरस्कार-संयुक्त

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 254142
- कुल जनसंख्या: 3,035
- कुल परिवार: 703

मुख्य उपलब्धियाँ

- 100% संस्थागत प्रसव, पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल एवं 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित।
- नियमित निगरानी एवं सहयोग सेवाओं के माध्यम से शून्य मातृ मृत्यु तथा मजबूत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणाम।
- मजबूत सामुदायिक सतर्कता एवं जागरूकता के कारण बाल विवाह एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध के शून्य मामले।
- बालिकाओं का शून्य ड्रॉपआउट एवं शिक्षा तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित।
- विद्यालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में सैनिटरी वेंडिंग मशीनों की स्थापना, जिससे मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार एवं अनुपस्थिति में कमी।
- सार्वजनिक संस्थानों में बेबी फीडिंग रूम/कॉर्नर की स्थापना, जिससे माताओं एवं शिशुओं की गरिमा एवं देखभाल सुनिश्चित।
- प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे एवं सौर स्ट्रीट लाइट स्थापना द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित।
- 29 स्वयं सहायता समूह आजीविका गतिविधियों में सक्रिय, जिससे वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित।
- कौशल प्रशिक्षण हस्तक्षेपों के बाद महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों द्वारा प्रतिवर्ष 3ख5 लाख आय अर्जित।

शिशु आहार कक्ष/कोने

चुनौतियाँ

- जनजातीय एवं भौगोलिक रूप से सीमित क्षेत्र में वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक संसाधनों की कमी।
- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं, जिनके कारण प्रारंभिक स्तर पर शासन एवं आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही।
- महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों हेतु आजीविका असुरक्षा एवं सीमित बाजार अवसर।
- निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के अभाव में मजबूत प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता।
- महिला-केंद्रित कार्यक्रमों में दीर्घकालिक सहभागिता एवं निरंतरता बनाए रखना।

दृष्टिकोण

- महिला सभाओं, सामुदायिक सहभागिता एवं योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सहभागी शासन।
- पंचायत प्रशासन, स्वयं सहायता समूहों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सामुदायिक संस्थाओं के बीच मजबूत समन्वय।
- नियमित जांच, एएनसी/पीएनसी सेवाओं एवं पोषण सहायता के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान।
- वेंडिंग मशीनों एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा।
- हस्तशिल्प, मोमबत्ती निर्माण, चप्पल निर्माण, पशुपालन एवं उत्पादक समूहों जैसे स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यमों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण।

प्राप्त समर्थन

- स्वयं सहायता समूह सुदृढ़ीकरण एवं आजीविका संवर्धन हेतु त्रिपुरा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (टीआरएलएम) का सहयोग।
- मोतियाबिंद जांच एवं नि:शुल्क सर्जरी हेतु द होप फाउंडेशन के साथ सहयोग।
- स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं (आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी) का सहयोग।
- सीसीटीवी, सैनिटरी वेंडिंग मशीनों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना हेतु विभिन्न सरकारी विभागों का सहयोग।
- कौशल विकास एवं उद्यम संवर्धन में कुचुक बेरम सीएलएफ की भूमिका।
- समग्र विकास हेतु विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार योजनाओं का अभिसरण।

नवाचार

- मोबाइल सीएससी वैन (महिला-नेतृत्व) ख डिजिटल एवं ई-गवर्नेंस सेवाओं की घर-घर उपलब्धता, जिससे समावेशन एवं आजीविका को बढ़ावा।
- बालिकाओं हेतु जूडो एवं थांगटा प्रशिक्षण ख पारंपरिक एवं आधुनिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां प्राप्त।
- एकीकृत वन स्टॉप सेंटर ख संकटग्रस्त महिलाओं हेतु एकल खिड़की सहायता प्रणाली (चिकित्सीय, कानूनी, परामर्श एवं पुलिस सहायता)।
- सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र ख कौशल विकास, उद्यमिता एवं आजीविका संवर्धन हेतु समर्पित मंच।
- बेबी फीडिंग रूम/कॉर्नर ख सार्वजनिक संस्थानों में माताओं हेतु गरिमा, गोपनीयता एवं देखभाल सुनिश्चित करना।

सततता के लिए रोडमैप

- स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यमों का विस्तार एवं महिलाओं हेतु आजीविका अवसरों का विविधीकरण।
- उन्नत कौशल विकास एवं उद्यमिता हेतु सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र को मजबूत करना।
- निरंतर जागरूकता एवं सतर्कता के माध्यम से शून्य बाल विवाह एवं महिलाओं के विरुद्ध शून्य अपराध की स्थिति बनाए रखना।
- नियमित निगरानी एवं जांच कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करना।
- बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं नेतृत्व निर्माण हेतु आत्मरक्षा एवं खेल प्रशिक्षण का विस्तार।
- सीएससी सेवाओं एवं ई-गवर्नेंस पहलों के विस्तार द्वारा डिजिटल समावेशन को मजबूत करना।
- नेतृत्व एवं शासन भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

Women Friendly Panchayat

BAIKUNTHAPUR

BLOCK PANCHAYAT: HEZAMARA
DISTRICT PANCHAYAT: WEST TRIPURA
STATE: TRIPURA

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 254142
- Total Population: 3,035
- Total Households: 703

3rd PRIZE

Third Prize-Joint

KEY ACHIEVEMENTS

- 100% institutional deliveries, full antenatal care, and 100% immunization coverage ensured.
- Zero maternal mortality and strong maternal & child health outcomes through regular monitoring and support services.
- Zero cases of child marriage and no crimes against women due to strong community vigilance and awareness.
- Zero dropout of girl children with continuous access to education.
- Sanitary vending machines installed in schools and health centres, improving menstrual hygiene and reducing absenteeism.
- Baby Feeding Rooms/Corners established in public institutions for dignity and care of mothers and infants.
- CCTV cameras and solar street lights installed across key locations, enhancing safety and security.
- 29 SHGs actively engaged in livelihood activities, ensuring financial inclusion and economic empowerment.
- Women-led enterprises generating ₹3–5 lakh annually post skill training interventions.

Baby Feeding Rooms/Corners

CHALLENGES FACED

- Limited financial and infrastructural resources in a tribal and geographically constrained area.
- Socio-cultural barriers initially restricting women's participation in governance and economic activities.
- Livelihood insecurity and limited market opportunities for women-led enterprises.
- Absence of elected PRI representatives requiring strong administrative coordination.
- Sustaining long-term engagement and continuity of women-centric programmes.

APPROACH TAKEN

- Participatory governance through Mahila Sabhas, community engagement, and convergence of schemes.
- Strong coordination between Panchayat administration, SHGs, ASHA workers, Anganwadi workers, and community institutions.
- Focus on maternal and child health through regular screening, ANC/PNC services, and nutrition support.
- Promotion of menstrual hygiene through vending machines and awareness campaigns.
- Economic empowerment through SHG-based enterprises such as handicrafts, candle making, slipper manufacturing, livestock rearing, and producer groups.

SUPPORT RECEIVED

- Support from Tripura State Rural Livelihood Mission (TRLM) for SHG strengthening and livelihood promotion.
- Collaboration with The Hope Foundation for cataract screening and free surgeries.
- Support from health departments and frontline workers (ASHA, ANM, Anganwadi) for health and nutrition services.
- Assistance from government departments for installation of CCTV, sanitary vending machines, and training programmes.
- Role of Kuchuk Berem CLF in skill development and enterprise promotion.
- Convergence with various State and Central Government schemes for holistic development.

INNOVATIONS

- Mobile CSC Van (Women-led) – Doorstep delivery of digital and e-governance services, enhancing inclusion and livelihood.
- Judo & ThangTa Training for Girls – Traditional and modern self-defence training leading to national-level achievements.
- Integrated One Stop Centre – Single-window support system for women in distress (medical, legal, counselling, police).
- Community Managed Training Centre – Dedicated platform for skill development, entrepreneurship, and livelihood promotion.
- Baby Feeding Rooms/Corners – Ensuring dignity, privacy, and care for mothers in public institutions.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Expand SHG-based enterprises and diversify livelihood opportunities for women.
- Strengthen Community Managed Training Centre for advanced skill development and entrepreneurship.
- Sustain zero child marriage and zero crime against women through continuous awareness and vigilance.
- Enhance health and nutrition services through regular monitoring and screening programmes.
- Scale up self-defence and sports training for girls to build confidence and leadership.
- Strengthen digital inclusion through expansion of CSC services and e-governance initiatives.
- Promote greater participation of women in leadership and governance roles.

क्लाइमेट एक्शन

विशेष पंचायत पुरस्कार

क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2025 में पूर्व के दो पुरस्कारों ख्र ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार एवं कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार ख्र को सम्मिलित कर की गई है। यह पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं जलवायु परिवर्तन शमन हेतु कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

जलवायु कार्रवाई की दिशा में कार्य करने वाली पंचायत वह है जो:

- शुद्ध शून्य (Net Zero) कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित करती है।
- पवन, सौर एवं जलविद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के 100% उपयोग को बढ़ावा देती है।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु प्रतिपूरक एवं शमन उपाय अपनाती है।
- सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल उपायों के माध्यम से ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति प्राप्त करना।
- 100% अपशिष्ट प्रबंधन एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावी निस्तारण।
- प्लास्टिक का शून्य उपयोग।
- घरेलू, परिवहन एवं औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण।
- वनों एवं जैव विविधता का संरक्षण एवं विस्तार।
- घरेलू, परिवहन एवं औद्योगिक क्षेत्रों से कार्बन उत्सर्जन में कमी।
- पारंपरिक एवं नवाचारी उपायों के माध्यम से मृदा एवं जल संरक्षण।

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- कुल कार्बन उत्सर्जन एवं ऊर्जा आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु आधारभूत सर्वेक्षण करना।
- पंचायत क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन तंत्र लागू करना।
- जलवायु लक्ष्यों हेतु समुदाय, प्रशासन, संगठनों एवं अन्य हितधारकों में जागरूकता एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करना।
- विद्युत उत्पादन, जल ताप एवं शीतलन तथा परिवहन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में बायोगैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- जैविक कृषि को बढ़ावा देना एवं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना।
- कार्बन प्रतिपूरण हेतु पारंपरिक उपायों को सामुदायिक आय के संभावित स्रोत के रूप में अपनाना।
- व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाना एवं वन संरक्षण को बढ़ावा देना।
- ट्री बैंकिंग एवं ट्री मॉर्गेजिंग जैसे नवाचारी वित्तीय मॉडल लागू करना।
- जलवायु कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (ळच्क्च) निधि एवं अन्य सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का अभिसरण एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

CLIMATE ACTION SPECIAL PANCHAYAT AWARD (CASPA)

CASPA has been instituted during the year 2025 by clubbing earlier 2 awards of Gram Urja Swaraj Vishesh Panchayat Puraskar and Carbon Neutral Vishesh Panchayat Puraskar. This award is for Gram Panchayats (GPs) for their performance regarding adoption and usage of renewable energy and efforts towards achieving carbon neutrality towards mitigation of climate change.

A PANCHAYAT TAKING MEASURES TOWARDS CLIMATE ACTION IS ONE THAT:

- Achieves net zero carbon emissions and significantly reduces carbon dioxide emissions
- Promotes 100% use of renewable energy sources such as wind, solar, and hydel power
- Undertakes offsetting and mitigation measures to reduce the emission of Greenhouse Gases
- Ensures self-sufficiency in energy through sustainable and eco-friendly practices

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Achieve Open Defecation Free status
- 100% waste management and effective solid and liquid waste disposal
- Zero use of plastic
- 100% transition to renewable energy sources for household, transportation, and industrial needs
- Conservation and expansion of forests and biodiversity
- Reduction of carbon emissions from all sectors — households, transportation, and industry
- Soil and water conservation through traditional and innovative practices

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Conduct baseline surveys to assess total carbon emissions and energy requirements
- Ban the use of plastic within the Panchayat area
- Implement effective management systems for solid and liquid waste
- Generate awareness and mobilize the community, authorities, organizations, and all stakeholders towards climate goals
- Promote the use of renewable energy sources for electricity generation, water heating and cooling, and transportation
- Encourage the use of biogas as a household and industrial fuel
- Promote organic agriculture and reduce dependency on chemical fertilizers
- Practice traditional methods of carbon offsetting as potential sources of community revenue
- Undertake extensive tree plantation drives and promote forest conservation
- Implement innovative financial models such as tree banking and tree mortgaging
- Ensure convergence and optimal utilization of Gram Panchayat Development Plan (GPDP) funds along with other government schemes and programs for climate action

क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार

दाव्वा एस

ब्लॉक पंचायत: सडक अर्जुनी
जिला पंचायत: गोंदिया
राज्य: महाराष्ट्र

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 175545
- कुल जनसंख्या: 3,418
- कुल परिवार: 796

मुख्य उपलब्धियाँ

- 1,16,643 से अधिक देशी वृक्षों, 5,000 बांस पौधों, 500 मोरिंगा पौधों एवं वेटिवर घास का व्यापक वृक्षारोपण अभियान संचालित।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु महाराष्ट्र के "माझी वसुंधरा 4.0" कार्यक्रम में तृतीय स्थान प्राप्त।
- विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं सार्वजनिक भवनों में सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली स्थापित।
- ऊर्जा आत्मनिर्भरता हेतु दिव्यांग व्यक्तियों को 80 सौर किट वितरित।
- पंचायत में 100% एलईडी कवरेज सुनिश्चित।
- वृक्ष आच्छादन में वृद्धि एवं भूजल पुनर्भरण में सुधार।
- जनजागरूकता एवं प्रवर्तन उपायों के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त वातावरण को बढ़ावा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी, बिहार में ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- राष्ट्रीय राजमार्ग 753 के निकट होने के कारण वाहन प्रदूषण।
- जलवायु परिवर्तनशीलता से कृषि एवं आजीविका पर प्रभाव।
- अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहार में परिवर्तन हेतु सामाजिक प्रतिरोध।

दृष्टिकोण

- पर्यावरणीय योजना हेतु जलवायु जोखिम प्रबंधन समिति का गठन।
- जैविक खेती एवं वर्मी-कम्पोस्टिंग को बढ़ावा।
- वर्षा जल संचयन एवं जलाशयों का गाद निकासी कार्य।
- परिपत्र अर्थव्यवस्था हेतु मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना।
- इलेक्ट्रिक वाहनों एवं म्ट चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा।

प्राप्त समर्थन

- राज्य सरकार से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता।
- स्वयं सहायता समूहों, विद्यालयों, किसानों एवं सामुदायिक नेतृत्व की सक्रिय सहभागिता।
- GPDP संसाधनों एवं स्वयं के राजस्व का उपयोग।

सततता के लिए रोडमैप

- पर्यावरण जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन अभियान जारी रखना।
- नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना एवं स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का विस्तार।
- भूजल, वायु गुणवत्ता एवं उत्सर्जन निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना।
- जलवायु कार्रवाई पहलों में सामुदायिक सहभागिता बनाए रखना।

Climate Action Special Panchayat Award (CASPA)

DAWWA S

BLOCK PANCHAYAT: SADAK ARJUNI
DISTRICT PANCHAYAT: GONDIA
STATE: MAHARASHTRA

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 175545
- Total Population: 3,418
- Total Households: 796

KEY ACHIEVEMENTS

- Undertook a large-scale afforestation drive with plantation of 1,16,643+ indigenous trees, 5,000 bamboo plants, 500 moringa plants, and vetiver grass.
- Secured 3rd rank in Maharashtra's Majhi Vasundhara 4.0 programme for environmental conservation.
- Installed solar photovoltaic systems in schools, anganwadi centres, and public buildings.
- Distributed 80 solar kits to differently-abled residents to support energy independence.
- Achieved 100% LED coverage across the Panchayat.
- Increased tree canopy coverage and improved groundwater recharge.
- Promoted a plastic-free environment through awareness campaigns and enforcement measures.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to the Gram Panchayat at Madhubani, Bihar on 24th April, 2025

CHALLENGES FACED

- Vehicular pollution due to proximity to National Highway 753.
- Climate variability affecting agriculture and livelihoods.
- Resistance to behavioural change in waste management practices.

APPROACH TAKEN

- Constituted a Climate Risk Management Committee for environmental planning.
- Promoted organic farming and vermicomposting practices.
- Implemented rainwater harvesting and desilting of water bodies.
- Established Material Recovery Facilities for circular economy practices.
- Promoted electric vehicles and EV charging infrastructure.

SUPPORT RECEIVED

- Financial and technical support from the State Government.
- Active participation of SHGs, schools, farmers, and community leaders.
- Utilization of GPDP resources and self-generated revenue.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Continue environmental awareness campaigns and behavioural change initiatives.
- Expand renewable energy infrastructure and clean energy adoption.
- Strengthen monitoring systems for groundwater, air quality, and emissions.
- Ensure continued community participation in climate action initiatives.

बिरादहल्ली

ब्लॉक पंचायत: सकलेशपुर
जिला पंचायत: हासन
राज्य: कर्नाटक

क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 218437
- कुल जनसंख्या: 4,145
- कुल परिवार: 950

मुख्य उपलब्धियाँ

- ग्राम पंचायत कार्यालय एवं सार्वजनिक संस्थानों में रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित।
- 21 हाई-मास्ट सौर लाइट एवं 190 मिनी सौर स्ट्रीट लाइट स्थापित।
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सौर लालटेन वितरित।
- परिवारों में 100% स्च्ळ एवं बायोगैस उपयोग सुनिश्चित।
- वनमहोत्सव एवं मनरेगा के अंतर्गत एक लाख से अधिक पौधों का रोपण।
- सौर पंप, सौर जल तापक एवं म्ट जागरूकता को बढ़ावा।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली एवं घरेलू पोषण वाटिकाओं की स्थापना।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी, बिहार में ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- सौर अवसंरचना अपनाने में उच्च प्रारंभिक लागत।
- योजनाओं से निधि प्राप्ति में विलंब।
- बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हेतु भूमि की कमी।
- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बदलाव में अनिच्छा।

दृष्टिकोण

- नवीकरणीय ऊर्जा एवं जलवायु कार्रवाई पर प्म्ब अभियान चलाए।
- हरित ऊर्जा तकनीकों पर विशेषज्ञ परामर्श सत्र आयोजित।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निरंतर सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित।
- स्वच्छ ऊर्जा अपनाने हेतु क्रमिक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा।

प्राप्त समर्थन

- केंद्र एवं राज्य सरकारों से वित्तीय एवं कार्यात्मक सहायता।
- गैर-सरकारी संगठनों, दानदाताओं एवं स्वयंसेवकों का सहयोग।
- वन विभाग से पौधे एवं तकनीकी सहायता।
- ग्राम सभाओं एवं वार्ड सभाओं के माध्यम से जनजागरूकता।

सततता के लिए रोडमैप

- "स्वच्छ एवं हरित पंचायत" की दिशा में प्रयास जारी रखना।
- पर्यावरणीय शासन एवं जनसहभागिता को सुदृढ़ करना।
- दीर्घकालिक सततता हेतु नवाचार एवं अनुकूलन को बढ़ावा देना।
- पारिस्थितिक संरक्षण एवं सेवा वितरण पर निरंतर ध्यान बनाए रखना।

Climate Action Special Panchayat Award (CASPA)

BIRADAHALLI

BLOCK PANCHAYAT: SAKALESHPUR
DISTRICT PANCHAYAT: HASSAN
STATE: KARNATAKA

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 218437
- Total Population: 4,145
- Total Households: 950

KEY ACHIEVEMENTS

- Installed rooftop solar systems in the Gram Panchayat office and public institutions.
- Deployed 21 high-mast solar lights and 190 mini solar streetlights.
- Distributed solar lanterns to economically weaker households.
- Achieved 100% LPG and biogas utilization among households.
- Planted more than one lakh saplings under Vanamahotsava and MGNREGS.
- Promoted solar pumps, solar water heaters, and EV awareness.
- Established solid waste management systems and household kitchen gardens.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to the Gram Panchayat at Madhubani, Bihar on 24th April, 2025

CHALLENGES FACED

- High initial costs affected adoption of solar infrastructure.
- Delays in mobilization of funds from schemes.
- Land constraints for large-scale plantation activities.
- Reluctance to shift from conventional energy sources.

APPROACH TAKEN

- Conducted IEC campaigns on renewable energy and climate action.
- Organized expert advisory sessions on green energy technologies.
- Ensured continuous community engagement through elected representatives.
- Promoted gradual behavioural change towards clean energy adoption.

SUPPORT RECEIVED

- Financial and functional support from Central and State Governments.
- Support from NGOs, donors, and volunteers.
- Seedlings and technical assistance from the Forest Department.
- Gram Sabhas and Ward Sabhas used for awareness generation.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Continue efforts towards a "Clean and Green Panchayat."
- Strengthen environmental governance and public participation.
- Promote innovation and adaptability for long-term sustainability.
- Maintain focus on ecological conservation and service delivery.

क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार

मोतीपुर

ब्लॉक पंचायत: रोसेरा
जिला पंचायत: समस्तीपुर
राज्य: बिहार

3rd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 100332
- कुल जनसंख्या: 10,536
- कुल परिवार: 1,684

मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्षा जल संचयन एवं मत्स्य पालन हेतु 21 तालाबों का पुनर्जीवन एवं 2 अमृत सरोवर विकसित।
- मनरेगा के अंतर्गत जल निकासी हस्तक्षेपों द्वारा 250 एकड़ क्षेत्र में जलभराव समस्या का समाधान।
- 60,000 से अधिक वृक्षारोपण एवं मियावाकी वृक्षारोपण तथा पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा।
- प्रत्येक बालिका जन्म पर 10 पौधों का वितरण।
- 560 से अधिक सोख्ता गड्ढों एवं 19,000 फीट जल निकासी नेटवर्क का निर्माण।
- घर-घर अपशिष्ट संग्रहण एवं बायोगैस उत्पादन प्रणाली स्थापित।
- सौर स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट कक्षाएं, बायोगैस प्रणाली एवं सौर पंप स्थापित।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी, बिहार में ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- आर्द्रभूमियों का सूखना एवं मौसमी जल संकट।
- अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण मानसून में बाढ़।
- अपशिष्ट पृथक्करण एवं जलवायु कार्रवाई के प्रति सीमित जागरूकता।
- जलवायु पहलों हेतु संसाधनों की कमी।

दृष्टिकोण

- भूजल पुनर्भरण एवं जल निकासी प्रबंधन हेतु सोख्ता गड्ढों एवं नहरों का निर्माण।
- वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना।
- जनजागरूकता अभियानों के साथ प्लास्टिक प्रतिबंध संकल्प लागू।
- ग्राम सभा, महिला सभा एवं बाल सभा के माध्यम से समुदाय को संगठित किया।
- मनरेगा, CFC, SFC एवं जल जीवन मिशन निधियों का अभिसरण।

प्राप्त समर्थन

- जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण गतिविधियों हेतु मनरेगा के अंतर्गत सहयोग।
- नवीकरणीय ऊर्जा पहलों हेतु पीएम-कुसुम योजना का समर्थन।
- SBM एवं जल जीवन मिशन के अंतर्गत अवसंरचना विकास सहायता।
- SELCO फाउंडेशन से तकनीकी सहयोग।

सततता के लिए रोडमैप

- निरंतर निगरानी हेतु जलवायु कार्रवाई निगरानी समिति का गठन।
- स्वच्छता एवं जल सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क लागू।
- जलवायु सहनशीलता हेतु योजनाओं के अभिसरण को सुदृढ़ करना।
- व्यवहार परिवर्तन हेतु सामुदायिक जागरूकता अभियान जारी रखना।

Climate Action Special Panchayat Award (CASPA)

MOTIPUR

BLOCK PANCHAYAT: ROSERA
DISTRICT PANCHAYAT: SAMASTIPUR
STATE: BIHAR

3rd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 100332
- Total Population: 10,536
- Total Households: 1,684

KEY ACHIEVEMENTS

- Rejuvenated 21 ponds and developed 2 Amrit Sarovars for rainwater harvesting and fish farming.
- Resolved waterlogging issues across 250 acres through drainage interventions under MGNREGS.
- Planted more than 60,000 trees and promoted Miyawaki plantations and Nutri Gardens.
- Distributed 10 saplings for every girl child born.
- Constructed more than 560 soak pits and developed a 19,000-foot drainage network.
- Established door-to-door waste collection and biogas production systems.
- Installed solar streetlights, smart classrooms, biogas systems, and solar pumps.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to the Gram Panchayat at Madhubani, Bihar on 24th April, 2025

CHALLENGES FACED

- Drying wetlands and seasonal water scarcity.
- Monsoon flooding due to inadequate drainage systems.
- Limited awareness regarding waste segregation and climate action.
- Resource constraints for climate initiatives.

APPROACH TAKEN

- Constructed soak pits and canals for groundwater recharge and drainage management.
- Established a Waste Processing Unit for scientific waste management.
- Implemented a plastic ban resolution supported by awareness campaigns.
- Mobilized communities through Gram Sabhas, Mahila Sabhas, and Bal Sabhas.
- Converged funds from MGNREGA, CFC, SFC, and Jal Jeevan Mission.

SUPPORT RECEIVED

- Support under MGNREGA for water conservation and afforestation activities.
- PM-KUSUM support for renewable energy initiatives.
- Support under SBM and Jal Jeevan Mission for infrastructure development.
- Technical assistance from SELCO Foundation.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Established a Climate Action Monitoring Committee for continuous oversight.
- Introduced user charges for sanitation and water services.
- Strengthen convergence of schemes for climate resilience.
- Continue community awareness campaigns for behavioural change.

आत्मनिर्भर पंचायत

विशेष पुरस्कार

आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने स्वयं के राजस्व स्रोतों (ओएसआर) को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह पुरस्कार स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देता है तथा पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी बनाकर स्थानीय शासन की नींव को मजबूत करता है।

एक आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत वह है जो:

- समुदाय पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना स्थानीय राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करे।
- वित्तीय संसाधनों के संकलन हेतु नवाचारपूर्ण उपाय अपनाए।
- राजस्व प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करे।
- विकास कार्यों एवं सेवा वितरण के लिए स्व-निर्भर वित्तीय मॉडल विकसित करे।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करना एवं बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम करना।
- कर, शुल्क, जुर्माना एवं अन्य स्रोतों से अधिकतम राज. स्व सृजन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- इको-टूरिज्म एवं लघु उद्यमों जैसे नवाचारपूर्ण मॉडल के माध्यम से स्थानीय आय बढ़ाना।
- पंचायत के भीतर वित्तीय निर्णयों में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
- सतत स्थानीय विकास हेतु संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना।

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- समुदाय में संभावित राजस्व स्रोतों की पहचान हेतु नियमित आकलन करना।
- सरल एवं न्यायसंगत कर प्रणाली लागू करना जिससे पंचायत एवं नागरिक दोनों लाभान्वित हों।
- राजस्व सृजन एवं उसके स्थानीय विकास पर प्रभाव के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना।
- स्थानीय व्यवसायों, गैर-सरकारी संगठनों एवं अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करना।
- सामुदायिक भूमि एवं अवसंरचना जैसी पंचायत परिसंपत्तियों का राजस्व सृजन हेतु बेहतर उपयोग करना।
- नियमित ऑडिट एवं सार्वजनिक रिपोर्टिंग के माध्यम से निधियों के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- स्थानीय शासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व को मजबूत करने हेतु सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

ATMA NIRBHAR PANCHAYAT SPECIAL AWARD (ANPSA)

Atma Nirbhar Panchayat Special Award recognizes Gram Panchayats (GPs) that demonstrate exceptional performance in mobilizing and augmenting their Own Sources of Revenue (OSR). It promotes the spirit of self-reliance at the grassroots by encouraging Panchayats to become financially independent, thus strengthening the foundation of local governance.

AN ATMA NIRBHAR GRAM PANCHAYAT IS ONE THAT:

- Achieves a significant increase in local revenue generation without overburdening the community
- Utilizes innovative methods to mobilize financial resources
- Ensures transparent, accountable management of the revenue
- Establishes self-sustaining models to fund development projects and service delivery

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Achieve fiscal autonomy and reduce dependence on external funding
- Maximize the generation of revenue through taxes, fines, fees, and other sources
- Strengthen systems for managing and accounting for local finances
- Introduce innovative models to increase local income, such as eco-tourism or small-scale enterprises
- Enhance transparency and participation in financial decision-making within the Panchayat
- Promote the responsible use of resources for sustainable local development

ROLE OF GRAM PANCHAYATS:

- Conduct regular assessments to identify potential revenue streams within the community
- Implement simple and fair taxation systems that benefit both the Panchayat and its residents
- Raise awareness about the importance of revenue generation and its impact on local development
- Establish partnerships with local businesses, NGOs, and other stakeholders to generate income
- Optimize the use of Gram Panchayat assets, such as common lands or infrastructure, for revenue generation
- Ensure transparency and accountability in the management of funds through regular audits and public reporting
- Foster community participation to strengthen local governance and financial responsibility

आत्मनिर्भर पंचायत
विशेष पुरस्कार

मल्ल

ब्लॉक पंचायत: याचरम
जिला पंचायत: रंगारेड्डी
राज्य: तेलंगाना

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 210571
- कुल जनसंख्या: 3,211
- कुल परिवार: 1,581

मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023ख24 के दौरान 95 लाख का स्वयं का राजस्व (ओएसआर) संग्रहित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक है।
- प्रति व्यक्ति लगभग 2,954 ओएसआर प्राप्त किया।
- कर, सेवा शुल्क, पशु बाजार एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किराए से राजस्व अर्जित किया।
- साप्ताहिक पशु बाजार संचालन से 67 लाख की आय प्राप्त की।
- विविध राजस्व स्रोतों के माध्यम से स्थानीय वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी, बिहार में ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- प्रारंभिक चरण में सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता।
- कर एवं गैर-कर राजस्व संग्रहण का निम्न स्तर।

दृष्टिकोण

- स्पष्ट कर निर्धारण एवं अनुपालन हेतु जनजागरूकता अभियान संचालित किए।
- कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में विशेष संग्रहण अभियान चलाए।
- आय सृजन परिसंपत्तियों हेतु पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया अपनाई।
- कम्पोस्ट उत्पादन एवं बिक्री हेतु डंपिंग यार्ड स्थापित किया।

प्राप्त समर्थन

- तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 के अंतर्गत सक्षम समर्थन प्राप्त हुआ।
- ऑनलाइन कर संग्रहण प्रणाली के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई।
- जनसहयोग एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से समर्थन मिला।

सततता के लिए रोडमैप

- प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी कर मूल्यांकन प्रणाली अपनाना।
- ग्राम सभाओं एवं स्थायी समितियों को सशक्त बनाना।
- प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन के माध्यम से राजस्व अधिकतम करना।
- आत्मनिर्भर शासन हेतु नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना।

Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA)

MALL

BLOCK PANCHAYAT: YACHARAM
DISTRICT PANCHAYAT: RANGAREDDI
STATE: TELANGANA

1st PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 210571
- Total Population: 3,211
- Total Households: 1,581

KEY ACHIEVEMENTS

- Collected ₹95 lakhs as Own Source Revenue during 2023–24 with a 45% increase over the previous year.
- Achieved approximately ₹2,954 per capita OSR.
- Generated revenue through taxes, service fees, cattle markets, and shopping complex rentals.
- Earned ₹67 lakhs from weekly cattle market operations.
- Strengthened local financial self-reliance through diversified revenue sources.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to the Gram Panchayat at Madhubani, Bihar on 24th April, 2025

CHALLENGES FACED

- High dependence on government grants during the initial phase.
- Low collection of tax and non-tax revenues.

APPROACH TAKEN

- Set clear tax demands and conducted awareness campaigns for compliance.
- Focused collection drives in low-performing areas.
- Conducted transparent auctions for income-generating assets.
- Established a dumping yard for compost production and sale.

SUPPORT RECEIVED

- Enabled by Telangana Panchayat Raj Act, 2018.
- Supported through online tax collection systems.
- Received public donations and CSR support.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Adopt technology-enabled transparent tax assessment systems.
- Strengthen Gram Sabhas and Standing Committees.
- Maximize revenue through effective asset management.
- Promote citizen participation for self-reliant governance.

आत्मनिर्भर पंचायत
विशेष पुरस्कार

हटबदरा

ब्लॉक पंचायत: कुसुमी
जिला पंचायत: मयूरभंज
राज्य: ओडिशा

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 120264
- कुल जनसंख्या: 6,703
- कुल परिवार: 1,552

मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023ख24 के दौरान ₹94 लाख का स्वयं का राजस्व (ओएसआर) संग्रहित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है।
- प्रति व्यक्ति लगभग ₹1,407 ओएसआर प्राप्त किया।
- हाट, कर, लाइसेंस, पट्टा एवं नीलामी के माध्यम से राजस्व अर्जित किया।
- गैर-कर राजस्व में 66.29% वृद्धि दर्ज की।
- सड़कों, पुलों, सिंचाई प्रणालियों एवं सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश किया।
- गरीबी उन्मूलन, जलापूर्ति एवं महिला विकास पर केंद्रित एलएसडीजी लक्ष्यों के अनुरूप व्यय सुनिश्चित किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी, बिहार में ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- सामुदायिक परिसंपत्तियों का अपर्याप्त उपयोग एवं अवसंरचना की कमी।
- मौसमी जल संकट एवं पुराने बाजार ढांचे।
- परिसंपत्ति प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता।

दृष्टिकोण

- अनुपयोगी परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण कर उनका उत्पादक उपयोग सुनिश्चित किया।
- राजस्व वृद्धि हेतु किराया एवं पट्टा प्रणाली में संशोधन किया।
- पारदर्शी नीलामी एवं अवसंरचना उन्नयन कार्य किए।
- शासन में महिलाओं की सहभागिता को सुदृढ़ किया।

प्राप्त समर्थन

- जिला प्रशासन एवं राज्य/केंद्र एजेंसियों से सहयोग प्राप्त हुआ।
- जिला कलेक्टर से वित्तीय प्रोत्साहन मिला।
- नागरिक अवसंरचना निवेश हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

सततता के लिए रोडमैप

- राजस्व स्रोतों में विविधता एवं अवसंरचना का आधुनिकीकरण।
- हितधारक सहभागिता एवं खुले शासन को मजबूत करना।
- कौशल विकास एवं संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा देना।
- दीर्घकालिक वित्तीय सततता तंत्र को सुदृढ़ करना।

Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA)

HATBADRA

BLOCK PANCHAYAT: KUSUMI
DISTRICT PANCHAYAT: MAYURBHANJ
STATE: ODISHA

2nd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 120264
- Total Population: 6,703
- Total Households: 1,552

KEY ACHIEVEMENTS

- Collected ₹94 lakhs as Own Source Revenue during 2023–24 with a 20% increase over the previous year.
- Achieved approximately ₹1,407 per capita OSR.
- Generated revenue through haats, taxes, licenses, leasing, and auctions.
- Recorded 66.29% growth in non-tax revenue.
- Invested in roads, bridges, irrigation systems, and public amenities.
- Aligned expenditure with LSDGs focusing on poverty reduction, water supply, and women's development.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to the Gram Panchayat at Madhubani, Bihar on 24th April, 2025

CHALLENGES FACED

- Underutilized community assets and inadequate infrastructure.
- Seasonal water scarcity and outdated market facilities.
- Need for improved transparency in asset management.

APPROACH TAKEN

- Surveyed and repurposed unused assets for productive utilization.
- Revised rental and leasing systems for revenue enhancement.
- Conducted transparent auctions and infrastructure upgrades.
- Strengthened women's participation in governance.

SUPPORT RECEIVED

- Support from district administration and State/Central agencies.
- Financial incentives from the District Collector.
- Technical guidance for civic infrastructure investments.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Diversify revenue sources and modernize infrastructure.
- Strengthen stakeholder participation and open governance.
- Promote skill development and institutional partnerships.
- Enhance long-term financial sustainability mechanisms.

आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार

गोल्लापुडी

ब्लॉक पंचायत: विजयवाड़ा ग्रामीण
जिला पंचायत: कृष्णा
राज्य: आंध्र प्रदेश

3rd PRIZE

प्रोफाइल:

- स्थानीय शासन निर्देशिका (एलजीडी) कोड: 203825
- कुल जनसंख्या: 37,349
- कुल परिवार: 9,460

मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023ख्24 के दौरान ₹4.11 करोड़ का स्वयं का राजस्व (ओएसआर) संग्रहित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है।
- प्रति व्यक्ति लगभग ₹1,130 ओएसआर प्राप्त किया।
- स्वयं की निधियों से जल टंकियों का निर्माण एवं सड़कों का नवीनीकरण किया।
- घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू कर अनियंत्रित अपशिष्ट में 60% कमी लाई।
- 50 सौर स्ट्रीट लाइट स्थापित कर विद्युत व्यय में कमी की।
- परिचालन व्यय प्रबंधन में लगभग 80% आत्मनिर्भरता प्राप्त की।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी, बिहार में ग्राम पंचायत को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- कर भुगतान एवं राजस्व संग्रहण के प्रति प्रारंभिक विरोध।
- आत्मनिर्भर पंचायत शासन के प्रति सीमित जागरूकता।
- राजस्व प्रबंधन हेतु कुशल मानव संसाधन की कमी।

दृष्टिकोण

- स्वर्ण पंचायत ऑनलाइन डेटाबेस में 13,919 संपत्तियों को एकीकृत किया।
- समय पर कर भुगतान करने वालों हेतु प्रोत्साहन प्रणाली शुरू की।
- जनजागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

प्राप्त समर्थन

- कर सुधार एवं डिजिटलीकरण पहल हेतु राज्य सरकार से समर्थन प्राप्त हुआ।
- पंचायत सचिवालय कर्मचारियों हेतु क्षमता निर्माण सहयोग मिला।
- कर अनुपालन एवं शासन सुधारों हेतु जागरूकता अभियान संचालित किए गए।

सततता के लिए रोडमैप

- वित्तीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का विस्तार।
- इको-टूरिज्म एवं कौशल विकास के माध्यम से राजस्व स्रोतों में विविधता लाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा एवं अपशिष्ट प्रबंधन में निवेश जारी रखना।
- जल संरक्षण पहलों को और मजबूत करना।

Atma Nirbhar Panchayat Special Award (ANPSA)

GOLLAPUDI

BLOCK PANCHAYAT: VIJAYAWADA RURAL
DISTRICT PANCHAYAT: KRISHNA
STATE: ANDHRA PRADESH

3rd PRIZE

Profile

- Local Government Directory (LGD) Code: 203825
- Total Population: 37,349
- Total Households: 9,460

KEY ACHIEVEMENTS

- Collected ₹4.11 crore as Own Source Revenue during 2023–24 with a 40% increase over the previous year.
- Achieved approximately ₹1,130 per capita OSR.
- Constructed water tanks and renovated roads using own funds.
- Implemented door-to-door waste collection reducing unmanaged waste by 60%.
- Installed 50 solar streetlights reducing electricity expenditure.
- Achieved nearly 80% self-reliance in operational expenditure management.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to the Gram Panchayat at Madhubani, Bihar on 24th April, 2025

CHALLENGES FACED

- Initial resistance towards tax payment and revenue mobilization.
- Limited awareness regarding self-reliant Panchayat governance.
- Shortage of skilled personnel for revenue management.

APPROACH TAKEN

- Integrated 13,919 properties under the Swarna Panchayat online database.
- Introduced incentives for timely taxpayers to improve compliance.
- Conducted awareness campaigns and training programmes.

SUPPORT RECEIVED

- State support for taxation reforms and digitization initiatives.
- Capacity-building support for Panchayat Secretariat staff.
- Awareness campaigns for tax compliance and governance reforms.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Digitize financial records and expand online payment systems.
- Diversify revenue streams through eco-tourism and skill development.
- Continue investments in renewable energy and waste management.
- Strengthen water conservation initiatives.

सशक्त पंचायत सतत् विकास

पंचायत क्षमता निर्माण

सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार

पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार उन संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) को प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहयोग प्रदान किया है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर के संस्थान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता निर्माण के माध्यम से विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, सेवा वितरण, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर पर ग्रामीण शासन को सुदृढ़ करते हैं।

स्थानीय उद्देश्य एवं लक्ष्य:

- क्षमता निर्माण ख़ संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पंचायतों की शासन, योजना एवं वित्तीय प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करना।
- सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण (एलएसडीजी) ख़ पंचायतों को वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय विकास योजनाओं (पंचायत विकास योजनाओं) में परिवर्तित करने में सक्षम बनाना।
- सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति ख़ पंचायतों के प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं गतिविधियों को एलएसडीजी के अनुरूप तैयार करना।
- डेटा आधारित योजना एवं अनुसंधान ख़ पंचायतों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी हेतु साक्ष्य आधारित अनुसंधान एवं निर्णय प्रणाली विकसित करना।

ग्राम पंचायतों की भूमिका:

- पंचायतों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण ख़ पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों हेतु संसाधन संकलन, सहभागी योजना, परियोजना कार्यान्वयन, डिजिटल शासन आदि विषयों पर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- नीति समर्थन ख़ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायतों को आवश्यक नीति संबंधी सहयोग प्रदान करना।
- निगरानी एवं मूल्यांकन ख़ पंचायत पहलों की प्रगति की निगरानी हेतु उपकरण एवं तंत्र विकसित करना।
- ज्ञान साझाकरण ख़ श्रेष्ठ प्रथाओं एवं अध्ययन मामलों का संकलन कर पंचायतों को नवाचारपूर्ण स्थानीय विकास समाधान अपनाने में सहायता देना।
- तकनीकी सहयोग ख़ वित्त, प्रौद्योगिकी एवं सामुदायिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता उपलब्ध कराना।
- सहयोग एवं नेटवर्किंग ख़ गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना।

सशक्त पंचायत सतत् विकास

PANCHAYAT KSHAMTA NIRMAN SARVOTTAM SANSTHAN PURASKAR

Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar is for those Institutions which have provided institutional support to GPs in achieving Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs). Institutions at State/Union Territory level provides technical and knowledge-based assistance to Panchayati Raj Institutions through capacity-building of their elected representatives and functionaries for implementing development programs and service delivery along with conducting research & innovations on key related areas to strengthen rural governance at grassroots levels.

LOCAL GOALS AND TARGETS:

- Capacity Building: Enhance the governance, planning, and financial management skills of Panchayats through structured training programs
- Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs): Enable Panchayats to translate global SDGs into actionable local development plans (Panchayat Development Plans)
- Realizing SDGs: Prepare and align training modules and activities of Panchayats with LSDGs
- Data-driven Planning and Research: Evidence-based research and decision-making to monitor progress on SDGs by Panchayats

ROLE OF INSTITUTIONS

- Training and Capacity Building of Panchayats: Conduct training sessions for Panchayat members, Training of Trainers with participatory training methodologies on topics such as resource mobilization, participatory planning, project implementation, digital governance etc.
- Policy Advocacy: Provide necessary support to Panchayats on policy frameworks for achieving SDGs
- Monitoring and Evaluation: Develop tools and mechanisms to monitor the progress of Panchayat initiatives aligned with SDGs
- Knowledge Sharing: Act as a repository of best practices and case studies, helping Panchayats to adopt innovative solutions for local development
- Technical Support: Offer expertise in areas like finance, technology, and community engagement to address complex rural challenges
- Collaboration and Networking: Facilitate partnerships with NGOs, academic institutions, and international organizations to bring additional resources and expertise to Panchayats

पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार

केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (किला)

राज्य: केरल

1st PRIZE

प्रोफाइल:

- वर्ष 1990 में केरल में स्थानीय शासन क्षमता विकास हेतु नोडल संस्थान के रूप में स्थापित।
- वर्ष 2014 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल द्वारा अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त।
- 15 संकाय सदस्यों, लगभग 3,000 प्रशिक्षकों एवं छह क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से कार्यरत।
- विकेंद्रीकरण, शासन सुधार, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रकाशनों पर केंद्रित।

मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023-24 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों हेतु 6,450 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- वर्ष 2023-24 में लगभग 21,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं 2.4 लाख विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।
- कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की।
- केरल की सभी ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक पंचायतों के लिए आईएसओ प्रमाणन सुनिश्चित किया।
- 260 से अधिक स्थानीय सरकारों को जलवायु परिवर्तन हेतु स्थानीय कार्ययोजना (LAPCC) तैयार करने में सक्षम बनाया।
- योजना एवं निगरानी हेतु डिजास्टर एंड क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर (DCAT) विकसित किया।
- अनुकूलित डैशबोर्ड एवं स्थानीय संकेतक ढांचे के माध्यम से एसडीजी स्थानीयकरण को मुख्यधारा में शामिल किया।
- विशेष उपकरणों एवं क्षमता निर्माण सहायता के माध्यम से अत्यधिक गरीबी पहचान अभ्यास संचालित किए।
- लैंगिक समानता, एसडीजी, जनजातीय विकास एवं शहरी शासन पर केंद्रित विषयगत केंद्र स्थापित किए।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी, बिहार में किला को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों में विविध हितधारकों हेतु बड़े स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन।
- जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास जैसी उभरती शासन चुनौतियों का समाधान।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के कौशल एवं ज्ञान का निरंतर उन्नयन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय शासन प्रणालियों में एसडीजी एवं सहभागी योजना को मुख्यधारा में शामिल करना।
- जवाबदेही, पारदर्शिता एवं नागरिक सहभागिता बनाए रखते हुए विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करना।

दृष्टिकोण

- केरल में समयबद्ध एवं सुलभ प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं क्षेत्रीय स्तर प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की।
- संरचित प्रशिक्षण एवं सुविधा तंत्र के माध्यम से सहभागी योजना, सामुदायिक सहभागिता एवं जमीनी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।
- शासन, जलवायु कार्रवाई, बाल अधिकार, शहरी विकास, लैंगिक समानता एवं सतत आजीविका पर केंद्रित विषयगत एवं क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रणाली, जियो-इन्फॉर्मेटिक्स लैब, एसडीजी डैशबोर्ड एवं ई-गवर्नेंस उपकरणों का उपयोग कर स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाया।

प्राप्त समर्थन

- स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल सरकार से संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों के साथ तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ।
- विकेंद्रीकृत शासन एवं क्षमता निर्माण पहलों के अंतर्गत वित्तीय एवं कार्यक्रम सहयोग मिला।
- शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ सक्रिय साझेदारी रही।

नवाचार

- स्थानीय सरकारों हेतु एसडीजी डैशबोर्ड एवं स्थानीय संकेतक ढांचे का विकास।
- जलवायु शासन हेतु डीसीएटी (डिजास्टर एंड क्लाइमेट एक्शन ट्रैकिंग टूल) की शुरुआत।
- विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय शासन पर भारत का पहला ईएमएस संग्रहालय स्थापित किया।
- बड़े स्तर पर पहुंच हेतु हाइब्रिड एवं डिजिटल क्षमता निर्माण प्रणाली अपनाई।
- लैंगिक शासन, जलवायु परिवर्तन, शहरी शासन एवं जियो-इन्फॉर्मेटिक्स पर विषयगत केंद्र स्थापित किए।

सततता के लिए रोडमैप

- निरंतर क्षमता निर्माण हेतु डिजिटल एवं हाइब्रिड शिक्षण प्रणाली का विस्तार।
- जलवायु अनुकूल एवं एसडीजी उन्मुख स्थानीय शासन ढांचे को सुदृढ़ करना।
- विकेंद्रीकृत शासन में अनुसंधान, नवाचार एवं साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना।
- उन्नत विषयगत संसाधन केंद्र एवं नेतृत्व कार्यक्रम विकसित करना।
- सह-अध्ययन एवं अंतर-राज्यीय ज्ञान आदान-प्रदान मंचों को प्रोत्साहित करना।
- सतत निगरानी, मूल्यांकन एवं ज्ञान प्रलेखन प्रणाली को संस्थागत रूप देना।

Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP)

KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION (KILA)

STATE: KERALA

1st PRIZE

Profile

- Established in 1990 as the nodal institution for capacity development in local governance in Kerala.
- Recognized as a Research Centre by the Central University of Kerala in 2014.
- Operates with 15 faculty members, nearly 3,000 trainers, and six regional centres.
- Focuses on decentralization, governance reforms, research, training, and publications.

KEY ACHIEVEMENTS

- Conducted 6,450 training programmes during 2023–24 for Elected Representatives and functionaries.
- Trained around 21,000 Elected Representatives and 2.4 lakh line department functionaries during 2023–24.
- Established a dedicated Project Management Unit for implementation and monitoring.
- Achieved ISO certification for all Gram Panchayats and Block Panchayats in Kerala.
- Enabled more than 260 local governments to prepare Local Action Plans on Climate Change (LAPCC).
- Developed the Disaster and Climate Action Tracker (DCAT) for planning and monitoring.
- Mainstreamed SDG localization through customized dashboards and local indicator frameworks.
- Led extreme poverty identification exercises through tailored tools and capacity-building support.
- Established thematic centres focusing on gender, SDGs, tribal development, and urban governance.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to KILA at Madhubani, Bihar on 24th April, 2025

CHALLENGES FACED

- Managing large-scale capacity-building programmes for diverse stakeholders across rural and urban local governments.
- Addressing emerging governance challenges such as climate change, disaster risk reduction, poverty eradication, and inclusive development.
- Ensuring continuous upgrading of skills and knowledge among elected representatives and officials.
- Mainstreaming SDGs and participatory planning within local governance systems.
- Strengthening decentralized governance while maintaining accountability, transparency, and citizen participation.

APPROACH TAKEN

- Established district-level and regional training systems to ensure timely and accessible training delivery across Kerala.
- Promoted participatory planning, community engagement, and grassroots democratic decision-making through structured training and facilitation.
- Created dedicated thematic and regional centres focusing on governance, climate action, child rights, urban development, gender, and sustainable livelihoods.
- Leveraged digital platforms, online training systems, geo-informatics labs, SDG dashboards, and e-governance tools to strengthen local administration.

SUPPORT RECEIVED

- Institutional support from the Local Self Government Department, Government of Kerala.
- Technical collaboration with national and international development agencies.
- Financial and programme support through decentralized governance and capacity-building initiatives.
- Active partnership with academic institutions, civil society organizations, and subject experts.

INNOVATIONS

- Development of SDG Dashboard and Local Indicator Framework for local governments.
- Introduction of DCAT (Disaster and Climate Action Tracking Tool) for climate governance.
- Establishment of India's first EMS Museum on Decentralisation and Local Governance.
- Adoption of hybrid and digital capacity-building systems for large-scale outreach.
- Creation of innovative thematic centres on gender governance, climate change, urban governance, and geo-informatics.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Expanding digital and hybrid learning ecosystems for continuous capacity building.
- Strengthening climate-resilient and SDG-oriented local governance frameworks.
- Enhancing research, innovation, and evidence-based policymaking in decentralized governance.
- Developing advanced thematic resource centres and leadership programmes.
- Promoting peer-learning mechanisms and inter-state knowledge exchange platforms.
- Institutionalizing continuous monitoring, evaluation, and knowledge documentation systems.

पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (SIRD&PR)

राज्य: ओडिशा

2nd PRIZE

प्रोफाइल:

- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इन-हाउस, ऑफ-कैंपस एवं चरणबद्ध मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है।
- 19 जिला पंचायत संसाधन केंद्र, 3 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र एवं 314 पंचायत समितियों द्वारा समर्थित।
- शासन सुधार एवं क्षमता विकास के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर केंद्रित।

मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023ख्र24 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों हेतु 2,795 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- लगभग 51,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं 1.09 लाख विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।
- समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की।
- नव नियुक्त जेई, जीपीडीओ एवं पीईओ के लिए 15 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए।
- महिला सभा एवं बाल सभा दिशा-निर्देश विकसित एवं लागू किए।
- मार्गदर्शन एवं प्रदर्शन निगरानी हेतु "लोकल चौंपियन" एवं "बिगिनर टू अचीवर" पहल शुरू की।
- वास्तविक समय प्रशिक्षण एवं प्रतिभागी निगरानी हेतु डिजिटल पोर्टल विकसित किया।
- ओनरशिप पहल के अंतर्गत 4,562 सरपंचों एवं 1,250 पीईओ को मार्गदर्शन प्रदान किया।
- ओएसआर नियम, पेसा नियम, नागरिक चार्टर एवं विषयगत मॉड्यूल सहित शासन उपकरण विकसित किए।
- वित्तीय सततता संकेतकों को शामिल कर पंचायत पुरस्कार मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2026 को मधुबनी, बिहार में एसआईआरडी एंड पीआर, ओडिशा को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पीआरआई कार्मिकों के बड़े एवं विविध समूह की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना।
- बड़े स्तर के आवासीय एवं विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अवसंरचना को मजबूत करना।
- जीपीडीपी को एलएसडीजी के नौ विषयों के अनुरूप बनाना।
- जमीनी स्तर पर सतत निगरानी, पारदर्शिता एवं प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करना।

दृष्टिकोण

- विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण मॉडल के माध्यम से आवासीय, जिला एवं ब्लॉक स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए।
- जियो-टैगिंग, मूल्यांकन एवं ऑनलाइन प्रतिक्रिया सहित प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की।
- 'लोकल चौंपियन' एवं ओनरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से सह-अध्ययन एवं मार्गदर्शन को बढ़ावा दिया।
- पीआरआई प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों हेतु विशेष अभिमुखीकरण एवं विषयगत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए।
- सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ समन्वित शासन हेतु सहयोग किया।

प्राप्त समर्थन

- पंचायती राज मंत्रालय एवं पीआर एंड डीडब्ल्यू विभाग, ओडिशा सरकार से तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हुआ।
- राष्ट्रीय महिला आयोग, ओएसडीएमए, नीति आयोग, गैर-सरकारी संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सहयोग मिला।
- पंचायत प्रशिक्षण अवसंरचना एवं शासन प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ।

नवाचार

- विषयगत पंचायत परिवर्तन हेतु 'लोकल चौंपियन' एवं 'बिगिनर टू अचीवर' कार्यक्रम शुरू किए।
- ओटीपी आधारित जियो-टैग डिजिटल प्रशिक्षण निगरानी प्रणाली लागू की।
- ओनरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत जमीनी प्रतिनिधियों हेतु व्यक्तिगत वर्चुअल मार्गदर्शन सहायता।
- समावेशी जमीनी शासन हेतु महिला सभा एवं बाल सभा दिशा-निर्देश विकसित किए।
- ग्राम पंचायत अवसंरचना एवं पीआरआई प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु पंचायत निगरानी प्रणाली विकसित की।

सततता के लिए रोडमैप

- ग्राम पंचायतों में पंचायत लर्निंग सेंटर (च्स्ब्) को संस्थागत रूप देना।
- शासन गुणवत्ता सुधार हेतु पंचायतों के लिए आईएसओ प्रमाणन को बढ़ावा देना।
- निरंतर संस्थागत सुदृढ़ीकरण हेतु मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण नीति विकसित करना।
- दीर्घकालिक सततता हेतु ई-गवर्नेंस एवं मार्गदर्शन कार्यक्रमों का विस्तार करना।
- एक्सपोजर विजिट, सह-अध्ययन एवं विषयगत पंचायत योजना तंत्र को मजबूत करना।

Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP)

STATE INSTITUTE FOR RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ (SIRD&PR)

STATE: ODISHA

2nd PRIZE

Profile

- Conducts training programmes through in-house, off-campus, and cascading models across district and block levels.
- Supported by 19 District Panchayat Resource Centres, 3 Extension Training Centres, and 314 Panchayat Samitis.
- Focuses on strengthening Panchayati Raj Institutions through governance reforms and capacity development.

KEY ACHIEVEMENTS

- Conducted 2,795 training programmes during 2023–24 for Elected Representatives and functionaries.
- Trained nearly 51,000 Elected Representatives and 1.09 lakh line department functionaries during 2023–24.
- Established a dedicated Project Management Unit.
- Introduced 15-day induction training modules for newly appointed JEs, GPDOs, and PEOs.
- Developed and operationalized Mahila Sabha and Bal Sabha guidelines.
- Launched "Local Champion" and "Beginner to Achiever" initiatives for mentorship and performance tracking.
- Implemented a digital monitoring portal for real-time training and participant tracking.
- Mentored 4,562 Sarpanches and 1,250 PEOs under the Ownership initiative.
- Prepared governance tools including OSR Rules, PESA Rules, Citizen Charters, and thematic modules.
- Strengthened Panchayat award assessment systems through inclusion of financial sustainability indicators.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to the SIRD&PR, Odisha at Madhubani, Bihar on 24th April, 2026

CHALLENGES FACED

- Meeting the training needs of a large and heterogeneous group of elected representatives and PRI functionaries.
- Strengthening infrastructure for large-scale residential and thematic training programmes.
- Aligning GPDPs with the nine themes of Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs).
- Ensuring continuous monitoring, transparency, and effective service delivery at the grassroots level.

APPROACH TAKEN

- Decentralized Training Model: Conducted residential, district-level, and block-level training programmes for wider outreach.
- Digital Governance: Introduced technology-enabled monitoring systems with geo-tagging, assessments, and online feedback.
- Peer Learning and Mentorship: Promoted cross-learning through the 'Local Champion' initiative and Ownership Programme.
- Capacity Building Focus: Developed specialized induction and thematic training modules for PRI representatives and officials.
- Convergent Governance: Collaborated with government departments, NGOs, and UN agencies for technical support and handholding.

SUPPORT RECEIVED

- Technical and administrative support from Ministry of Panchayati Raj (MoPR) and PR & DW Department, Government of Odisha.
- Collaboration with National Commission for Women, OSDMA, NITI Aayog, NGOs, and UN agencies.
- Financial and institutional support for strengthening Panchayat training infrastructure and governance systems.

INNOVATIONS

- Launch of the 'Local Champion' and 'Beginner to Achiever' programmes for thematic Panchayat transformation.
- Introduction of OTP-based geo-tagged digital training monitoring systems.
- One-to-one virtual mentoring support for grassroots representatives under the Ownership Programme.
- Development of Mahila Sabha and Bal Sabha guidelines for inclusive grassroots governance.
- Creation of Panchayat Monitoring Systems for assessing GP infrastructure and PRI performance.

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Institutionalizing Panchayat Learning Centres (PLCs) across Gram Panchayats.
- Promoting ISO certification for Panchayats to improve governance quality standards.
- Developing Human Resource and Training Policies for continuous institutional strengthening.
- Expanding e-governance systems and mentorship programmes for long-term sustainability.
- Strengthening exposure visits, peer-learning initiatives, and thematic Panchayat planning mechanisms.

पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट (SIP&RD)

राज्य: ओडिशा

3rd PRIZE

प्रोफाइल:

- सितंबर 1987 में स्थापित तथा वर्ष 1998 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत स्वायत्त निकाय बना।
- पंचायती राज मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जुलाई 2016 में **SIP&RD** के रूप में पुनर्नामित किया गया।
- प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं ग्रामीण शासन सुधारों के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्यरत।
- गुवाहाटी स्थित दो परिसरों, 12 विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों एवं 11 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों के माध्यम से कार्यरत।
- 87 संकाय सदस्यों एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों एवं संसाधन व्यक्तियों के नेटवर्क द्वारा समर्थित।

मुख्य उपलब्धियाँ

- वर्ष 2023ख्र24 के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों हेतु 5,975 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- लगभग 14,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं 25,000 विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।
- समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की।
- राज्यभर में जीपीडीपी, बीपीडीपी एवं डीपीडीपी तैयार करने हेतु पीपुल्स प्लान अभियान का संचालन किया।
- लैंगिक समानता, आजीविका एवं पेयजल सहित नौ विषयगत क्षेत्रों में एसडीजी केंद्रित प्रशिक्षण आयोजित किए।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु छह पीएमएवाई-जी मॉडल आवास विकसित किए।
- प्रशिक्षण निगरानी एवं रिपोर्टिंग हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू की।
- विकेंद्रीकृत पहुंच हेतु विस्तार प्रशिक्षण केंद्र एवं जिला पंचायत संसाधन केंद्र स्थापित किए।
- संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों का नेटवर्क विकसित किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2026 को मधुबनी, बिहार में एसआईपी एंड आरडी, असम को पुरस्कार प्रदान करते हुए

चुनौतियाँ

- भौगोलिक रूप से विस्तृत ग्रामीण क्षेत्रों एवं विविध हितधारकों में क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना।
- पीआरआई प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों हेतु गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बढ़ती मांग को पूरा करना।
- विकेंद्रीकृत योजना एवं विभागीय समन्वय को मजबूत करना।
- पंचायत शासन प्रणाली में सतत निगरानी, डेटा सत्यापन एवं पारदर्शिता बनाए रखना।

दृष्टिकोण

- विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों एवं डीपीआरसी के माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण नेटवर्क स्थापित किया।
- विभिन्न क्षेत्रों में पीआरआई प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं हितधारकों हेतु विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- प्रशिक्षण प्रगति, सहभागिता एवं परिणामों की निगरानी हेतु एमआईएस आधारित प्रणाली लागू की।
- समग्र पंचायत विकास हेतु विभागों, विशेषज्ञों एवं संगठनों के साथ समन्वित कार्य किया।

प्राप्त समर्थन

- पंचायती राज संस्थाओं एवं क्षमता निर्माण पहलों को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय से सहयोग प्राप्त हुआ।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार से प्रशासनिक एवं संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ।
- पहुंच विस्तार एवं प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार हेतु विशेषज्ञों, संस्थानों एवं मास्टर ट्रेनरों के साथ सहयोग मिला।

नवाचार

- विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों एवं डीपीआरसी के साथ राज्यव्यापी विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण नेटवर्क स्थापित किया।
- व्यावहारिक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु पीएमएवाई-जी मॉडल आवास विकसित किए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी एवं ट्रैकिंग हेतु एमआईएस आधारित प्रणाली का उपयोग।
- साक्ष्य आधारित शासन हेतु पंचायत विकास सूचकांक (PDI) प्रक्रियाओं का संचालन।
- सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) पर केंद्रित बड़े स्तर के विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

सततता के लिए रोडमैप

- असम में जिला पंचायत संसाधन केंद्रों का विस्तार कर प्रशिक्षण पहुंच को और मजबूत करना।
- डिजिटल शासन प्रणाली एवं एमआईएस आधारित निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना।
- एसडीजी एवं पंचायत विकास सूचकांक के अनुरूप विषयगत प्रशिक्षण मॉड्यूल का निरंतर विकास।
- पीपुल्स प्लान अभियान के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना एवं सहभागी शासन को बढ़ावा देना।
- पंचायतों हेतु फील्ड मार्गदर्शन एवं सह-अध्ययन अवसरों को बढ़ाना।

Panchayat Kshamta Nirmaan Sarvottam Sansthan Puraskar (PKNSSP)

STATE INSTITUTE OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT (SIP&RD)

STATE: ASSAM

3rd PRIZE

Profile

- Established in September 1987 and became an autonomous body in 1998 under the Societies Registration Act, 1860.
- Redesignated as SIP&RD in July 2016 following directions from the Ministry of Panchayati Raj.
- Functions as a centre of excellence for training, research, and rural governance reforms.
- Operates through two campuses in Guwahati, 12 Extension Training Centres, and 11 District Panchayat Resource Centres.
- Supported by 87 faculty members and a network of trained Master Trainers and Resource Persons.

KEY ACHIEVEMENTS

- Conducted 5,975 training programmes during 2023–24 for Elected Representatives and functionaries.
- Trained around 14,000 Elected Representatives and 25,000 line department functionaries during 2023–24.
- Established a dedicated Project Management Unit.
- Anchored the People's Plan Campaign for GPDP, BPDP, and DPDP preparation across the State.
- Conducted SDG-focused training across nine thematic sectors including gender, livelihoods, and drinking water.
- Developed six PMAY-G model houses as demonstration units for practical training.
- Implemented a Management Information System for training monitoring and reporting.
- Established Extension Training Centres and District Panchayat Resource Centres for decentralized outreach.
- Developed a trained network of Master Trainers through structured Training of Trainers programmes.

Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi conferring the award to the SIP&RD, Assam at Madhubani, Bihar on 24th April, 2026

CHALLENGES FACED

- Ensuring capacity building across geographically dispersed rural areas and diverse stakeholder groups.
- Meeting the increasing demand for quality training programmes for PRI representatives and officials.
- Strengthening decentralized planning and ensuring effective convergence among line departments.
- Maintaining continuous monitoring, data verification, and transparency in Panchayat governance systems.

APPROACH TAKEN

- Decentralized Training Network: Established Extension Training Centres and DPRCs for grassroots outreach and localized training delivery.
- Capacity Building Focus: Organized thematic training programmes for PRI representatives, officials, and stakeholders across multiple sectors.
- Digital Monitoring Systems: Implemented MIS-based systems for tracking training progress, participation, and outcomes.
- Collaborative Governance: Worked closely with line departments, experts, and organizations for holistic Panchayat development.

SUPPORT RECEIVED

- Support from the Ministry of Panchayati Raj, Government of India for strengthening Panchayati Raj Institutions and capacity-building initiatives.
- Administrative and institutional support from the Panchayat & Rural Development Department, Government of Assam.
- Collaboration with experts, institutions, and Master Trainers for expanding outreach and improving training quality.

INNOVATIONS

- Establishment of a statewide decentralized training network with Extension Training Centres and DPRCs.
- Development of PMAY-G Model Houses for practical field demonstration and hands-on learning.
- Use of MIS-based systems for monitoring and tracking training programmes.
- Anchoring Panchayat Development Index (PDI) processes for evidence-based governance.
- Large-scale thematic training programmes focusing on Localization of Sustainable Development Goals (LSDGs).

ROADMAP FOR SUSTAINABILITY

- Expansion of District Panchayat Resource Centres (DPRCs) across Assam for enhanced training outreach.
- Strengthening digital governance systems and MIS-based monitoring mechanisms.
- Continuous development of thematic training modules aligned with SDGs and Panchayat Development Index.
- Promoting decentralized planning and participatory governance through sustained People's Plan Campaign initiatives.
- Enhancing field mentoring and cross-learning opportunities for Panchayats.

सशक्त पंचायत सतत् विकास

नानाजी देशमुख

सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार की सभी 9 पुरस्कार थीमों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों/समकक्ष निकायों के समग्र प्रदर्शन तथा ब्लॉक एवं जिला पंचायतों के उनके ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के समेकित मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित पंचायतें एनडीएसपीएसवीपी 2025 के अंतर्गत विजेता के रूप में उभरी हैं। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनके समग्र एवं अभिसरण आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

क्रम संख्या	रैंक	पुरस्कार थीम/श्रेणी	पुरस्कार प्राप्त पंचायत का नाम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1	1	सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत	सेपाहिजला	त्रिपुरा
2	2	सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत	गंजम	ओडिशा
3	3	सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
4	1	सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत	हरीपड़ (जिला अलप्पुझा)	केरल
5	3	सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत	कुप्पम (जिला चित्तूर)	आंध्र प्रदेश
6	1	सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत	न्यू नापम (ब्लॉक गाभोरू, जिला सोनितपुर)	असम
7	2	सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत	टेलकप (ब्लॉक रोहतास, जिला रोहतास)	बिहार
8	3	सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत	बिराहारु (ब्लॉक सैयां, जिला आगरा)	उत्तर प्रदेश

सशक्त पंचायत सतत् विकास

NANAJI DESHMUKH SARVOTTAM PANCHAYAT SATAT VIKAS PURASKAR (NDSPSVP)

For overall performance of Gram Panchayats/Equivalent bodies and aggregate performance of Block and District Panchayats based on their GPs performance under all 9 award themes of DDUPSVP, following Panchayats have emerged as winners under NDSPSVP 2025. This award reflects their holistic and convergent approach for achieving Sustainable Development Goals.

Sl. No.	Rank	Award Theme/Category	Name of Awardee Panchayat	State/UT
1	1	Best District Panchayat	Sepahijala	Tripura
2	2	Best District Panchayat	Ganjam	Odisha
3	3	Best District Panchayat	Coimbatore	Tamil Nadu
4	1	Best Block Panchayat	Harippad (District Alappuzha)	Kerala
5	3	Best Block Panchayat	Kuppam (District Chittoor)	Andhra Pradesh
6	1	Best Gram Panchayat	New Napam (Block Gabhoru, District Sonitpur)	Assam
7	2	Best Gram Panchayat	Telcup (Block Rohtas, District Rohtas)	Bihar
8	3	Best Gram Panchayat	Biraharu (Block Saiyan, District Agra)	Uttar Pradesh

सशक्त पंचायत सतत् विकास

https://panchayataward.gov.in/

www.facebook.com/MinistryOfPanchayatiRaj

www.youtube.com/channel/UCEVBqQXipAuDqZsinwto4nA

www.twitter.com/mopr_goi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Panchayati Raj
Government of India